

08



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 757]

नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 31, 2004/भाद्र 9, 1926

[No. 757]

NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 31, 2004/BHADRA 9, 1926

वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय

(वाणिज्य विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 31 अगस्त, 2004

सं० 1/2004—2009

का०आ० 973(अ).—विदेश व्यापार नीति, 2004-2009 के पैराग्राफ 1.2 के साथ पठित विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम, 1992 (1992 का 22) की धारा 5 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार इस अधिसूचना के अनुलग्नक में यथा शामिल विदेश व्यापार नीति 2004—2009 को एतद्वारा अधिसूचित करती है। यह नीति 1 सितम्बर, 2004 से प्रभावी होगी।

इसे लोकहित में जारी किया जाता है।

[फा० सं० 01/94/180/विदेश व्यापार नीति/एएम 05/पीसी-4]

गोपाल के० पिल्लै, महानिदेशक, विदेश व्यापार
एवं पदेन अपर सचिव

विदेश व्यापार नीति

प्रस्तावना

सन्दर्भ

विश्व व्यापार में भारत द्वारा महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए देश के विदेश व्यापार के समग्र विकास हेतु विस्तृत दृष्टिकोण अपनाने की जरूरत है। यद्यपि निर्यात में वृद्धि का विशेष महत्व है, फिर भी हमारी अर्थव्यवस्था को उद्वेलित करने के लिए हमें जरूरी आयातों को सुविधाएँ प्रदान करनी होंगी। विकास के लिए इन नीतियों के योगदान की अधिकतम करने हेतु व्यापार और अन्य आर्थिक नीतियों के बीच सामंजस्य और सुसंगति महत्वपूर्ण है। इस प्रकार, वार्षिक निर्यात-आयात नीति घोषित करने की मौजूदा परम्परा को जारी रखते हुए इससे कहीं आगे जाकर भारत की विदेश नीति की विकासात्मक अवश्यकताओं का समेकित दृष्टिकोण अपनाना आवश्यक है। नयी विदेश व्यापार नीति इसी सन्दर्भ में जारी की जा रही है।

उद्देश्य

व्यापार अपने आप में अन्तिम उद्देश्य नहीं है बल्कि यह आर्थिक विकास और राष्ट्रीय विकास का माध्यम है। प्रमुख उद्देश्य केवल विदेशी मुद्रा का अर्जन नहीं बल्कि संबंधित आर्थिक कार्यकलापों को उद्वेलित करना है। विदेश व्यापार नीति इस विचारधारा से प्रेरित है और दो प्रमुख उद्देश्यों से प्रभावित है, जोकि इस प्रकार हैं:-

1. अन्तरराष्ट्रीय व्यापार में हमारी भागीदारी की प्रतिशतता को आगामी पांच वर्षों के भीतर दो गुनी करना: तथा
2. रोजगार सृजन को बढ़ावा देते हुए आर्थिक विकास के प्रभावी उपकरण के तौर पर कार्य करना।

रणनीति

अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित रणनीतियों को अपनाते हुए इन उद्देश्यों को प्राप्त करना प्रस्तावित है:

1. हमारे व्यवसायकर्त्ताओं, उद्योगपतियों और व्यापारियों की स्वाभाविक उद्यमियता को बढ़ावा देने के लिए विश्वास और पारदर्शिता का माहौल बनाने हेतु नियंत्रणों को हटाना।

2. प्रक्रियाओं को सरल बनाना और सौदे की लागत को कम करना ।
3. इस मूल सिद्धान्त के आधार पर कि शुल्कों और प्रशुल्कों का निर्यात नहीं किया जाना चाहिए, अतः निर्यात उत्पादों में इस्तेमाल की गई निविष्टियों पर सभी प्रशुल्कों और शुल्कों को निष्प्रभावी बनाना ।
4. विनिर्माण, व्यापार और सेवाओं के क्षेत्र में भारत को एक विश्व ताकत के रूप में विकसित करना ।
5. उन क्षेत्रों का पता लगाना तथा इन्हें विकसित करना जिनपर विशेष बल दिया जाना है, जिससे अतिरिक्त रोजगार के अवसर पैदा होंगे, विशेषकर अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में, और प्रत्येक क्षेत्र के लिए प्रेरक स्त्रोतों को विकसित करना ।
6. भारतीय अर्थव्यवस्था के सभी क्षेत्रों के प्रौद्योगिकीय और बुनियादी सुविधाओं का विकास करना, विशेष रूप से पूंजीगत वस्तुओं और उपकरणों का आयात करके, इस प्रकार गुणवत्ता के स्वीकृत मानदण्डों को अन्तरराष्ट्रीय रूप से प्राप्त करते हुए मूल्य संवर्धन और उत्पादकता में वृद्धि करना ।
7. शुल्क वापसी के ढांचे की प्रणाली से बचना और यह सुनिश्चित करना कि हमारे घरेलू क्षेत्र निर्यात में वृद्धि करने के उद्देश्य से किए गए मुक्त व्यापार समझौतों/क्षेत्रीय व्यापार समझौतों/प्राथमिक व्यापार समझौतों का उल्लंघन नहीं हुआ है ।
8. अन्तरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सम्पूर्ण विदेशी व्यापार श्रृंखला से संबंधित वास्तविक और आभासी दोनों के बुनियादी नेटवर्क को विकसित करना ।
9. व्यापार बोर्ड की भूमिका को पुनः परिभाषित करके इसे पुनः जीवित करना, इसे उचित मान्यता देना तथा व्यापार नीति में विशेषज्ञों को शामिल करना ।
10. हमारी निर्यात रणनीति में हमारे दूतावासों को मुख्य भूमिका निभाने के लिए गतिशील बनाना और विदेश में हमारे वाणिज्यिक विभाग को इलैक्ट्रानिक प्लेटफार्म से जोड़ना ताकि वास्तविक रूप से व्यापार आसूचना और पूछताछ के दायरे को बढ़ाया जा सके ।

भागीदारी

नई नीति में कथित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए व्यवसायिक/व्यापारिक निर्यातक और विनिर्माता निर्यातक, व्यापार और उद्योग जगत सरकार के भागीदार हैं। लम्बे समय तक चलने वाली और अनावश्यक मुकदमेबाजी भागीदारी को बिगाड़ती है। मुकदमेबाजी की जरूरत को दूर करने के लिए सृजनात्मक और सौहार्दपूर्ण वातावरण तैयार करने हेतु उपयुक्त शिकायत निवारण प्रणाली स्थापित की जाएगी, ऐसी उम्मीद की जाती है, जो मुकदमेबाजी को काफी कम करेगी और भागीदारी के रिश्ते को मजबूत बनाएगी।

उदार व्यापार प्रणाली का गति विज्ञान कई बार डम्पिंग के परिणामस्वरूप घरेलू उद्योग को नुकसान पहुँचाता है। जब ऐसा घटित होता है तो इस नुकसान को दूर करने के लिए प्रभावी कदम उठाए जाएंगे।

प्रारूप (रोड मैप)

यह नीति भारत के विदेश व्यापार के विकास हेतु अनिवार्य प्रारूप है। हमें जिस दिशा में अग्रसर होना है उसके आधार भूत सिद्धांत और मुद्दे इसमें शामिल हैं। कोई व्यापार नीति केवल अपने गति-विज्ञान की वजह से ही अपने सभी ब्यौरों के बावजूद पूर्णतः व्यापक नहीं हो सकती है। इसके लिए समय समय पर संशोधन करना स्वाभाविक तौर पर आवश्यक होगा। हम अन्तरराष्ट्रीय व्यापार के अवश्यंभावी परिवर्तनशील गति-विज्ञान पर आधारित निरन्तर अद्यतन करने के माध्यम से ऐसा करने का प्रस्ताव करते हैं। व्यापार और उद्योग जगत के साथ भागीदारी के माध्यम से हम इस प्रारूप (रोड मैप) पर कीर्तिमान स्थापित करने का प्रस्ताव करते हैं।

कमल नाथ
वाणिज्य और उद्योग मंत्री
भारत-सरकार

नई दिल्ली

31 अगस्त, 2004

अध्याय - एक (क)

विधिक ढाँचा

- | | | |
|-------------------------|-----|---|
| प्रस्तावना | 1.1 | प्रस्तावना में वृहत को इंगित किया गया है तथा यह विदेश व्यापार नीति का अभिन्न अंग है । |
| अवधि | 1.2 | विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 (1992 की संख्या 22) की धारा 5 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केन्द्र सरकार 2004-2009 यथासंशोधित की अवधि के लिए निर्यात एवं आयात नीति को अधिसूचित करती है । यह नीति 1 सितम्बर, 2004 से लागू होगी तथा 31 मार्च, 2009 तक प्रभावी रहेगी, जब तक अन्यथा उल्लेख न किया जाए । |
| संशोधन | 1.3 | तथापि केन्द्रीय सरकार, अधिनियम की धारा-5 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जनहित में इस नीति में कोई संशोधन कर सकती है। ऐसे संशोधन भारत के राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना के माध्यम से किए जाएंगे। |
| अन्तर्वर्ती
व्यवस्था | 1.4 | पूर्व निर्यात/आयात नीतियों के अंतर्गत जारी की गई कोई भी व्यवस्था अधिसूचना या सार्वजनिक सूचना या अन्य व्यवस्था जो इस नीति के प्रारम्भ होने से पूर्व लागू थी, वह जब तक इस नीति के प्रावधानों में असंगत न हों, लागू रहेगी तथा उन्हें इस नीति के तहत जारी किया माना जाएगा ।
इस नीति से पूर्व जारी किए गए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमत पत्र उनमें अनुमत मदों के आयात/निर्यात के लिए मान्य रहेंगे जब तक अन्यथा अधिसूचित न किया गया हो। |
| | 1.5 | यदि इस नीति के तहत मुक्त रूप से किए जा सकने वाले किसी निर्यात या आयात पर बाद में कोई प्रतिबंध लगाया जाता है या उसे विनियमित किया जाता है तो ऐसे प्रतिबंध या विनियमन के बावजूद सामान्यतः ऐसे निर्यात या आयात की अनुमति प्रदान की जाएगी, जब तक कि अन्यथा निर्धारित न किया गया हो, बशर्ते कि ऐसे प्रतिबंध से पूर्व स्थापित अपरिवर्तनीय साख-पत्र के प्रति ऐसे निर्यात या आयात का पोत लदान ऐसे प्रतिबंध से लागू होने की मूल वैधता अवधि के भीतर हो जाए। |

अध्याय - एक (ख)विशेष ध्यान देने योग्य पहल

विशेष ध्यान देने योग्य पहल

1ख.1

विश्व व्यापार में 5 वर्ष के अन्दर अपनी भागीदारी का प्रतिशत दुगना करने तथा विशेष रूप से अर्द्ध शहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि, हथकरघा, हस्तशिल्प, रत्न और आभूषण तथा चमड़े से बने सामान रोजगार का अवसर बढ़ाने कुछ विशेष ध्यान देने योग्य पहल पहचान लिए गए हैं।

भारत सरकार इन क्षेत्रों में निर्यात को बढ़ाने के लिए संगठित प्रयास करेगी जिनके लिए विशेष रणनीति तय करेगी जिसको समय समय में अधिसूचित किया जाएगा।

इन दवाव क्षेत्रों को निम्नलिखित सुविधाएं दी जाएंगी :-

(1) कृषि

(क) फलों, सब्जियों, फूलों, कुछ बन उत्पादों तथा उनके मूल्य वृद्धि उत्पादों के लिए विशेष कृषि उपज योजना जिसका नाम सनराईज कृषि योजना बनायी गयी है। (पैरा 3.8)

(ख) कृषि निर्यात क्षेत्र (ए.ई.जैड) के लिए एस आई डी ई के अन्तर्गत नीति निर्धारित की गयी है।

(ग) ई पी सी जी नीति के अन्तर्गत पूँजीगत माल के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति होगी।

(घ) ई पी सी जी नीति के अन्तर्गत ए ई जैड यूनिटों को बैंक गारंटी से छूट होगी।

(ङ) ई पी सी जी के अन्तर्गत आयातित माल ए ई जैड में किसी भी स्थान में लगाने की अनुमति होगी।

(च) प्रतिबंधित मदों जैसे कि पैन्ल, के आयात की विभिन्न निर्यात संवर्धन योजनाओं के तहत अनुमति होगी।

(छ) कृषि निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस के तहत कीटनाशक जैसे इनपुट के आयातों की अनुमति होगी।

(ज) रु0 250 करोड़ के न्यूनतम सीमा के साथ निर्यात वृद्धि के नये कीर्तिमानों को अधिसूचित किया जाएगा ।

(ii) हथकरघा

(क) हथकरघा निर्यात को बढ़ाने के लिए एम.ए.आई./एम डी ए योजना के तहत विशिष्ट विधि निर्धारित की जाएगी ।

(ख) विशिष्ट कटाई छंटाई के शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यातों पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत होगी ।

(ग) हाथ से बनाई हुई चटार्ड के नमूनों पर शुल्क मुक्त आयात की हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 1 प्रतिशत होगा।

(घ) हाथ से बनाई हुई चटार्ड के पुराने टुकड़ों की खेप का शुल्क मुक्त आयात का पुनः निर्यात मरम्मत के बाद अनुमत होगा।

(ङ.) निर्यात वृद्धि की न्यूनतम सीमा 250 करोड़ रुपये वाले नये कस्बों को अधिसूचित किया जायेगा ।

(III) हस्तशिल्प

(क) नये हस्तशिल्प विशेष आर्थिक परिक्षेत्र स्थगित किए जायेंगे जो निर्यात के लिए तैयार किए गए और कॉटेज क्षेत्र से खरीदे गए उत्पाद होंगे।

(ख) कटाई और छंटाई की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 5 प्रतिशत होगी। हकदारी को अन्य के किसी भी अनुमति दी गई है, ये सुविधा सहायक विनिर्माताओं के साथ जुड़े व्यापारी निर्यातकों को भी दी जायेगी।

(ग) हस्तशिल्प निर्यात संवर्धन परिषद उन निर्यातकों की तरफ से जो परेक्ष रूप से निर्यात करने में सुदृढ़ नहीं हैं के कटे हुए छटे हुए और उपभोज्यों को आयात करने के लिए प्राधिकृत होगी।

- (घ) प्रोत्साहित हस्तशिल्प के लिए एमएआई/एमडीए योजना के अधीन विशेष कोष निर्धारित किए जायेंगे।
- (ङ) शुल्क मुक्त आयात पर ट्रिनिंग इम्बेलिशमेन्ट और उपभोज्यों पर सीवीडी की छूट होगी।
- (च) निर्यात वृद्धि के नवीन करबों की न्यूनतम सीमा को 250 करोड़ तक घटा दिया गया है।

(iv) रत्न
और आभूषण:

- (क) 18 कैरेट और अधिक के सोने का आयात प्रतिभूति योजना के अधीन अनुमेय होगा।
- (ख) सोना प्लेटिनम के अलावा धातुओं के लिए उपभोज्यों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान किए गए निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 2 प्रतिशत तक होगी।
- (ग) व्यापारिक नमूनों की शुल्क मुक्त निर्यात हकदारी 100,000 रुपये होगी।
- (घ) नकार दिए आभूषणों के लिए शुल्क मुक्त पुनः आयात हकदारी निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 2 प्रतिशत होगी।
- (ङ.) कटे एवं पोलिश किए हुए रत्न और आभूषणों को आयकर अधिनियम के खण्ड-10 के अधिन छूट के उद्देश्य के लिए तैयार माल की तरह माना जायेगा।

(v) चमड़ा और
जूते

- (क) विनिर्दिष्ट मर्दों की शुल्क मुक्त आयात हकदारी चालू वित्तीय वर्ष के दौरान निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 5 प्रतिशत होगी।
- (ख) जूतों (चमड़ा और सिंथेटिक दोनों) दस्ताने, यात्रा बैग और हैंड बैग के लिए ट्रिनिंग्स, इम्बेलिशमेन्ट और जूते उपांगो

के आयात के लिए शुल्क मुक्त हकदारी पिछले वित्तीय वर्ष के निर्यात के जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की 3 प्रतिशत होगी। हकदारी डिब्बा बंद सामग्री, जैसे छपे हुए और बिना छपे हुए जूतों के डिब्बे लकड़ी के छोटे कार्टून, पैकिंग जूतों के लिए टिन या प्लास्टिक सामग्री पर भी लागू होगी।

- (ग) प्रदूषण नियंत्रण संयंत्रों को सीमा शुल्क से छूट होगी।
- (घ) अनुप्रयुक्त आयातित सामग्री जैसे की खालें एवं चमड़ा और नम-नीला चमड़ा का पुनर्निर्यात अनुमेय है।
- (ङ.) लीनिंग और इन्टरवीनिंग सामग्री सीमा शुल्क अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 01-03-2003 की क्रम सं. 168 पर अधिसूचित सीवीडी की छूट होगी।
- (च) आई टी सी (एचएस) के अध्याय 43 के अधीन आने वाले कच्चा, टैन्ड और ड्रेस रोम और चमड़े पर सीवीडी की छूट होगी।

प्रगति मैदान के लिए इष्टतम विकास कार्यक्रम

1ख.2

हमारी औद्योगिक और व्यापारिक उपलब्धियों का अधिकतम लाभ उठाने और मौजूदा सुविधाओं में वृद्धि करने के उद्देश्य से जगह और सेवाओं में वृद्धि के लिए प्रगति मैदान को एक विश्वस्तर का काम्पलेक्स बनाया जाएगा जो आगन्तुकों के अंतःप्रवेश और बहिर्गमन के अनुकूल होगा। काम्पलेक्स की उपलब्ध सुविधाओं में सुधार किया जाएगा, इन्हें बढ़ाया जाएगा और इन्हें वैविध्य प्रदान किया जाएगा। वहाँ एक अत्यंत आधुनिक, “स्टेट आफ द आर्टे” पर्यावरण नियंत्रित, वातानुकूलित प्रदर्शनी क्षेत्र और स्थाई प्रदर्शनी माटर्स होंगे। इसके अलावा, दस हजार शिष्टमंडलों के लिए एक बड़ा सम्मेलन केन्द्र विकसित किया जाएगा जिसमें बहुउद्देशीय और परिवर्तनीय हाल, जिनमें उच्च तकनीकी उपकरण लगे होंगे। पूरे वर्ष चलने वाले खाद्य एवं पेय रेस्त्रां को विकसित किया जाएगा जिसमें विभिन्न किस्म और सस्ते-मंहगे सभी प्रकार के पकवान के बेचने के लिए बहुत सी दुकाने होंगी। प्रगति मैदान के अहाते में नौ हजार से अधिक वाहनों को पार्क करने के लिए एक बहुस्तरीय पार्किंग स्थल होगा।

अध्याय - एक (ग)

व्यापार बोर्ड

- | | | |
|----------------------|-------|--|
| व्यापार उद्योग बोर्ड | 1.ग.1 | विदेश व्यापार नीति से संबंधित मामलों में सरकार के सलाह देने के लिए व्यापार बोर्ड का पुनर्गठन किया जाएगा तथा इसे स्पष्ट और सक्रिय भूमिका दी जाएगी वांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने व भारत का निर्यात बढ़ाने के लिए व्यापार बोर्ड तथा सरकार के बीच लगातार पारस्परिक क्रिया होगी । |
| विचारणीय विषय | 1.ग.2 | <p>व्यापार बोर्ड के निम्नलिखित विचारणीय विषय होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) बदलते हुए राष्ट्रीय व अन्तर्राष्ट्रीय आर्थिक परिदृश्य में निर्यात को बढ़ाने के लिए अल्पकालीन व दीर्घकालीन योजना बनाने तथा इसे क्रियान्वित करने में सरकार को सलाह देना 2) विभिन्न क्षेत्रों में निर्यात निष्पादन की समीक्षा, नियंत्रण की पहचान तथा निर्यात अग्रिम को सर्वोत्तम करने के लिए औद्योगिक सुस्पष्ट उपाय सुझाना । 3) आयात व निर्यात के वर्तमान संस्थागत फ्रेमवर्क की जाँच करना तथा बांछित लक्ष्यों को प्राप्त करने के सरल और कारगर व्यवहारिक उपाय सुझाना 4) आयात निर्यात के नीति दस्तावेजों तथा प्रक्रियाओं को जाँच करना तथा ऐसी योजनाओं में एकरूपता तथा चैनलाईज के लिए उपाय सुझाना 5) भारत के विदेश व्यापार के संवर्धन से संबंधित मामलों की जाँच करना तथा देश के सामान व सेवाओं के अन्तर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा में मजबूत करना । 6) उपर्युक्त लक्ष्यों को बढ़ाने के लिए अध्ययन करना । |

संयोजन	1.ग.3	सरकार व्यापार नीति में विशेषज्ञ अथवा प्रसिद्ध व्यक्ति को व्यापार बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त करेगी । सरकार अन्य 25 व्यक्तियों को भी नामित करेगी जिनमें 10 व्यक्ति व्यापार नीति में विशेषज्ञता प्राप्त होंगे । इसके अलावा मान्यता प्राप्त निर्यात संवर्धन परिषद का चेयरमैन तथा पदेन सदस्यों को राष्ट्रीय चैम्बर्स ऑफ कामर्स का अध्यक्ष अथवा महासचिव नियुक्त करेगी ।
बैठकें	1.ग.4	बोर्ड की बैठक प्रत्येक तिमाही में एक बार आयोजित की जाएगी तथा रखे गए मुद्दों की मदों के सन्दर्भ में सरकार को सिफरिश को भेजेगा ।
उप समिति	1.ग.5	व्यापार बोर्ड को सह-समितियों बनाने का अधिकार होगा और विशेष क्षेत्रों तथा उद्देश्यों पर सिफारिशों को बनाने के लिए विशेषज्ञों को कार्यरत करने का अधिकार होगा।
सचिवालय और बजट	1.ग.6	व्यापार बोर्ड का एक सचिवालय और बजट शीर्ष होगा । तथा इसकी सेवाएँ वाणिज्य विभाग के अन्तर्गत आएंगे ।

अध्याय - दो

निर्यात एवं आयात से संबंधित सामान्य प्रावधान

- | | | |
|--|-----|---|
| आयात और निर्यात मुक्त जब तक कि विनियमित न हो | 2.1 | इस नीति के प्रावधानों अथवा तत्समय लागू अन्य कानूनों द्वारा जिस सीमा तक विनियमित होते हैं, को छोड़कर निर्यात एवं आयात मुक्त होगा। मदवार निर्यात और आयात नीति, समय-समय पर यथा संशोधित विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा प्रकाशित और अधिसूचित “आई टी सी(एच एस)” में विनिर्दिष्ट के अनुसार होगी। |
| कानून का अनुपालन | 2.2 | प्रत्येक निर्यातक या आयातक को, विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992 के प्रावधानों, इसके अन्तर्गत बनाए गए नियमों और आदेशों, इस नीति के प्रावधानों तथा उसको दिए गए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति या प्रमाणपत्र या उसे प्रदान अनुमति की शर्तों और उस समय लागू किसी अन्य कानून के प्रावधानों का अनुपालन करना होगा। सभी आयातित माल भी देशी उत्पादित माल पर यथा लागू स्वदेशी कानूनों, नियमों, विनियमों, तकनीकी विनिर्देशनों, पर्यावरण और सुरक्षा मानदण्डों के अधीन होंगे। रत्न और आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद द्वारा विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत आवश्यक किम्बरलै प्रोसेस प्रमाण-पत्र जब तक पोतलदान पार्सल के साथ संलग्न न हो, अनगढ़े हीरों का आयात अथवा निर्यात अनुमत नहीं होगा। |
| नीति की व्याख्या | 2.3 | आई टी सी(एच एस) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1), अथवा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) अथवा डी ई पी बी दर की अनुसूची में किसी मद के वर्गीकरण, के संबंध में या इस नीति में दिए गए किसी भी प्रावधान के स्पष्टीकरण के बारे में यदि किसी भी प्रकार का प्रश्न अथवा शंका उत्पन्न होती है तो ऐसे प्रश्न अथवा शंका को महानिदेशक, विदेश व्यापार को भेजा जाएगा तथा उनका निर्णय अंतिम व बाध्यकारी होगा। |

किसी लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/अनुमति के नीति अनुसार जारी होने के विषय में कोई शंका या प्रश्न उठने पर अथवा ऐसे दस्तावेजों की आवश्यकता और अंश पर किसी प्रश्न अथवा शंका के उठने पर उन दस्तावेजों को विदेश व्यापार महानिदेशालय के पास भेजा जाएगा जिनका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होगा।

- प्रक्रिया 2.4 महानिदेशक, विदेश व्यापार किसी एक मामले में अथवा मामलों की श्रेणी में किसी भी आयातक अथवा निर्यातक या अन्य लाइसेंसिंग अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी इस अधिनियम के प्रावधानों, इसके अधीन बने आदेशों तथा इस नीति को लागू करने के उद्देश्य से कोई विशेष प्रक्रिया निर्धारित कर सकता है। ऐसी प्रक्रिया, प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1), प्रक्रिया पुस्तक (भाग-2), डी ई पी बी दर की अनुसूची और आई.टी.सी. (एच एस) में सम्मिलित होगी तथा सार्वजनिक सूचना के माध्यम से प्रकाशित होगी। ऐसी प्रक्रियाओं को, इसी प्रकार, समय-समय पर संशोधित किया जाएगा। प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) विदेश व्यापार नीति की अनुपूरक है तथा इससे सम्बद्ध प्रक्रियाओं और अन्य ब्यौरों का उल्लेख है। नीति की विभिन्न स्कीमों के तहत उपलब्ध लाभों को प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।
- नीति/प्रक्रिया से छूट 2.5 इस नीति अथवा किसी प्रक्रिया के प्रावधानों में ढील प्राप्त करने के लिए इस आधार पर किया गया अनुरोध कि आवेदक को वास्तव में कठिनाई है अथवा नीति या प्रक्रिया को कड़ाई से लागू करने पर व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो तो उसे आवश्यक छूट के लिए महानिदेशक, विदेश व्यापार के पास भेजा जा सकता है। उस पर महानिदेशक ऐसा आदेश या ऐसी छूट या राहत जैसा भी उचित या समुचित हो, दे सकते हैं।

महानिदेशक, विदेश व्यापार लोकहित में किसी भी व्यक्ति या वर्ग या व्यक्तियों की श्रेणी को इस नीति के किसी प्रावधान से या किसी प्रक्रिया से छूट दे सकते हैं या ऐसी छूट देते समय वह ऐसी शर्त लगा सकते हैं जैसाकि वह उचित समझे। यदि वह अनुरोध नीति/प्रक्रिया के अध्याय-4 (रत्न और आभूषण क्षेत्र से संबंधित किसी प्रावधान को छोड़कर) के प्रावधानों के बारे में हो तो ऐसे अनुरोधों पर केवल अग्रिम लाइसेंसिंग समिति से सलाह लेकर ही विचार किया जाए। तथापि अध्याय-4 और रत्न और आभूषण क्षेत्र से भिन्न प्रावधानों के संबंधों में ऐसे किसी अनुरोध पर केवल नीति छूट समिति की सलाह लेने के बाद विचार किया जाएगा।

प्रतिबंध के सिद्धान्त	2.6	<p>विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचना के माध्यम से निम्नलिखित हेतु कोई भी आवश्यक उपाय अपनाया और लागू किया जा सकता है।</p> <ol style="list-style-type: none"> (1) सार्वजनिक आचरण का संरक्षण (2) मानव, जानवर अथवा पादप जीवन अथवा स्वास्थ्य का संरक्षण (3) पेटेंट, ट्रेडमार्क और कापीराइट का संरक्षण और भ्रामक कृत्यों की रोकथाम। (4) कारागार श्रमिकों के प्रयोग की रोकथाम (5) कला, इतिहास अथवा पुरातत्व मूल्य की राष्ट्रीय धरोहर का संरक्षण। (6) सम्पूर्ण प्राकृतिक स्रोतों का संरक्षण। (7) विखंडनीय सामग्री अथवा जिससे वह प्राप्त की गई है, के व्यापार का संरक्षण, और (8) हथियारों, गोला-बारुद और युद्ध के साज-सामान के व्यापार की रोकथाम
प्रतिबंधित माल	2.7	कोई भी माल जिसका आई टी सी (एच एस) के अधीन निर्यात अथवा आयात प्रतिबंधित किया गया है, उसका इस संबंध में जारी किए गए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति या सार्वजनिक सूचना के अनुसार ही निर्यात अथवा आयात किया जा सकेगा।
लाइसेंस/प्रमाण पत्र/ अनुमति की शर्तें	2.8	<p>प्रत्येक लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति विनिर्दिष्ट वैधता अवधि के लिए वैध होगा तथा लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति में दी गई शर्तें, लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यथा विनिर्दिष्ट होगी तथा इसमें निम्नलिखित सम्मिलित होंगे :-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. माल की मात्रा, विवरण एवं मूल्य, 2. वास्तविक प्रयोक्ता शर्त, 3. निर्यात दायित्व, 4. प्राप्त किया जाने वाला मूल्य वर्धन, 5. न्यूनतम निर्यात मूल्य
लाइसेंस/प्रमाणपत्र/ अनुमति अधिकार नहीं	2.9	कोई भी व्यक्ति लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति को अधिकार से नहीं ले सकता है तथा महानिदेशक, विदेश व्यापार या लाइसेंसिंग प्राधिकारी को, अधिनियम के प्रावधानों और उसके अंतर्गत बने नियमों के अनुसार लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति पत्र देने से इनकार करने या नवीकरण नहीं करने का अधिकार होगा।

- जुर्माना 2.10 यदि लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति धारक लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति की किसी शर्त का उल्लंघन करता है या निर्यात दायित्व को पूरा नहीं कर पाता है, तो उसे इस नीति के तहत बनाए गए अधिनियम, नियमों और आदेशों तथा उस समय लागू किसी अन्य नियम के अनुसार दंडित किया जा सकता है।
- राज्य व्यापार 2.11 कोई माल, जिसके आयात अथवा निर्यात के लिए राज्य व्यापार उद्यमों को विशेषाधिकार दिया गया हो अथवा जिनके माध्यम से विशेष रूप से विनियमित किया गया हो, राज्य व्यापार उद्यम द्वारा आई टी सी(एच एस) नामक पुस्तक में यथा- विनिर्दिष्ट अनुसार उस माल का आयात या निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि वह विनिर्दिष्ट शर्तों के अधीन हो। तथापि विदेश व्यापार महानिदेशक, इनमें से किसी माल के आयात या निर्यात के लिए किसी अन्य व्यक्ति को लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/अनुमति दे सकता है।
ऐसे माल के सम्बन्ध में, जिसके लिए राज्य व्यापार उद्यमों को विशेषाधिकार मंजूर किया गया हो, अथवा विशेष रूप से विनियमित किया गया हो, राज्य व्यापार उद्यम वाणिज्यिक दृष्टिकोण के अनुसार जिसमें कीमत, गुणवत्ता, उपलब्धता, विपणनता, परिवहन तथा क्रय-विक्रय की अन्य शर्तें शामिल हैं, ऐसी कोई अन्य खरीद या विक्रय कर सकता है। ये उद्यम किसी भेदभाव के बिना कार्य करेंगे और ऐसी खरीद और विक्रय में भाग लेने हेतु सक्षम होने के लिए प्रचलित व्यापार प्रथा के अनुसार प्राप्त सुविधाओं वाले देशों के उद्यमों के साथ ताल-मेल बिठाएंगे।
- आयातक-निर्यातक कोड नम्बर 2.12 जब तक विशेष छूट नहीं दी जाती किसी भी व्यक्ति द्वारा आयातक-निर्यातक कोड नम्बर (आई ई सी) के बिना किसी माल का निर्यात या आयात नहीं किया जायेगा। आयातक-निर्यातक कोड नम्बर, प्रक्रिया पुस्तक (भाग-1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा आवेदन के आधार पर मंजूर किया जायेगा।
- पड़ोसी देशों के साथ व्यापार 2.13 महानिदेशक विदेश व्यापार समय-समय पर आवश्यकता पड़ने पर ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा ऐसी योजनाएं बना सकते हैं जो पड़ोसी देशों के साथ व्यापार को बढ़ावा देने और आर्थिक संबंध मजबूत करने के लिए अपेक्षित हों।
- माल लाने-ले-जाने की सुविधा 2.14 भारत के पड़ोसी देशों को माल भेजने या वहां से लाने की सुविधा भारत और इन देशों के बीच हुई द्विपक्षीय संधियों के अनुसार विनियमित होगी तथा अन्तर्राष्ट्रीय अभिसमयों के अनुसार विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट प्रतिबंधों के अधीन होगी।

ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रुस के साथ व्यापार	2.15	ऋण की पुनः अदायगी करार के तहत रुस के साथ व्यापार के मामले में, महानिदेशक, विदेश व्यापार समय-समय पर आवश्यकता अनुसार ऐसे अनुदेश जारी कर सकते हैं अथवा स्कीमें बना सकते हैं जो अपेक्षित हों तथा इस नीति में दिया गया कुछ भी जो इन अनुदेशों अथवा स्कीमों के अनुरूप नहीं है, लागू नहीं होगा।
वास्तविक प्रयोक्ता शर्त	2.16	पूँजीगत माल, कच्चा माल, मध्यस्थ, संघटक, उपभोज्य पदार्थ, अतिरिक्त पुर्जे, हिस्से पुर्जे उपसाधित्र यंत्र और अन्य सामान जिनके आयात पर प्रतिबंध नहीं है उनका आयात किसी भी व्यक्ति द्वारा किया जा सकता है। तथापि, यदि इनके आयात के लिए लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र की जरूरत हों, तो केवल वास्तविक प्रयोक्ता ही ऐसे माल का आयात कर सकता है बशर्ते कि लाइसेंसिंग प्राधिकारी द्वारा यह शर्त समाप्त न कर दी गई हो।
पुरानी वस्तुएं	2.17	सभी पुरानी वस्तुएं आयात हेतु प्रतिबंधित होंगी तथा उन्हें इस नीति के प्रावधानों, आई टी सी(एच एस) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) सार्वजनिक सूचना या इस संबंध में जारी लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र के अनुसार उनका आयात किया जा सकता है। पुरानी वस्तुओं का आयात जिसमें रिफरबिशड/रिकंडीशंड स्पेयर्स भी शामिल है के मुक्त रूप से आयात की अनुमति है।
नमूनों का आयात	2.18	नमूनों का आयात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित प्रावधानों के अन्तर्गत किया जाएगा।
उपहारों का आयात	2.19	इस नीति के अधीन जहां ऐसा माल अन्यथा मुक्त रूप से आयात किया जा सकता हो, उपहारों के आयात की अनुमति होगी। अन्य मामलों में सीमाशुल्क निकासी(सी सी पी) की अनुमति महानिदेशक विदेश व्यापार से प्राप्त करनी होगी।
यात्री का असबाब	2.20	वस्तुतः घरेलू वस्तुओं और निजी प्रयोग की वस्तुओं को यात्री के निजी सामान के तौर पर आयात किया जा सकता है। ऐसी मदों के नमूने जो अन्यथा इस नीति के अधीन मुक्त रूप से आयात योग्य हैं, का भी लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र के बिना वैयक्तिक असबाब के रूप में आयात किया जा सकता है। विदेश से आने वाले निर्यातकों को भी, लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति पत्र के बिना, अपने वैयक्तिक असबाब के रूप में, उनके पास आए विशिष्ट निर्यात आर्डरों के लिए अपेक्षित ड्राइंग, पैटर्न्स, लैबल्स, प्राइस टैग्स, बटन्स, बैल्ट्स, ट्रिमिंग और एम्बेलिशमेंट्स का आयात करने की अनुमति है।

- निर्यात आधार पर
आयात
- 2.21 नया अथवा पुराना पूंजीगत माल, उपकरण, संघटक, हिस्से एवं उपकरणों, कंटेनर जो निर्यात हेतु माल के पैकिंग के लिए हों उनका सीमाशुल्क प्राधिकारियों के साथ विधिक बचनबद्धता/बैंक गारंटी के निष्पादन पर किसी लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति के बिना निर्यात के लिए आयात किया जा सकता है। बशर्ते कि मद को बिना किसी शर्त/लाइसेंस/अनुमति की आवश्यकता के मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता हो जैसा कि आई टी सी (एच एस) अनुसूची-2 के अन्तर्गत अपेक्षित है।
- विदेश में मरम्मत की
गई वस्तुओं का पुनः
आयात
- 2.22 पूंजीगत माल, उपकरण संघटक अतिरिक्त पुर्जे, एक्सेसरीज चाहे आयातित हो या स्वदेशी, उनकी मरम्मत, परीक्षण गुणवत्ता सुधार या टेक्नोलौजी में सुधार अथवा मानकीकरण के लिए उनको किसी लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति के बिना विदेश भेजा जा सकता है और उनका पुनः आयात किया जा सकता है।
- विदेश में
परियोजनाओं में
प्रयुक्त सामान का
आयात
- 2.23 विदेश में परियोजनाओं के पूरा हो जाने के बाद परियोजना ठेकेदार पूंजीगत माल सहित प्रयुक्त माल का किसी लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति के बिना आयात कर सकता है, बशर्ते कि इनका कम से कम एक वर्ष का इस्तेमाल किया गया हो।
- खुले समुद्र में बिक्री
- 2.24 भारत में आयात हेतु समुद्र में वस्तुओं की बिक्री इस नीति अथवा उस समय प्रभावी किसी अन्य नियम के तहत की जा सकती है।
- लीज फाइनेंसिंग के
अधीन आयात
- 2.25 लीज फाइनेंसिंग के अधीन नई पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु लाइसेंसिंग प्राधिकारी की अनुमति आवश्यक नहीं है।
- सीमाशुल्क से माल
की निकासी
- 2.26 वह माल जो पहले ही आयातित/शिपड/पहुंच गया हो लेकिन सीमाशुल्क से उसकी निकासी न हुई हो उस माल को बाद में जारी लाइसेंस/प्रमाण-पत्र/अनुमति के प्रति निकासी की जा सकती है।
- बैंक गारंटी/विधिक
वचनबद्धता का
निष्पादन
- 2.27 जहाँ कहीं शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है या जहाँ कहीं अन्यथा विनिर्दिष्ट किया गया है, वहाँ आयातक को सीमाशुल्क प्राधिकारी के साथ वस्तुओं की निकासी से पूर्व सीमाशुल्क प्राधिकारी के पास यथानिर्धारित तरीके से एक विधिक वचनबद्धता/बैंक गारंटी का निष्पादन करना होगा। स्वदेशी प्राप्ति पत्र/अनुमति धारक को स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं/नामजद अधिकरणों से माल प्राप्त करने से पूर्व लाइसेंस प्राधिकारी के पास बैंक गारंटी/विधिक वचनबद्धता को प्रस्तुत करना होगा।

बैंक गारंटी से छूट

इस नीति के तहत उन सभी निर्याताकों, जिनका कारोबार चालू वित्तीय वर्ष तथा उससे पहले लाइसेंसिंग वर्ष में न्यूनतम 5 करोड़ का रहा तथा जिसके निर्यातों का तीन वर्षों का रिकार्ड अच्छा हो, को बैंक गारंटी के निष्पादन से मुक्त किया गया है तथा वे उस नीति की किसी भी योजना के तहत बैंक गारंटी के बदले विधिक प्रतिबद्धता प्रस्तुत कर सकते हैं।

आयात के लिए
निजी/सार्वजनिक
बांडेड गोदाम

2.28 राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों के अनुसार घरेलू टैरिफ क्षेत्र में निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदाम बनाए जा सकते हैं।

कोई भी व्यक्ति निषिद्ध मदों, हथियार और गोला-बारूद तथा खतरनाक अपशिष्टों और रसायनों को छोड़कर किसी भी वस्तु का आयात कर सकता है तथा उन्हें ऐसे निजी/सार्वजनिक बांडेड गोदामों में रख सकता है।

ऐसी वस्तुओं को इस नीति के प्रावधानों के अनुसार और जहां कहीं जरूरी हो लाइसेंस के प्रति घरेलू खपत के लिए जारी किया जा सकता है।

ऐसे माल पर निकासी के साथ यथा लागू सीमाशुल्क का भुगतान किया जाएगा।

एक वर्ष की अवधि अथवा बढ़ाई गई अवधि, जिसकी अनुमति सीमाशुल्क प्राधिकारी द्वारा दी जाती है, यदि घरेलू खपत के लिए ऐसी वस्तुओं की निकासी नहीं की जाती तो इनका आयातक इन वस्तुओं का पुनः निर्यात कर सकता है।

मुक्त निर्यात

2.29 आयात और निर्यात की आई.टी.सी.(एच एस) या इस नीति के किसी अन्य प्रावधान या तत्समय लागू किसी अन्य कानून द्वारा विनियमित न होते हों तो सभी निर्यात बिना किसी प्रतिबंध के किया जा सकेगा।

तथापि, महानिदेशक विदेश व्यापार एक सार्वजनिक सूचना के जरिए उन शर्तों को निर्धारित कर सकते हैं जिनके अनुसार आई टी सी (एच एस) में शामिल न की गई किसी वस्तु का लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/अनुमति के बिना निर्यात किया जा सकता है।

नमूनों का निर्यात

2.30 नमूनों और निःशुल्क वस्तुओं के निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित प्रावधानों द्वारा नियंत्रित किया जाएगा (फार्मास्युटिकल्स के विकास हेतु)।

यात्री असबाब का
निर्यात

2.31 बाहर जाने वाले भारतीय यात्रियों के वस्तुतः निजी समान को या तो यात्रियों के साथ ही अथवा यदि साथ न ले जाना हो तो भारत से यात्री के प्रस्थान के पहले या बाद में एक वर्ष के अन्दर ले जाने की अनुमति है। तथापि, आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित तौर पर उल्लिखित मदों के लिए खाद्य मदों को छोड़कर लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति लेना जरूरी होगा।

- उपहारों का निर्यात 2.32 किसी एक लाइसेंसिंग वर्ष में खाद्य मदों सहित 5,00,000/- रुपये तक के मूल्य की वस्तुओं का निर्यात उपहार स्वरूप किया जा सकेगा तथापि, निर्यात की आई टी सी(एच एस) निषेधात्मक सूची की मदों को उपहार के तौर पर बिना लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति के निर्यात नहीं किया जा सकता।
- अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात 2.33 संयंत्र, उपस्कर, मशीनरी, आटोमोबाइल अथवा किसी अन्य माल के स्वदेशी अथवा आयातित वारण्टी अतिरिक्त पुर्जों का निर्यात ऐसे माल की वारण्टी अवधि के भीतर मुख्य उपस्कर के साथ या बाद में, लेकिन भारतीय रिजर्व बैंक के अनुमोदन के मद्दे (7.5% की सीमा को हटाना प्रस्तावित है)।
- तीसरा पक्ष निर्यात 2.34 नीति के अध्याय 9.55 में यथापरिभाषित अनुसार तीसरे पक्ष द्वारा निर्यात की अनुमति होगी।
- आयातित वस्तुओं का निर्यात 2.35 इस नीति के अनुसार आयातित माल का बिना किसी लाइसेंस प्रमाण-पत्र/अनुमति के उसी रूप में या वास्तव में उसी रूप में निर्यात किया जा सकता है बशर्ते आयात या निर्यात की जाने वाली मद विशेष आयात लाइसेंस या निर्यात की निषेधात्मक सूची के अन्तर्गत आयातित मदों को छोड़कर आई टी सी (एच एस) में आयात की प्रतिबंधात्मक सूची या निर्यात की प्रतिबंधात्मक सूची में शामिल न हो। मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के प्रति आयातित ऐसी वस्तुओं के निर्यात मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा में भुगतान के प्रति अनुमत होंगे।
- 2.36 आई टी सी(एच एस) में निर्यात अथवा आयात की प्रतिबंधित मदों के तौर पर उल्लिखित मदों (निषिद्ध मदों को छोड़कर) का आयात सीमाशुल्क बॉण्ड के तहत मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/अनुमति के बिना किया जा सकता है बशर्ते कि मद को बिना किसी शर्त/लाइसेंस/अनुमति की आवश्यकता के मुक्त रूप से निर्यात किया जा सकता हो जैसा कि आई टी सी (एच एस) अनुसूची-2 के अन्तर्गत अपेक्षित है।
- प्रतिस्थापन माल का निर्यात 2.37 निर्यात करते समय यदि कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण/टूटे-फूटे अथवा अन्यथा प्रयोग के अयोग्य पाये जाएं तो उनका प्रतिस्थापन निर्यातक द्वारा निःशुल्क किया जाएगा और इस प्रकार के माल की सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा क्लीयरेंस निम्नलिखित शर्तों के अधीन दी जा सकेगी। बशर्ते कि प्रतिस्थापन माल आई टी सी (एच एस) में निर्यात हेतु प्रतिबंधित मदों के तौर पर अतिरिक्त न हो।

मरम्मत किए गए सामान का निर्यात	2.38	निर्यात करते समय कोई माल या उसके हिस्से दोषपूर्ण, टूटे-फूटे या अन्यथा उपयोग के लिए अयोग्य पाये जायें तो मरम्मत के लिए उनका आयात किया जा सकता है और बाद में पुनः निर्यात किया जा सकता है। ऐसे सामान को लाइसेंस/ प्रमाणपत्र/अनुमति के बिना और समय-समय पर इस संबंध में जारी सीमाशुल्क अधिसूचना के अनुसार निकासी की अनुमति होगी।
निर्यात के लिए निजी वाण्डेड गोदाम	2.39	राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाओं की शर्तों के अनुसार विशेषतया निर्यात के लिए डी टी ए में निजी वाण्डेड गोदाम की स्थापना की जाए। ऐसे गोदाम सीमाशुल्क का भुगतान किए बिना स्वदेशी विनिर्माताओं से माल खरीदने के पात्र होंगे। अधिसूचित गोदामों को स्वदेशी आपूर्तिकर्ताओं द्वारा की गई आपूर्ति को वास्तविक निर्यात माना जाएगा बशर्ते की उसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो।
निर्यात संविदाओं का कोटिकरण	2.40	सभी निर्यात संविदाओं और बीज़कों को मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा के वर्ग में रखा जाएगा परन्तु निर्यात प्राप्तियाँ मुक्त रुप से परिवर्तनीय मुद्रा में वसूल की जाएंगी। तथापि विशेष निर्यातों के प्रति निर्यात प्राप्तियाँ रुपयों में भी वसूल की जा सकती है बशर्ते कि यह ए सी यू के सदस्य देश या नेपाल या भूटान को छोड़कर किसी भी देश में स्थित अप्रवासी बैंक के मुक्त रुप से परिवर्तनीय बोस्टर्स खाते के जरिए हों। इसके साथ बोस्टर्स खाते के जरिए रुपये का भुगतान क्रेता द्वारा उसके अप्रवासी बैंक खाते में मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान के प्रति हों। इस कारोबार के सम्बन्ध में क्रेता द्वारा उसके अप्रवासी बैंक (बैंक सेवा प्रभार को घटाने के बाद) दी गई मुक्त विदेशी मुद्रा इस नीति की निर्यात संवर्धन स्कीमों के तहत निर्यात वसूली के रुप में मानी जाएगी। जिन संविदाओं के लिए भुगतान एशियन क्लयरिंग यूनियन (ए सी यू) के जरिए किए जाएंगे उन्हें ए सी यू डालर के वर्ग में रखा जाएगा। केन्द्रीय सरकार उपयुक्त मामलों में इस पैराग्राफ के प्रावधानों से छूट दे सकती है। एक्विजम बैंक/भारत सरकार लाइन ऑफ क्रेडिट के प्रति निर्यात ठेके और बीजक भारतीय रुपयों में किए जा सकते हैं।
निर्यात प्राप्तियाँ की वसूली	2.41	यदि कोई निर्यातक भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर निर्यात आय वसूल नहीं कर सकता है तो ऐसी स्थिति में, उस समय लागू किसी कानून के अन्तर्गत किसी दायित्व या दण्ड पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, उसके विरुद्ध अधिनियम, नियमों और उसके अंतर्गत जारी किए गए आदेशों और नीति के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई की जा सकेगी।

निर्यात वस्तुओं की मुक्त आवाजाही	2.42	किसी भी केन्द्र सरकार/राज्य सरकार के अभिकरण द्वारा निर्यात हेतु अनुमत मर्दों के कनसाइनमेंट को किसी भी कारण से रोका/निलम्बित नहीं किया जाएगा। किसी भी संदेह की स्थिति में संबंधित प्राधिकारी, निर्यातक से वचनबद्धता मांग सकता है।
स्टॉक को जब्त न करना	2.42.1	किसी भी अभिकरण द्वारा स्टॉक को जब्त नहीं किया जायेगा ताकि विनिर्माण संबंधी कार्यकलापों और निर्यात वस्तुओं की सुपुर्दगी की तारीख में बाधा न डाली जा सकें। कुछ खास मामलों में, संबंधित अधिकरण प्रथम दृष्टया प्रमाण के आधार पर स्टॉक को जब्त कर सकती है। तथापि, इस प्रकार जब्त किए गए माल को 7 दिन के भीतर छोड़ना होगा।
निर्यात संवर्धन परिषद	2.43	निर्यात संवर्धन परिषदों का मूल उद्देश्य देश के निर्यात को बढ़ावा देना और उसमें वृद्धि करना है। प्रत्येक परिषद विशेष वर्ग के उत्पाद परियोजनाओं और सेवाओं के संवर्धन के लिए जिम्मेदार है। निर्यात संवर्धन परिषदों की सूची तथा उनका मुख्य कार्य प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है।
पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाणपत्र	2.44	कोई भी व्यक्ति जो आयात निर्यात के लिए (1) लाइसेंस/प्रमाण पत्र/अनुमति पत्र आई टी सी(एच एस) में सूचीबद्ध मर्दों के अतिरिक्त (2) किसी अन्य लाभ या इस नीति के अन्तर्गत किसी अन्य छूट के लिए आवेदन करता है तो उसको प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के अनुसार सक्षम प्राधिकारी द्वारा जारी पंजीकरण एवं सदस्यता प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना होगा बशर्ते कि इस सम्बन्ध में विशेष रूप से उसे छूट न दी गई हो।
इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेंज	2.45	व्यवसाय की गति बढ़ाने के लिए, व्यक्तिगत रूप से सम्पर्क कम करने और निर्यातों से संबंधित गतिविधियों में पारदर्शिता लाने के लिए इलेक्ट्रॉनिक फण्ड ट्रान्सफर के जरिए भुगतान को बढ़ावा दिया जाएगा। ऐसे आवेदनों पर 24 घन्टे के भ्तर विचार कर लिया जाएगा और आवेदक को प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-29 में उल्लिखित शुल्क का केवल 50 प्रतिशत देना होगा।
सीमाशुल्क अधिनियम के तहत निपटान आयोग के जरिए निर्यात दायित्व चूक का विनियमीकरण और सीमाशुल्क और ब्याज का निपटान	2.46	ऐसी फर्मों को सहायता प्रदान करने को ध्यान में रखते हुए जिन्होंने ऐसे कारणों को उनके नियंत्रण में न हीं थे, के लिए विदेश व्यापार नीति के तहत भुगतान नहीं किए हैं और कमजोर इकाईयों के विलयन, अर्जन और पुर्नवास को सरल बनाने के लिए 0.1.04.2005 से ऐसे मामलों का निर्णय लेने के लिए उत्पाद एवं सीमाशुल्क केन्द्रीय बोर्ड में निपटान आयोग बनाने का निर्णय लिया गया है।

निर्यातकों और
आयातकों के लिए
दस्तावेजी अपेक्षाओं
को आसान करना

2.47 अन्तराष्ट्रीय व्यापार के लिए एकल सामान्य दस्तावेज के पूरा होने तक निर्यातों और आयातों से संबंधित सरकारी विभाग निर्यात दस्तावेजों जैसे कि शिपिंग बिल, बैंक वसूली प्रमाणपत्र, पैकिंग सूची, लेडिंग बिल इत्यादि की जाँच के आधार पर अन्य सरकारी विभागों द्वारा जारी अनुमति/लाइसेंस/प्रमाण-पत्र को मान्यता देंगे।

सेवा कर से छूट

2.48 निर्यातित माल या सेवाओं के संबंध में, यदि माल और सेवाएं सेवा कर के अधीन हैं, तो यह छूट प्राप्त होंगी।

शिकायत सुधार

शिकायतों का
निवारण

2.49 विदेश व्यापार महानिदेशालय निर्यातों और आयातों के सुविधाकारक के रूप में कार्य करने को वचनबद्ध है। हमारा केन्द्र बिन्दु सही संचालन पर है जो कि स्पष्ट, पारदर्शी और उत्तरदायी निकासी प्रणालियों पर निर्भर करता है।

2.49.1 विदेश व्यापार महानिदेशालय का एक सिटीजन चार्टर है जिसमें कि आयातकों और निर्यातकों के प्रति इसकी वचनबद्धता दर्शाई गई है। इसमें ग्राहकों को सेवाएँ प्रदान करने के लिए समय सूची भी दी गई है और विभिन्न स्तरों पर शिकायत समितियों के विवरण दिए गए हैं।

स्थायी शिकायत
समितियाँ

2.49.2 नीति और प्रक्रिया से संबंधित व्यापार और उद्योग की शिकायतों के तीव्र सुधार को आसान बनाने लिए सभी कार्यालयों में शिकायत समितियाँ गठित की गई हैं। क्षेत्रीय स्तर और मुख्यालयों पर ये स्थायी समितियाँ पुनः गठित की जाएंगी।

समितियाँ, जिनमें सीमाशुल्क, आयकर तथा अन्य संबंधित विभाग और एजेंसियाँ सभी बाकी मामलों पर विचार करने और सुलझाने के लिए प्रत्येक पक्ष में बैठक रखेंगी।

निर्यातकों की सभी शिकायतें, इन समितियों के अध्यक्ष को पहले ही इलेक्ट्रानिकली भेज दी जाएंगी। क्षेत्रीय कार्यालयों में लिए जाने वाले निर्णयों के संबंध में, शिकायत पर अधिकारी द्वारा विचार किया जाएगा जो कि मुख्यालय में अपर महानिदेशक, विदेश व्यापार के रैंक से नीचे का न हो।

बैव चैट

2.49.3 विदेश व्यापार महानिदेशालय में विदेश व्यापार नीति पर शंकाओं के उत्तर देने के लिए व्यापार और उद्योग के साथ इन्ट्रैक्टिंग के लिए इसके बैवसाइट पर एक चैट विन्डो खोली गई है। यह बैव आधारित इन्टरफेस प्रत्येक महीने के दूसरे बुधवार को शाम 3.00 से 5.00 तक होगा।

अध्याय - तीन

संवर्धनात्मक उपाय

राज्यों को निर्यात विकास 3.1
हेतु मूलभूत सुविधाओं के
(ए एस आई डी ई)

पैरा 1.5 में उल्लिखित पद्धति के अनुसार राज्य सरकारों को निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए पूरा योगदान देते हुए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस उद्देश्य हेतु वाणिज्य विभाग ने एक योजना बनाई है जिसको ए0एस0आई0डी0ई0 कहा जाएगा।

राज्यों को राशि आबंटित करने के लिए वाणिज्य विभाग ने वार्षिक योजना में निवल निर्यात तथा निर्यात में बढ़ोत्तरी के दर के दोहरे मानक के आधार पर उपर्युक्त प्रावधान किए गए हैं।

राज्य इस राशि को प्राथमिक मूल ढाँचे के विकास हेतु उपयोग करेगा जैसे कि उत्पादन केंद्रों को पत्तनों के साथ जोड़ने के लिए सड़कें बनाना और इनलैण्ड कन्टेनर डिपो और कन्टेनर फ्रेट स्टेशन को स्थापित करना, नए राज्य स्तर के निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्कों/जोनों की संरचना और मौजूदा जोनों में सामान्य सुविधाओं को बढ़ाना, मूलभूत ढाँचे की परियोजनाओं में इक्विटी भागीदारी तथा विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा समय-समय पर यथा अधिसूचित किन्हीं अन्य गतिविधियों में भाग लेना।

बाजार पहुँचने की पहल 3.2
(एमएआई)

बाजार पहुँचने की पहल (एमएआई) योजना माध्यम स्तर के निर्यात संवर्धन प्रयत्नों के लिए है जिसमें देशों तथा उत्पाद पर सुस्पष्ट केन्द्र बिन्दु होगा।

वित्तीय साहयता निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग और व्यापार एसोसियेशनों राज्य सरकार की एजेंसियों, विदेशों में भारतीय वाणिज्यिक मिशनों तथा अन्य पात्रा हस्तियों, जिनको समय-समय पर अधिसूचित किया जाएगा के लिए उपलब्ध है।

एम.ए.आई. योजना के अन्तर्गत विभिन्न कार्यकलापों को वित्तीय सहायता दी जा सकती है, जिसमें बाजार का अध्ययन, शो रूम, गोदाम सुविधाएँ, बिक्री संवर्धन मुहिम अन्तर्राष्ट्रीय डिपार्टमेंटल स्टोर, प्रचार मुहिम, अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों बाण्ड प्रमोशन, भेषजीय उत्पादन पंजीकरण तथा इंजीनियरिंग उत्पादों के लिए परीक्षण प्रभार भी शामिल है। इनमें से प्रत्येक निर्यात संवर्धन गतिविधियों सरकार से उनके कुल लागत के 25 प्रतिशत से 100 प्रतिशत तक वित्तिय

विपणन विकास सहायता 3.2.1 (एमडीए)	<p>सहायता उनकी गतिविधियों के आधार पर दिया जा सकता है, मार्गदर्शन की का पूरा विवरण एचटीपीप/कामर्स.एनआईसी.इन में देखा जा सकता है।</p> <p>निर्यात संवर्धन परिषदों, उद्योग और व्यापार एसोसिएशनों द्वारा नियमित रूप से प्रत्येक वर्ष निर्यात संवर्धन गतिविधियों के क्रियान्वयन के लिए विपणन विकास सहायता (एमडीए) योजना बनाई गई</p> <p>संशोधित एमडीए मार्गदर्शन 1 अप्रैल, 2004 से उन निर्यातकों को एमडीए सहायता उपलब्ध है जिनका वार्षिक कारोबार 5 करोड़ रु० है</p> <p>इसमें व्यापार मेलों विदेशों या भारत में क्रेताओं और विक्रेताओं के सम्मेलन में भागीदारी व्यापार संवर्धन सेमिनार भी शामिल है</p> <p>इसके अतिरिक्त उन निर्यातकों के जो कि चार केन्द्र बिन्दु क्षेत्र जैसे कि लैटिन, अमेरिका, अफ्रिका, सीआईएस क्षेत्र, एएमईएन दो, आस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड की यात्रा करते हैं, उनको यात्रा अनुदान तथा अन्तर्राष्ट्रीय व्यापार मेलों भागदारी के लिए सहायता उपलब्ध है।</p> <p>अन्य क्षेत्रों में ब्रूपार मेलों इत्यादि में शामिल होने के लिए बिना अनुदान के लिए वित्तीय सहायता उपलब्ध है।</p>
व्यापार संवर्धित मामले में 3.2.1.1 मुकदमें पर खर्च का चुकाना	<p>निर्यात संवर्धन परिषदों की अनुशंसा पर योग्य पाना निर्यातक व्यापार संवर्धित मामले में मुकदमें पर खर्च को चुकाने के लिए वित्तीय सहायता दी जाएगी।</p>
उत्कृष्ट निर्यात के शहर 3.3	<p>कुछ विशिष्ट औद्योगिक स्थलों में अनेक शहर अच्छे खासे औद्योगिक स्थापना स्थलों के रूप में उभरे हैं जो भारत के निर्यात में पर्याप्त योगदान देते हैं। इन औद्योगिक क्लस्टर मदों को मान्यता देना आवश्यक हो गया है ताकि उनके निर्यात प्रोफाइल को अधिकतम किया जा सके और उच्च मूल्य बाजार में जाने के लिए उनका दर्जा बढ़ाने में सहायता किया जा सके।</p> <p>1000 करोड़ या उससे अधिक निर्यात करने वाले कुछ कस्बों को उनकी निर्यात क्षमता के आधार पर उत्कृष्ट निर्यात के शहर के रूप में अधिसूचित किया जाएगा। तथापि हथकरघ, हस्तशिल्प, कृषि व मत्स्य क्षेत्रों में उत्कृष्ट निर्यात के शहर के लिए यह सीमा 250 करोड़ रूपया होगी।</p> <p>इन क्षेत्रों में साधारण सेवा संभरक ईपीसीजी योजना के हकदार होंगे।</p> <p>इन मान्यता प्राप्त एसोसिएशनों केन्द्रित तकनीके सेवाओं के</p>

- बनाने के लिए बाजार पहुँचने में पहल योजना के अन्तर्गत निधि पर पहुँच होगी ।
फिर भी ऐसे क्षेत्र एसआईडीई योजना में से आइडेंटिफाईड क्रिटिकल इन्फ्रास्ट्रक्चर गैप में संशोधन के लिए प्राथमिकता के आधार पर सहायता प्राप्त करेंगे ।
उत्कृष्ट निर्यात के शहर के अधिसूचित कस्बे परिशिष्ट 41 में दिए गए हैं ।
- ब्रांड संवर्धन तथा गुणवत्ता 3.4.1 भारत सरकार की नीति यह है कि वह विनिर्माताओं और निर्यातकों को इस बात के लिए प्रोत्साहित करें कि वे अपने-अपने उत्पादों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वीकृत गुणवत्ता के मानदण्डों को प्राप्त करें । केन्द्रीय सरकार गुणवत्ता जागरूकता पर एक राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम बनाने और कुल गुणवत्ता प्रबंध के विचार को बढ़ावा देने के लिए उद्योग और व्यापार संस्थाओं को समर्थन और सहायता प्रदान करेगी ।
- परीक्षण गृह 3.4.2 केन्द्रीय सरकार परीक्षण गृहों और प्रयोगशालाओं को अंतर्राष्ट्रीय मानकों के बराबर के स्तर का बनाने के लिए उनके आधुनिकीकरण और उन्नयन में सहायता करेगी ।
- गुणवत्ता संबंधी शिकायतें/ 3.4.3 विदेशी क्रेताओं से प्राप्त हुई गुणवत्ता संबंधी शिकायतों की विवाद जांच विदेश व्यापार महानिदेशालय के क्षेत्रीय कार्यालयों में गठित गुणवत्ता शिकायतों हेतु क्षेत्रीय उप-समिति द्वारा की जाएगी । गुणवत्ता संबंधी शिकायतों के निवारण हेतु मार्ग निर्देश, विशेषतः और ऐसी अन्य शिकायतों के संबंध में, सामान्यतः, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-37 में दिए गए हैं ।
- व्यापार संबंधों को 3.4.4 यदि विदेश व्यापार महानिदेशक की जानकारी में यह बात प्रभावित करने वाले व्यापारिक विवाद आती है अथवा उन्हें यह विश्वास हो जाता है कि कोई निर्यात अथवा आयात इस तरीके से किया गया है,
(i) किसी बाहरी देश के साथ भारत के व्यापार संबंधों के लिए हानिकारक हो,
(ii) निर्यात अथवा आयात में कार्यरत अन्य व्यक्तियों के हितों के प्रति हानिकर हो;
(iii) जिससे देश की बदनामी हुई हो
तो ऐसी स्थिति में विदेश व्यापार महानिदेशक संबंधित निर्यातक अथवा आयातक के विरुद्ध अधिनियम, इसके अधीन बने नियमों तथा आदेशों और इस नीति के उपबंधों के अनुसार कार्यवाही कर सकते हैं ।

स्टार व्यापार सदन 3.5.1 व्यापारी और विनिर्माता निर्यातक, सेवा प्रदायक, निर्यातोन्मुखी एकक (ई ओ यू)/निर्यात संसाधन जौन (ई पी जेड)/विशेष आर्थिक जौन (एस ई जेड)/कृषि निर्यात जौन (ई पी जेड) में स्थित यूनितें/ इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर तकनॉलॉजी पार्क (ई एच टी पी)/ साफ्टवेयर तकनॉलॉजी पार्क (एस टी पी) स्टार निर्यात सदन स्तर की मान्यता के पात्र हैं।

निर्यात निष्पादन स्तर 3.5.2 आवेदक की श्रेणी का निर्धारण चालू पिछले तीन वर्षों की कुल जहाज पर्यन्त निःशुल्क मूल्य/एफओआर निर्यात स्थिति पर निर्भर करेगा।

श्रेणी

निष्पादन (रुपयों में)

एक स्टार निर्यात सदन

15 करोड़

दो स्टार निर्यात सदन

100 करोड़

तीन स्टार निर्यात सदन

500 करोड़

चार स्टार निर्यात सदन

1500 करोड़

पाँच स्टार निर्यात सदन

5000 करोड़

टिप्पणी :-

1. लघु उद्योग/अति लघु क्षेत्र/कुटीर क्षेत्र के यूनित/के वी आई सी या के वी आई सी के साथ पंजीकृत यूनित/पूर्वोत्तर राज्यों, सिक्किम ओर जम्मू एवं कश्मीर में स्थित यूनित/हस्तकरघा, हस्त शिल्प, हाथ से बुना कालीन, रेशम के कालीन निर्यात करने वाले यूनित तथा “स्वर्ण स्तर” वाले निर्यातक लेटिन अमेरिका और सी आई एस। सब सहारन अफ्रीका को निर्यात करने वाले निर्यातक, परिशिष्ट 17 ग में सूचीबद्ध अधिकर जो द्वारा दिए गए आई एस ओ 9000 श्रृंखला आईएसओ 14000 श्रृंखला स्तर वाले डब्ल्यूएचओजीएमपी/एचएसीसीपी/एसईआईसीएमएम-2 स्तर तथा उच्च स्तर प्राप्त एजेंसियां जो परिशिष्ट 28क में सूचीबद्ध की गई हैं। स्टार व्यापार सदन के एस ओ आर प्राप्त करने पर प्रारम्भिक सीमा सेवा निर्यातकों और कृषि निर्यातकों (अनाज के अलावा) पर लागू होगी।

2. मान्यता प्रदान करने के लिए पुनः निर्यात आधार पर किए गए निर्यात की गणना नहीं की जाएगी।

3. मान्यता के प्रयोजन के लिए किसी लिमिटेड कम्पनी की सहायक कम्पनी द्वारा किये गये निर्यात को लिमिटेड कम्पनी के निर्यात निष्पादन में गिना जाएगा। इस प्रयोजन के लिए कम्पनी के सहायक कम्पनी में अधिकतर शेयर होने चाहिए।

- विशेषाधिकार 3.5.2.1 एक स्टार निर्यात सदन निम्नलिखित सुविधाओं के हकदार होंगे :-
- (i) स्व-घोषणा आधार पर आयात और निर्यात दोनों के लिए लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति और सीमाशुल्क निकासी।
 - (ii) तरजीह पर निवेश-उत्पादन मानदण्डों का निर्धारण 60 दिन के भीतर
 - (iii) बैंकों के माध्यम से दस्तावेजों के अनिवार्य लेन-देन से छूट, तथापि बैंकिंग चैनलों से रुपया भेजना जारी रहेगा।
 - (iv) ई ई एफ सी खाते में विदेशी मुद्रा का 100 प्रतिशत रखना होगा,
 - (v) सामान्य प्रत्यावर्तन अवधि को 180 दिन से 360 दिन तक करना।
 - (vi) लक्ष्यों परियोजना (टारगेट प्लस स्कीम) के अधीन स्वीकृती के लिए हकदार होगा।
 - (vii) इस नीति के अधीन योजनाओं बैंक गारंटी प्रस्तुत करने की छूट होगी।
- वैधता अवधि 3.5.3 1.9.2002 को या उससे बाद जारी अथवा नवीकृत सभी स्तर प्रमाण पत्र लाइसेंसिंग वर्ष के 1 अप्रैल से वैध होंगे। इस अवधि के दौरान आवेदक जब तक अन्य विनिर्दिष्ट न हो 31.3.2009 तक ऐसी मान्यता की मंजूरी के लिए आवेदन कर सकता है। ऐसे प्रमाण-पत्र की समाप्ति पर प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा-निर्धारित अवधि के भीतर स्तर प्रमाण-पत्र के नवीकरण के लिए आवेदन देना आवश्यक होगा। उक्त अवधि के दौरान स्तर-धारक आम सुविधाओं और लाभों के लिए दावा करने का हकदार होता है।
- सेवा निर्यात 3.6.1 सेवाओं में व्यापार संबंधी सामान्य समझौते के तहत आने वाले सभी 161 व्यापार योग्य सेवाएं शामिल हैं। यहाँ ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान को मुक्त विदेशी मुद्रा में लिया जाएगा। सेवाओं की सूची प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट - 36 में दी गई हैं। सेवा निर्यातकों को फियो के पास पंजीकरण कराना होगा। तथापि, सॉफ्टवेयर निर्यातकों को इलैक्ट्रॉनिक और सॉफ्टवेयर निर्यात संवर्धन परिषद के पास पंजीकरण कराना होगा। नीति में उल्लिखित सभी सुविधाएं पाने के हकदार होंगे। नीति के सभी प्रावधान आवश्यक परिवर्तनों के साथ सेवाओं के निर्यात के लिए भी लागू होंगे जो वस्तुओं के लिए लागू हैं।

सेवाओं के लिए निर्यात संवर्धन परिषद	3.6.2	सेवा निर्यात को भारतीय निर्यातक संघ के संगठन के साथ पंजीकृत होना होगा।
सेवाओं के लिए नई निर्यात संवर्धन परिषद		<p>सेवा क्षेत्र को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वास्तविक दिशा निर्देशों के तहत सेवाओं के लिए एक विशेष निर्यात संवर्धन परिषद बनाई जायगी।</p> <p>सेवा निर्यात संवर्धन परिषद निम्न कार्य करेगी:</p> <ul style="list-style-type: none"> (i) मुख्य सेवाओं के लिए मुख्य बाजारों की तलाश करेगी और मैट्रिक्स के प्रत्येक भाग के लिए कार्यक्रम के माध्यमों से बाजार का विकास करेगी। (ii) ब्राण्ड स्थापित करने और लक्ष्य बाजारों में मार्केटिंग कार्यक्रम तैयार करने में क्षेत्रीय सेवा प्रदायक के साथ सहयोग करेगी। (iii) नीति, प्रक्रिया और द्विपक्षीय/बहुपक्षीय मुद्दों के संबंध में सेवा उद्योग की मान्य नोडल बोडी के समन्वय स्थापित करने में आवश्यक हस्तक्षेप करेगी।
आम सुविधा केन्द्र	3.6.3	सरकार क्षेत्र विशेष में गृह आधार पर सेवा प्रदायकों जैसे इंजिनियरिंग तथा वास्तुविद डिजाइन, मल्टी-मिडिया कार्यक्रमों, साफ्टवेयर का निकास करने वालों आदि उपयोग हेतु आम सुविधा केन्द्रों की स्थापना और विकास करेगी तथा राज्य स्तर और जिला स्तर के कस्बों से सेवा निर्यात नजरिये में गृह आधारित व्यावसायिकों को भारी संख्या में बुलाया जायेगा।
उद्देश्य	3.6.4.1	सेवाओं के निर्यात में वृद्धि को बढ़ावा देना उद्देश्य है ताकि सशक्त और विशिष्ट “भारत से प्रदान की गई सेवा” बांड को तुरंत समस्त विश्व में मान्यता और आदर प्राप्त हो जाए।
पात्रता	3.6.4.2	सभी सेवा प्रदायकों जिन्होंने विगत अथवा चालू वित्तीय वर्ष में कम से कम 10 लाख रुपए का कुल विदेशी मुद्रा अर्जन किया है शुल्क क्रेडिट हकदारी हेतु पात्रता के हकदार होंगे। उन व्यक्तियों हेतु जो सेवा प्रदायक हैं, कुल विदेशी मुद्रा अर्जन मापदंड विगत वित्तीय वर्ष में 5 लाख रुपए होगा।
हकदारी	3.6.4.3	सभी सेवा प्रदायक (होटलों और रेस्टोरेंटों को छोड़कर) विगत वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट के हकदार होंगे।

- होटल और रेस्टोरेंट 3.6.4.4 पर्यटन विभाग द्वारा अनुमोदित एक सितारा और उससे अधिक होटल (मैनेज्ड होटल और हैरिटेज होटल शामिल हैं) और पर्यटन विभाग के पास पंजीकृत पर्यटन क्षेत्र के अन्य सेवा प्रदायक विगत वित्तीय वर्ष में रेस्टोरेंट बिक्रियों से उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 5 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट के हकदार होंगे ।
विशिष्ट रेस्टोरेंट विगत वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 20 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट के हकदार होंगे ।
टिप्पणी : एक और दो सितारा होटलों और विशिष्ट रेस्टोरेंटों के मामले में अन्तर्राष्ट्रीय क्रेडिट कार्डों के माध्यम से अर्जित विदेशी मुद्रा को स्कीम के तहत शुल्क क्रेडिट हकदारी के परिकलन के उद्देश्य हेतु गिना जाए ।
- अनुमत आयात 3.6.4.5 शुल्क क्रेडिट हकदारी को स्पेयर्स, कार्यालय उपकरण और पेशेवर उपकरण, कार्यालय फर्नीचर और उपभोग्यों समेत किसी भी पूंजीगत माल के आयात हेतु प्रयोग किया जा सकता है बशर्ते के यह उनके मुख्य व्यापार का एक हिस्सा हो ।
होटलों और विशिष्ट रेस्टोरेंटों के मामले में शुल्क क्रेडिट हकदारी को खाद्य वस्तुओं और अल्कोहल युक्त पेयों हेतु भी प्रयोग किया जा सकता है ।
- गैर-हस्तांतरणीयता 3.6.4.6 हकदारी और आयातित माल गैर-हस्तांतरणीय होगा ।
- हैल्थ केयर और शिक्षा 3.6.4.7 हैल्थ केयर और शैक्षणिक संस्थानों को विश्वस्तर के स्टेट- आफ-द-आर्ट मूलभूत सुविधाएँ प्राप्त करने की दृष्टि से, इन क्षेत्रों के सेवा प्रदायक, अन्य सेवा प्रदायकों की तरह, विगत वित्तीय वर्ष में उनके द्वारा अर्जित विदेशी मुद्रा के 10 प्रतिशत के बराबर शुल्क क्रेडिट के हकदार होंगे ।
(i) हैल्थ केयर संस्थानों हेतु विदेशी मुद्रा कारोबार में मैडीकल ट्रीटमेंट, सर्जरी, टैस्टिंग, कंसलटेंसी और संस्थान द्वारा प्रदान की जाने वाली हैल्थ केयर के माध्यम से अर्जित फीस शामिल होगी ।
(ii) शैक्षणिक संस्थानों हेतु विदेशी मुद्रा कारोबार में संस्थान द्वारा प्रदान किए जाने वाले कोर्सों और कंसल्टेंसी के माध्यम से अर्जित फीस शामिल होंगी ।
(iii) किसी भी मामले में, इसमें किसी अन्य स्रोत के माध्यम से प्राप्त विदेशी मुद्रा जिसमें इक्विटी भागीदारी, जोनेशन आदि शामिल नहीं होगी ।
शुल्क मुक्त हकदारी के तहत आयातित पूंजीगत माल और उपभोग्य माल का संबंधित शैक्षणिक अथवा हैल्थ केयर संस्थानों की गतिविधियों से संबंध होगा ।
- विशेष प्रावधान 3.6.4.8 सरकार के पास जनहित में अधिकार सुरक्षित होगा कि वह समय-समय पर सेवा निर्यातों की श्रेणी अथवा किस्म निर्धारित करेगी जो पात्रता अथवा हकदारी की गणना हेतु पात्र नहीं होंगे ।
इसी प्रकार, सरकार समय-समय पर उस माल को भी अधिसूचित करेगी जो स्कीम के तहत जारी शुल्क मुक्त हकदारी प्रमाणपत्र के तहत आयात हेतु अनुमत नहीं होंगे ।

लक्ष्योपरि स्कीम (टारगेट प्लस स्कीम)

उद्देश्य	3.7.1	स्कीम का उद्देश्य है निर्यात में वृद्धि हेतु स्टार निर्यात सदनों को पुरस्कृत करना जिन्होंने निर्यात में अत्यधिक वृद्धि को प्राप्त किया है। अधिक निष्पादन प्राप्त करने वाले स्टार निर्यात सदन निर्धारित समस्त वार्षिक निर्यात लक्ष्य से काफी अधिक किए निर्यात के आधार पर शुल्क क्रेडिट हेतु पात्र होंगे (चूंकि 2004-05 हेतु निर्धारित लक्ष्य 16% है, चालू वर्ष में पुरस्कारों हेतु पात्र बनने के लिए निष्पादन की निम्नतर सीमा 20% निर्धारित की गई है)														
पात्रता मापदंड	3.7.2	सभी स्टार निर्यात सदन (एग्जिम नीति 2002-2007 के पैरा 3.7.2.1 में यथा परिभाषित स्तर धारकों समेत) जिन्होंने विगत वर्ष यानीकि अप्रैल 2003-2004 में 10 करोड़ रुपए की मुक्त विदेशी मुद्रा में न्यूनतम निर्यात कारोबार किया है लक्ष्योपरि स्कीम के तहत विचार किए जाने हेतु पात्र (यानि कि 2004-2005) है।														
हकदारी	3.7.3	<p>इस स्कीम के तहत हकदारी विगत वर्ष की तुलना में चालू वर्ष में प्रतिशतता संवर्धन वृद्धि पर आधार होगी जो इस प्रकार है :</p> <table border="1"> <tr> <td>2004-2005 के दौरान</td> <td>शुल्क क्रेडिट हकदारी</td> </tr> <tr> <td>प्रतिशतता संवर्धन वृद्धि</td> <td>(संवर्धन वृद्धि के % तौर पर)</td> </tr> <tr> <td>20% से अधिक परन्तु</td> <td>5%</td> </tr> <tr> <td>25% से कम</td> <td></td> </tr> <tr> <td>25% से अधिक परन्तु</td> <td>10%</td> </tr> <tr> <td>100% से कम</td> <td></td> </tr> <tr> <td>100% और अससे अधिक</td> <td>15% (100% का)</td> </tr> </table> <p>टिप्पणी : (i) 100 प्रतिशत से अधिक की संवर्धित वृद्धि शुल्क क्रेडिट हकदारी की गणना हेतु नहीं गिनी जाएगी।</p> <p>(ii) इस स्कीम के उद्देश्य हेतु, निर्यात निष्पादन किसी अन्य निर्यातक को स्थानान्तरित अथवा से स्थानान्तरित नहीं किया जाएगा। तीसरे पक्ष द्वारा निर्यात के मामले में सहायक विनिर्माता/विनिर्माता निर्यातक का नाम घोषित किया जाएगा।</p> <p>(iii) निर्यातक के पास विकल्प होगा कि वह लक्ष्योपरि स्कीम अथवा विशेष कृषि उपज योजना के तहत लाभ उठाने हेतु आवेदन करेगा परन्तु एक ही निर्याति उत्पाद के</p>	2004-2005 के दौरान	शुल्क क्रेडिट हकदारी	प्रतिशतता संवर्धन वृद्धि	(संवर्धन वृद्धि के % तौर पर)	20% से अधिक परन्तु	5%	25% से कम		25% से अधिक परन्तु	10%	100% से कम		100% और अससे अधिक	15% (100% का)
2004-2005 के दौरान	शुल्क क्रेडिट हकदारी															
प्रतिशतता संवर्धन वृद्धि	(संवर्धन वृद्धि के % तौर पर)															
20% से अधिक परन्तु	5%															
25% से कम																
25% से अधिक परन्तु	10%															
100% से कम																
100% और अससे अधिक	15% (100% का)															

बारे में होने हेतु नहीं, बशर्ते कि पैरा 3.7.3 के तहत हकदारी गिनने के लिए प्रतिशतता संबंधित विकास गिनने हेतु कुल पात्र निर्यातों को ध्यान में रखा जायेगा, लेकिन शुल्क क्रेडिट हकदारी की गणना हेतु पात्र निर्यातों को उस मात्र से घटा दिया जाएगा जिसके लिए पैरा 3.8.2 के तहत लाभ का दावा किया गया।

(iv) मुक्त शिपिंग बिल जो सीमा शुल्क द्वारा सत्यापित और प्रमाणित किये गये हैं और रत्न और आभूषण शिपिंग बिलों के तहत किये निर्यातों समेत सभी निर्यात, लेकिन पैरा 3.7.5 के तहत विनिर्दिष्ट निर्यातों को छोड़कर लक्ष्योपरि स्कीम के तहत लाभों हेतु पात्र होंगे।

आवेदक कम्पनियाँ 3.7.4

वे कम्पनियाँ, जो स्टार निर्यात सदन हैं और किसी समूह कम्पनी का भी हिस्सा हैं, अलग कम्पनी का समूह के कुल करोबार में वृद्धि के आधार पर समूह कम्पनी के रूप में आवेदन कर सकती हैं (इस योजना के प्रयोजन के लिए अध्याय 9 में दी गई समूह कम्पनी की परिभाषा लागू होगी। इसके अलावा, समूह की केवल ऐसी कम्पनियों पर विचार किया जायेगा जो स्टार निर्यात सदन हैं)।

यदि कोई समूह कम्पनी/अपने एक या अधिक अलग-अलग स्टार निर्यात सदन कम्पनियों के निर्यात के आधार पर आवेदन करती है तो हकदारी का परिकलन आवेदक कम्पनी के पिछले वर्ष (1 अप्रैल, 2003-31 मार्च, 2004) के निर्यात निष्पादन के आधार पर किया जायेगा। यह जरूरी होगा कि चालू वर्ष (1 अप्रैल, 2004-31 मार्च, 2005) के दौरान समूह की सभी स्टार निर्यात सदन कम्पनियों का सभायोचित निर्यात निष्पादन पिछले वर्ष (1 अप्रैल, 2003-31 मार्च, 2004) में समूह की सभी स्टार निर्यात सदन कम्पनियों के समग्र निर्यात निष्पादन से कम नहीं होना चाहिए।

यदि कोई समूह, समूह के करोबार (अर्थात् सभी स्टार निर्यात सदन कम्पनियों का करोबार) में कुल वृद्धि के आधार पर आवेदन करता है तो समूह की स्टार निर्यात सदन कम्पनियों में से कोई भी एक कम्पनी समूह की सभी स्टार निर्यात सदन कम्पनियों की ओर से आवेदन कर सकती है।

3.7.5

इस योजना के अन्तर्गत निम्नलिखित निर्यातों को निर्यात निष्पादन या हकदारी परिकलन करने के लिए नहीं गिना जायेगा:-

(क) विदेश व्यापार नीति के पैरा 2.35 के अधीन शामिल आयातित वस्तुओं का निर्यात या ट्रांशिपमेंट के जरिये किया गया निर्यात।

(ख) एसईजेड/ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपीआई योजनाओं के अधीन संचालित एककों का निर्यात कारोबार या उन द्वारा विनिर्मित डीटीए के जरिये निर्यातित उत्पाद।

(ग) मान्य निर्यात (चाहे भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया गया हो और भुगतान ईईएफसी खाते से किया गया हो)।

(घ) सेवा निर्यात।

(ङ.) अपरिष्कृत, काटे न गये और अर्ध पालिशड हीरे और अन्य बहुमूल्य पत्थर।

(च) किसी भी रूप में स्वर्ण, चांदी, प्लेटिनम और अन्य बहुमूल्य धातुएँ, जिसमें इनसे बने सदे आभूषण शामिल हैं। तथापि, इस योजना के तहत हकदारी के लिए जड़ित आभूषणों के निर्यात को नहीं गिना जायेगा।

(छ) निर्यातक की ओर से अन्य निर्यातक अन्य द्वारा किया गया निर्यात निष्पादन।

अनुमत आयात 3.7.6

शुल्क क्रेडिट का इस्तेमाल किसी निविष्टि, स्पेयर्स, कार्यालय उपकरण, व्यवसायिक उपकरण और कार्यालय फर्निचर सहित पूंजीगत वस्तुएं बशर्ते आईटीसी (एसएस) के तहत अपने या परिशिष्ट 17घ में यथा निर्दिष्ट सहायक विनर्माताओं के प्रयोग के लिए इनका मुक्त रूप से आयात किया जा सकता हो।

आई टी सी (एचएस) के अध्याय 1-24 में दिए गए कृषि उत्पादों का आयात इस योजना के अन्तर्गत अनुमत नहीं होगा।

सेंवेट/शुल्क-मुक्त 3.7.7

लक्ष्योपरि योजना (टारगेट प्लस स्कीम) के तहत नकद या डेबिट के जरिये किए गये अतिरिक्त सीमा-शुल्क/उत्पाद शुल्क के भुगतान को राजस्व विभाग द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार समयोजित किया जायेगा।

- विशेष प्रावधान 3.7.8 सरकार को जन हित में यह अधिकारी रहेगा कि वे समय-समय पर उन निर्यातों और निर्यात उत्पादों के वर्ग को निर्दिष्ट करे जो बढ़ रही वृद्धि/हकदारी के परिकलन हेतु पात्र नहीं होंगे।
इसी प्रकार, सरकार समय-समय पर उन वस्तुओं की सूची को भी अधिसूचित कर सकती है जिनका आयात इस योजना के तहत जारी किए गए शुल्क क्रेडिट हकदारी प्रमाणपत्र के अन्तर्गत अनुमत नहीं होगा।

विशेष कृषि उपज योजना

- उद्देश्य 3.8.1 इस योजना का उद्देश्य ऐसे उत्पादों के निर्यातकों प्रोत्साहन देकर फलों, सब्जियों, फूलों, साधारण वन्य उपज और इनके मूल्य संवर्धित उत्पादों को बढ़ावा देना है।
- हकदारी 3.8.2 ऐसे उत्पादों के निर्यातक अप्रैल, 2004 मार्च-मार्च, 2005 की अवधि के लिए निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत बराबर शुल्क क्रेडिट स्क्रिप के हकदार होंगे। इसके मद्दे आयातित स्क्रिप और मर्दे मुक्त रूप हस्तांतरणीय होंगी।
- अनुमत आयात 3.8.3 शुल्क क्रेडिट का प्रयोग यथा निर्दिष्ट निविष्टियों या पूंजीगत वस्तुओं के आयात हेतु किया जा सकता है बशर्ते आई टी सी (एचएस) के तहत इनका मुक्त रूप से आयात किया जा सके।

निर्यात के पत्तन के अलवा अन्य किसी पत्तन से आयात की अनुमति राजस्व विभाग द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों के अनुसार दी जा सकती है।
- सेंवेट/शुल्क-मुक्त 3.8.4 विशेष कृषि उपज योजना के तहत नकद या डेबिट के जरिये किए गये अतिरिक्त सीमा-शुल्क/उत्पाद शुल्क के भुगतान को राजस्व विभाग द्वारा बनाये गये नियमों के अनुसार समायोजित किया जायेगा।
- विशेष प्रावधान 3.8.5 सरकार को जन हित में यह अधिकारी रहेगा कि वे समय-समय पर उन निर्यातों और निर्यात उत्पादों के वर्ग को निर्दिष्ट करे जो बढ़ रही वृद्धि/हकदारी के परिकलन हेतु पात्र नहीं होंगे।

अध्याय - चार

शुल्क मुक्त/वापसी स्कीम

शुल्क मुक्त/वापसी स्कीम	4.1	शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत निर्यात उत्पाद के लिए आवश्यक निविष्टियों का आयात किया जाता है। शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत अग्रिम लाइसेंस जारी किया जाता है। शुल्क वापसी स्कीम के अन्तर्गत निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों पर लगे शुल्क के निर्यात पश्चात छूट/वापसी की जाती है। शुल्क वापसी स्कीम में (क) डी एफ आर सी और (ख) डी ई पी बी शामिल हैं। डी एफ आर सी निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निवेशों के शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति (रिपलैनिशमेंट) अनुमत करता है। डी ई पी बी स्कीम में निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त निविष्टियों पर आयात प्रभारों की वापसी की अनुमति है।
शुल्क मुक्त/वापसी स्कीम के अन्तर्गत निर्यात की गई वस्तुओं का पुनः आयात	4.1.1	अग्रिम लाइसेंस/डी एफ आर सी/डी ई पी बी के अन्तर्गत निर्यात की गई वस्तुओं का पुनः आयात उसी रूप या आंशिक रूप से उसी रूप में पुनः आयात किया जा सकता है बशर्ते कि वे समय-समय पर जारी राजस्व विभाग द्वारा विनिर्दिष्ट शर्तों को पूरा करते हों।
मूल्य संवर्धन	4.1.2	इस अध्याय के मामले में मूल्य संवर्धन इस प्रकार होगा :- वी.ए. ए-बी = ----- 100, जहाँ बी वी.ए. मूल्य संवर्धन ए वास्तविक निर्यात का पोत पर्यन्त निशुल्क मूल्य/प्राप्त आपूर्ति के मूल्य के लिए बी लाइसेंस के तहत आने वाले आयातित निवेशों का लागत बीमा भाड़ा मूल्य

अग्रिम लाइसेंस

4.1.3

निर्यात उत्पाद में (अपशिष्ट के लिए सामान्य अनुमति देते हुए) वास्तव में शामिल की जाने वाली निविष्टियों के आयात की अनुमति देने के लिए शुल्क मुक्त स्कीम के अन्तर्गत अग्रिम लाइसेंस प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, स्कीम के अधीन ईंधन, तेल, ऊर्जा, कैटालिस्ट आदि जिनकी खपत निर्यात उत्पाद के लिए उपयोग की जाती है, भी जारी किया जा सकता है। अग्रिम लाइसेंस के अधीन लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक ऐसे मैडेटरी (वैधानिक) कलपुर्जों के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है जिनके परिणामी उत्पाद को सायन (एस आई ओ एन) के अधीन निवेशों और निर्यात मदों के आधार पर अग्रिम लाइसेंस जारी किए जाने की अनुमति है।

तथापि, वे प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 4.7 के अनुसार स्वतः घोषित मानदण्डों या तदर्थ मानदण्डों के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं। अग्रिम लाइसेंस के अधीन लाइसेंस के लागत बीमा भाड़ा मूल्य के 10 प्रतिशत तक ऐसे अनिवार्य अतिरिक्त कलपुर्जों का भी शुल्क मुक्त आयात की अनुमति है जिनके परिणामी उत्पाद के साथ निर्माण/आपूर्ति की अपेक्षा होती है, अग्रिम लाइसेंस निम्नलिखित के लिए जारी किया जाता है:-

(क) वास्तविक निर्यात:- निर्यात उत्पाद हेतु आवश्यक निवेशों के आयात हेतु सहायक विनिर्माता से संबंध विनिर्माता निर्यातक अथवा व्यापारी निर्यातक को वास्तविक निर्यातों जिसमें एस ई जैड को भी निर्यात शामिल है। हेतु अग्रिम लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

(ख) अन्तर्वर्ती आपूर्ति:- अन्य अग्रिम लाइसेंसधारक अंतिम मूल निर्यातक/मान्य निर्यातक को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के विनिर्माण में अपेक्षित निविष्टियों के आयात के लिए विनिर्माता-निर्यातक को अन्तर्वर्ती आपूर्ति हेतु अग्रिम लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

(ग) मान्य निर्यात:- नीति के पैरा 8.2 (ख), (ग), (घ), (ड.), (च), (छ) और (ज) में उल्लिखित वर्गों को आपूर्ति की जाने वाली वस्तुओं के विनिर्माण में आवश्यक निविष्टियों को आयात हेतु मुख्य ठेकेदार को मान्य निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस जारी किया जा सकता है।

इसके अलावा, नीति के पैराग्राफ 8.2 (घ), (ड.), (च), (छ) और (ज) में उल्लिखित विनिर्दिष्ट परियोजनाओं को माल की आपूर्ति के संबंध में मान्य निर्यात हेतु अग्रिम लाइसेंस का लाभ मुख्य ठेकेदार के ऐसे उप-ठेकेदारों द्वारा भी उठाया जा सकता है जिन उप-ठेकेदारों का नाम मुख्य ठेके में दिया गया है।

मान्य निर्यात के लिए ऐसे लाइसेंस, संयुक्त राष्ट्र संगठनों, या संयुक्त राष्ट्र के सहायता कार्यक्रम के अधीन या अन्य बहुपक्षीय एजेंसियों को की जाने वाली आपूर्तियों और विदेशी मुद्रा में भुगतान के लिए भी जारी किया जा सकता है।

- 4.1.4 वास्तविक प्रयोक्ता शर्त के मद्दे पैरा 4.1.1 में परिभाषित निवेशों के शुल्क मुक्त आयात हेतु अग्रिम लाइसेंस जारी किया जाता है। ऐसे लाइसेंस (मान्य निर्यातों हेतु अग्रिम लाइसेंस के अलावा) मूल सीमाशुल्क, अतिरिक्त सीमाशुल्क, एंटीडम्पिंग शुल्क, और सुरक्षा शुल्क, यदि कोई हो, से छूट प्राप्त होंगे। तथापि, ईओयू/एसईजेड/ ईएचटीपी/एसटीपी को की जाने वाली आपूर्तियों के मामले में एंटी-डम्पिंग शुल्क और सुरक्षा शुल्क में भी छूट प्राप्त होंगे।
- 4.1.5 अग्रिम लाइसेंस और/अथवा उनके तहत आयातित माल निर्यात दायित्व की पूर्ति के बाद भी हस्तान्तरणीय नहीं होंगे।
- 4.1.6 अग्रिम लाइसेंस (मान्य निर्यातों और अन्तरवर्ती आपूर्ति हेतु अग्रिम लाइसेंस) सकारात्मक मूल्य संवर्धन के साथ जारी किया जा सकता है।
तथापि, ऐसा निर्यात जिसका भुगतान मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त नहीं होता है वह प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-32 में यथाविनिर्दिष्ट मूल्य संवर्धन के अधीन होगा।
- 4.1.7 अग्रिम लाइसेंस जारी करने की तारीख को प्रभावी प्रक्रिया और नीति के अनुसार जारी किया जाएगा और यथाविनिर्दिष्ट समयबद्ध निर्यात दायित्व की पूर्ति की शर्तों के अधीन होगा।
- 4.1.8 अग्रिम लाइसेंस की सुविधा वहाँ भी उपलब्ध होगी जहाँ निर्यातक को कुछ निवेशों की निशुल्क आपूर्ति की जाती है।

ऐसे मामलों में, मूल्य संवर्धन की गणना हेतु, निशुल्क निवेशों के नोशनल मूल्य के साथ अन्य शुल्क मुक्त निवेशों को भी ध्यान में रखा जाएगा तथापि, यदि सभी निविष्टियों की बिना लागत आपूर्ति की जाती है तो ऐसे निविष्टियों नीति के पैराग्राफ 4.2.7 के अधीन आएंगे।

निर्यात दायित्व

- 4.1.9 अग्रिम लाइसेंस के अधीन निर्यात दायित्व को पूरा करने की अवधि प्रक्रिया पुस्तक भाग-1 में उल्लिखित अनुसार होंगी। वास्तविक निर्यातों के लिए अग्रिम लाइसेंसों के तहत निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए एस ई जैड को की जाने वाले आपूर्ति को भी सम्मिलित किया जाएगा।

- वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम लाइसेंस 4.1.10 अग्रिम लाइसेंस वास्तविक निर्यातों अर्न्तवर्ती आपूर्तियों या मान्य निर्यातों के लिए वार्षिक अपेक्षाओं के आधार पर भी जारी किए जा सकते हैं।
- एक से पाँच सितारा निर्यात सदन, वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम लाइसेंस के लिए पात्र होंगे। तथापि, वे स्तरधारक जिनके पास व्यापारी निर्यातक का प्रमाण-पत्र है, वे वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम लाइसेंस के भी पात्र होंगे बशर्ते कि वे संगत लाइसेंस में सह निर्माता के नाम (नामों) के पृष्ठांकन के लिए सहमत हों।
- इस योजना के तहत पूर्व लाइसेंसिंग वर्ष में निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 200% तक पात्रता होगी। ऐसे लाइसेंस का सकारात्मक मूल्य संवर्धन होगा।
- अग्रिम रिलीज आदेश 4.1.11 अग्रिम लाइसेंसधारक, (वार्षिक अपेक्षा के लिए अग्रिम लाइसेंसधारक और डी एफ आर सी धारक जो सीधे आयात के बदलने स्वदेशी स्रोतों राज्य व्यापार अभिकरणों/ई ओ यू/एस ई जेड/ई एच टी पी/ एस.टी.पी. यूनिटों से निविष्टियां प्राप्त करना चाहता है तो उसे उन निविष्टियों को अग्रिम रिलीज आदेशों के प्रति विदेशी मुद्रा/भारतीय रूपए में प्राप्त करने का विकल्प होगा। डी एफ आर सी के हस्तातरणकर्ता भी ए.आर.ओ सुविधा के लिए पात्र होगा। तथापि, ई.ओ.यू/ई.एच.टी.पी/एस.टी.पी/एस ई जेड से ए.आर.ओ को परिवर्तन किए बिना लाइसेंस के प्रति आपूर्तियां प्राप्त की जा सकती हैं।
- बैंक टू बैंक ऋण का अन्तर्देशीय साख पत्र 4.1.12 अग्रिम लाइसेंसधारक(वार्षिक अपेक्षाओं के लिए अग्रिम लाइसेंसधारक) और डी एफ आर सी धारक अग्रिम रिलीज आदेश के लिए आवेदन करने के बजाय प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार बैंक टू बैंक अन्तर्देशीय साख पत्र का लाभ उठा सकता है।
- निषिद्ध मदें 4.1.13 इस स्कीम के अन्तर्गत जारी लाइसेंसों के तहत आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित आयातों का निषिद्ध मदों का आयात नहीं किया जाएगा।
- शुल्क वापसी की स्वीकार्यता 4.1.14 अग्रिम लाइसेंस कोई भी आयातित या स्वदेशी शुल्क प्रस्त सामग्री को वित्त मंत्रालय (शुल्क वापसी निदेशालय) द्वारा निर्धारित शुल्क वापसी दर के अनुसार शुल्क वापसी उपलब्ध होगी। तथापि, लाइसेंस में यथाउल्लिखित शुल्क प्रदत्त सामग्रियों को ही शुल्क वापसी दी जाएगी।

शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र (डी एफ आर सी)

- 4.2 वस्तुओं के विनिर्माण में प्रयुक्त निविष्टियों के आयात के लिए व्यापारी-निर्यातक अथवा विनिर्माता-निर्यातक को मूल सीमाशुल्क, शुल्क और विशेष अतिरिक्त शुल्क का भुगतान किए बिना शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किया जाता है। तथापि, ऐसी निविष्टियाँ आयात के समय उत्पाद शुल्क के बराबर अतिरिक्त सीमाशुल्क के भुगतान के शर्तों के अधीन होंगी।
- 4.2.1 डी एफ आर सी, रत्न और आभूषण क्षेत्र की ऐसी मदों जिनके लिए प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 4.56.1 में मूल्य संवर्धन दिया गया है, को छोड़कर 25 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य संवर्धन पर जारी किए जायेंगे।
- 4.2.2 उस निर्यात के लिए शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र जारी किया जा सकता है जिसके लिए भुगतान अपरिवर्तनीय मुद्रा में प्राप्त किया गया हो। तथापि, ऐसा निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-32 में यथानिर्दिष्ट मूल्य संवर्धन के अधीन होगा। डी.एफ.आर.सी उन आपूर्तियों के लिए भी जारी की जा सकती है जो नीति के पैराग्राफ 8.2 के अधीन प्रभावी है।
- 4.2.3 विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा यथाअधिसूचित सिओनस के अन्तर्गत शामिल केवल निर्यात उत्पादों के संबंध में शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। तथापि सिओनस जो "वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त के अधीन है या जहाँ आयात की पूर्व शर्त सहित निविष्टि की अनुमति है या जहाँ निर्यात को पूरा न किया गया हो या सामान्य मानदण्डों के तहत ईंधन के आयात के लिए हो, इन सब निवेशों के लिए डी एफ आर सी वास्तविक प्रयोक्ता की शर्त सहित जारी किया जाएगा।

तथापि, ईंधन, जोकि कैनलाइज्ड है, के लिए आयात पात्रता कैनलाइजिंग एजेंसी को हस्तांतरित की जा सकती है।

ऐसे मामले जिनमें मानक निवेश उत्पाद मानदण्ड एसिटिक एनहाइड्राइड, एपीड्राइन तथा सिओडो एपीड्राइन के आयात को अनुमत करते हैं, इनके लिए डी एफ आर सी जारी किया जाएगा बशर्ते इन मदों को विशेषतः आयात मदों की सूची से न हटा दिया गया हो।

सॉयन (एस आई ओ एन) जोकि निवेशों के लिए पूर्व आयात की शर्त लगाता हो, के मामले में डी एफ आर सी जारी नहीं किया जाएगा।

- 4.2.4 शिपिंग बिल में यथा उल्लिखित सिओन के अनुसार निविष्टियों के आयात के लिए शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाणपत्र जारी किए जाएंगे। ऐसे लाइसेंसों की वैधता 24 माह की होगी। डी. एफ. आर. सी. और/या इसके मद्दे आयातित सामग्री मुक्त रूप से हस्तांतरणीय

होगी। तथापि, वास्तविक प्रयोक्ता की सशर्त डी एफ आर सी या उसके बदले में आयातित सामग्री (सामग्रियों) अहस्तांतरणीय होंगी।

4.2.5 निर्यात उत्पाद, जो संशोधित वैट के लिए पात्र हैं, सेनवेट ऋण के लिए पात्र होंगे। तथापि, स्कीम के अन्तर्गत गैर-उत्पाद शुल्क योग्य, गैर-शुल्क योग्य या केन्द्रीय वैट योग्य उत्पाद, स्कीम के तहत आयात के समय प्रदत्त अतिरिक्त सीमाशुल्क के बदले में निर्यात के समय शुल्क वापसी के पात्र होंगे।

4.2.6 शुल्क वापसी निदेशालय (वित्त मंत्रालय) द्वारा निर्धारित शुल्क वापसी दर के अनुसार निर्यात उत्पाद में प्रयुक्त किसी भी सामग्री जिसपर शुल्क अदा किया गया हो चाहे आयातित हो अथवा स्वदेशी, के संबंध में निर्यातक शुल्क वापसी लाभों के लिए पात्र होंगे। तथापि, शुल्क वापसी उन सामग्रियों पर दी जाएगी जिन पर शुल्क दिया गया हो और सिओन के अन्तर्गत न आती हों।

पुनः निर्यात के लिए 4.2.7 राजस्व विभाग द्वारा समय-समय पर जारी की गयी अधिसूचना के अनुसार जाबिंग मरम्मत आदि जो माल आई टी सी (एच एस) में प्रतिबंधित रूप में उल्लिखित है लेकिन पैराग्राफ 4.1.1 में निःशुल्क आपूर्ति की शर्तों पर निषिद्ध मद नहीं है जाबिंग प्रयोजन के लिए उसका लाइसेंस/प्रमाणपत्र/अनुमति के बिना आयात के अनुमति दी जा सकती है। सीमाशुल्क अधिसूचना की शर्तों के अनुसार, मरम्मत, रिकंडिशनिंग, रिइंजीनियरिंग, टेस्टिंग आदि करने के लिए इसी प्रकार के माल के आयात की अनुमति होगी चाहे वह माल निर्यात आयात नीति/आयात और निर्यात पुस्तक के आई.टी.एच.एस वर्गीकरण के अधीन आयात के लिए प्रतिबंधित हों।

शुल्क पात्रता पास 4.3 शुल्क छूट पासबुक स्कीम का उद्देश्य है निर्यात उत्पाद के आयात अंश पर बुक स्कीम लागू मूल सीमाशुल्क को अप्रभावी करना है। निर्यात उत्पाद के अधीन शुल्क ऋण को प्रदान करने के माध्यम से अप्रभावीकरण की व्यवस्था की जाएगी।

डी ई पी बी योजना तब तक चालू रहेगी जब तक कि निर्यातकों के साथ परामर्श करके कोई नई योजना नहीं बनाई जाती।

4.3.1 डी ई पी बी के अधीन निर्यातक, अपनी ऋण की पात्रता के कारण मुक्त परिवर्तनीय मुद्रा में किए गए निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य की विनिर्दिष्ट प्रतिशता का दावा करने का पात्र होगा।

कच्चे माल, अन्तरवर्तियों, संघटकों, कलपूर्जों, पैकेजिंग सामग्री आदि के आयात हेतु क्रेडिट, ऐसे निर्यात उत्पादों और दर के लिए

		उपलब्ध होगा जो विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा इस संबंध में जारी सार्वजनिक सूचना में विनिर्दिष्ट किए गए हों।
	4.3.2	डी ई पी बी धारक के पास अतिरिक्त सीमाशुल्क का भुगतान नकद करने का विकल्प होगा।
वैधता	4.3.3	डी ई पी बी, इसके जारी होने की तारीख से 24 माह की अवधि के लिए वैध होगा।
हस्तांतरणीयता	4.3.4	डी ई पी बी और/अथवा इसके प्रति आयातित मदे मुक्त हस्तांतरणीय हैं। तथापि, डी ई पी बी का हस्तांतरण आयात के लिए डी ई पी बी में आयात के लिए विनिर्दिष्ट उस पत्तन पर होगा जहाँ से निर्यात किया गया है।
		तथापि, निर्यात के अन्य पत्तन से आयातों को राजस्व विभाग द्वारा जारी की गई टी आर ए अधिसूचना की शर्तों के अनुसार अनुमति दी जाएगी।
शुल्क वापसी उपयुक्तता	4.3.5	सामान्य रूप से डी. ई. पी. बी. स्कीम के अधीन किए गए निर्यात शुल्क वापसी के हकदार नहीं होंगे। डी ई पी बी अधीन निविष्टियों पर नकद अदा किया गया अतिरिक्त सीमाशुल्क उत्पाद शुल्क को राजस्व विभाग द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसार सेनेवैट क्रेडिट या शुल्क वापसी के रूप में समायोजित किया जाएगा।
रत्न और आभूषण के लिए योजनाएं	4.4	रत्न और आभूषण निर्यातक इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार लाइसेंसिंग प्राधिकारी से प्रतिपूर्ति लाइसेंस (आर ई पी) प्राप्त करके अपने निवेशों का आयात कर सकते हैं।
प्रतिपूर्ति लाइसेंस	4.4.1	प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 26 में सूचीबद्ध रत्न और आभूषण उत्पादों के निर्यातक, अपने निवेशों के आयात और प्रतिपूर्ति के लिए उक्त परिशिष्ट में उल्लिखित दर पर और उसमें दी गई मदों के लिए, प्रतिपूर्ति लाइसेंस के पात्र होंगे। प्रतिपूर्ति लाइसेंस, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैराग्राफ 4.80 में उल्लिखित विवरण के अनुसार उपभोक्त्यों के आयात के लिए भी जारी किया जा सकता है।

- प्रमाणन ग्रेडिंग
केलिए कटे हुए
और पॉलिश किए
हीरों का निर्यात
- 4.4.2 कम से कम तीन वर्षों का निर्यात अनुभव रखने वाले और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ रुपये और उससे अधिक के वार्षिक औसत कारोबार करने वाले अथवा जिमोलॉजिकल इस्टिच्यूट आफ इंडिया (जी आई ए), दि रोबर्ट मोउवाड कैम्पस, इन्टरनेशनल जिमोलॉजिकल इस्टिच्यूट (आई जी आई) और यू एस ए में यूरोपियन जिमोलॉजिकल लेबोरेटरी (ईजीएल), हॉग रोड बूर डायमण्ड, एन्टवर्प (एच आर डी) वर्ल्ड डायमण्ड सेंटर आफ डायमण्ड हाई काउंसिल उक्त प्रयोगशालाओं/एजेन्सियों द्वारा निर्धारित प्रमाणन/ग्रेडिंग प्रयोजन के लिए कटे हुए और पॉलिश किए हुए हीरों, प्रत्येक वजन 0.50 कैरिट और उससे अधिक के निर्यात की अनुमति दी जाएगी बशर्ते पुनः आयात के एन्टवर्प बेल्जियम के भारत में प्राधिकृत अधिकारी/एजेन्सियों से बिना किसी आयात शुल्क के भुगतान की अभिकरणों से प्रमाण-पत्र/ग्रेडिंग रिपोर्टों सहित पुनः आयात किया जाएगा।
- 4.4.2.1 प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिये करे हुए और पालिश किये हीरों के निर्यात के समय निर्यातक को सीमाशुल्क को यह वचनबद्धता देनी होगी कि कटे हुये और पालिश किये हीरे प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिये निर्यात के तीन माह के भीतर पुनः आयात किया जायेगा। निर्यात बीजक में प्रमाणन/ग्रेडिंग के लिए निर्यात किए जाने वाले प्रत्येक हीरे के अनुमानित मूल्य, ऊंचाई, व्यास, भार का स्पष्ट उल्लेख किया जाये ताकि उनके आयात के समय उनकी पहचान के लिए उक्त विनिर्देशन के साथ मूल की तुलना की जा सके। बाद में, इन कटे और पालिश किए हीरों का नीति के प्रावधानों के अनुसार निर्यात किया जा सके।
- स्वर्ण/चांदी/
प्लेटिनम के
आभूषणों के लिए
योजनाएं
- 4.4.3 स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों और उनकी वस्तुओं के निर्यातक इस संबंध में निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार स्वर्ण, प्लेटिनम, चांदी, माउंटिंग्स, फाइंडिंग्स, अपरिष्कृत रत्न, कीमती और अर्द्ध-कीमती पत्थर सिन्थेटिक पत्थर और असंसाधित मोती आदि जैसी अपनी अनिवार्य निविष्टियों का आयात कर सकते हैं।
- नामित एजेंसियां
- 4.4.4 स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों और उनकी वस्तुओं की स्कीमों का लाभ उठाने वाले निर्यातक नामित एजेंसियों से स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं। नामित एजेंसियां ये हैं - एमएमटीसी लिमिटेड, हस्तशिल्प और हथकरघा निर्यात निगम (एच एच ई सी), राज्य व्यापार निगम (एस टी सी) भारतीय परियोजना और उपकरण निगम लिमिटेड (पी ई सी) और भारतीय रिजर्व बैंक (आर बी आई) द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य एजेंसी, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत एजेंसी/भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्राधिकृत बैंक को रिफाइनिंग के लिए गोल्ड स्क्रेप का निर्यात करने तथा स्टैंडर्ड गोल्ड बार्स के रूप में आयात करने की अनुमति है।

सोने आयात के विषय में विस्तृत प्रक्रिया भरतीय रिजर्व बैंक द्वारा पृथक रूप से अधिसूचित की जाएगी ।

निर्यात की मर्दे

4.4.5 निम्नलिखित मर्दों का यदि निर्यात किया जाता है तो वे इन स्कीमों के अन्तर्गत सुविधाओं के लिए पात्र होंगी ।

(क) 8 कैरेट या अधिक सोना वाले सोने के जेवरात चाहे सादे हों अथवा जड़ित जिनमें आंशिक रूप से संसाधित आभूषणों तथा ऐसी अन्य वस्तुएं जिनमें तमगे एवं सिक्के शामिल हैं (इनमें कानूनी निविदा किस्म के सिक्के शामिल नहीं हैं)

(ख) भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी वाले आंशिक रूप से संसाधित जेवरात सहित चांदी के जेवरात और वस्तुएं इसमें मैडल और सिक्के शामिल हैं (इनमें वैध टेंडर वाले सिक्के और कोई इंजीनियरी माल शामिल नहीं है।)

(ग) भार के रूप में 50 प्रतिशत से अधिक भार प्लेटिनम वाले जेवरात जिनमें आंशिक रूप से संसाधित आभूषण तथा ऐसी अन्य वस्तुएं जिनमें तमगे एवं सिक्के शामिल हैं (इनमें कानूनी निविदा किस्म के सिक्के व इंजीनियरिंग माल शामिल नहीं हैं)।

मूल्य परिवर्धन

4.4.6 मूल्य परिवर्धन प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 4.5.6.1 के पैरा 4.5.6.1 अनुसार होगी।

वेस्टेज मानदंड

4.4.7 सोने/चांदी/प्लेटिनम जेवरात के लिए स्कीमों के तहत, विनिर्माण अपशेष अथवा वेस्टेज प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 4.56 के पैरा 4.56 में विनिर्दिष्ट के अनुसार अनुमत होगी।

- विदेशी क्रेता द्वारा
आपूर्ति के प्रति
निर्यात
- 4.4.8 जहाँ निर्यात आदेश तीन वर्ष के अनुभव वाले नामित एजेंसी/स्तरधारियों/निर्यातकों जिन्होंने पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ का कारोबार किया है, को दिया जाता है वहां विदेशी क्रेता को विनिर्माण और निर्यात के लिए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम एलॉय प्लेटिनम फाइंडिंग्स और चांदी/स्वर्ण/प्लेटिनम की माउंटिंग को अग्रिम और मुक्त रूप में आपूर्ति कर सकता है। नामित अभिकरणों द्वारा सीधे या उनकी सहयोगी कम्पनियां या स्तरधारियों/निर्यातकों जैसी भी स्थिति हो, के माध्यम से निर्यात किया जा सकता है। फाइंडिंग्स का आयात और निर्यात नेट टू नेट आधार पर किया जाएगा। विदेशी क्रेता, नामित एजेंसियों/स्तरधारियों/निर्यातकों को सादे, अर्ध परिष्कृत सोना/चांदी/प्लेटिनम आभूषण जिनमें मरम्मत/पुनःनिर्माण और निर्यात के लिए फाइंटिंग/माउंटिंग/कम्पोनेन्ट्स शामिल हैं, की भी आपूर्ति कर सकता है बशर्तों के न्यूनतम मूल्य संवर्धन 10 प्रतिशत हो तथापि, यदि इस प्रकार के आयातित अर्ध परिष्कृत सोना/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों का जड़ित आभूषण के रूप में निर्यात किया जा सकता है। उनका मूल्य संवर्धन 15 प्रतिशत प्राप्त किया जायेगा। निर्यात के ऐसे मामलों में 2 प्रतिशत के छीजन की अनुमति होती है। इस संबंध में प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्धारित है।
- प्रदर्शनियों/निर्यात
संवर्धन दौरों/
ब्रान्डेड आभूषणों के
माध्यम से
- 4.4.9 वाणिज्य मंत्रालय और अन्य के अनुमोदन से नामित एजेंसियां और उनके सहयोगी तथा रत्न एवं आभूषण निर्यात संवर्धन परिषद (जी. जे. ई. पी. सी) के अनुमोदन से विदेशों में प्रदर्शनियों लगाने/भाग लेने के लिए सोने/चांदी/प्लेटिनम के जेवरों और उनकी वस्तुओं का निर्यात कर सकते हैं। सोना/चांदी/प्लेटिनम के आभूषणों, कीमती, अर्ध कीमती पत्थरों, मनके और वस्तुओं के व्यक्तिगत कैरेज और ब्रान्डेड आभूषणों के निर्यात की भी अनुमति होगी। यह निर्यात प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार होगा।
- नामित एजेंसियों
द्वारा आपूर्ति के
निर्यात
- 4.4.10 निर्यातक, इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार निर्यात उत्पादों के लिए सोने/चांदी/प्लेटिनम को निवेश के रूप में अग्रिम अथवा प्रति निर्यात के बाद प्रतिपूर्ति के तौर पर नामित एजेंसियों से प्राप्त कर सकता है।
- अग्रिम लाइसेंस
प्रति निर्यात
- 4.4.11 निम्नलिखित हेतु शुल्क मुक्त आयात के लिए अग्रिम लाइसेंस दिया के जा सकता है।
(क) कम से कम 0.995 शुद्धता का सोना, और 8 कैरेट और अधिक के माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स।
(ख) कम से कम 0.995 शुद्धता की चांदी, माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स जिनमें भार में 50 प्रतिशत से अधिक चांदी हो।
(ग) कम से कम 0.900 शुद्धता का प्लेटिनम, माउन्टिंग्स, साकेट्स, फ्रेम्स एवं फाइंडिंग्स जिनमें भार में 50 प्रतिशत से अधिक प्लेटिनम हो।

	<p>4.4.12 ऐसे लाइसेंसों में निर्यात दायित्व की शर्त रहेगी जिसे इस संबंध में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार पूरा करना अपेक्षित होगा।</p> <p>अग्रिम लाइसेंसधारक इस बारे में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार सीधे आयात के बदले नामित एजेंसियों से सोना/चांदी/प्लेटिनम प्राप्त कर सकते हैं।</p>
रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस	<p>4.4.13 नीति के पैरा 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10, और 4.4.11 में दिए गए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम आभूषण और उनसे बनी वस्तुओं के निर्यात के लिए स्कीमों के तहत रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस जारी किया जा सकता है। सादा स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी जेवरात और उनकी वस्तुओं के मामले में, ऐसे लाइसेंसों का मूल्य, निर्धारित न्यूनतम मूल्य परिवर्धन से अधिक की वसूली के संदर्भ में निर्धारित किया जाएगा। जड़ित स्वर्ण/चांदी प्लेटिनम जेवरात और उनकी वस्तुओं के मामले में, अनुमेय वेस्टेज समेत स्वर्ण/प्लेटिनम/चांदी पर मूल्य परिवर्धन का हिसाब लगाने के बाद, निर्यातित मदों में उपयुक्त जड़ितों के मूल्य को ध्यान में रखकर रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस का मूल्य निर्धारित किया जाएगा। ऐसे रत्न प्रतिपूर्ति लाइसेंस मुक्त रूप से हस्तान्तरणीय होंगे।</p>
रत्न प्रतिपूर्ति दर और मद	<p>4.4.14 प्रतिपूर्ति का पैमाना और आयात की प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के मद परिशिष्ट 26क के अनुसार निर्धारित होगी।</p>
निर्यात/आयात पार्सलों को व्यक्तिगत तौर पर ले जाना	<p>4.4.15 विदेश जाने वाले यात्रियों द्वारा रत्नों और आभूषणों के निर्यात पार्सल तथा किसी भारतीय आयातक/विदेशी नागरिक द्वारा रत्नों और आभूषणों के आयात पार्सल को, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार व्यक्तिगत रूप से ले जाने की अनुमति होगी।</p>
हीरा अग्रदाय लाइसेंस	<p>4.4.16 कटे और पालिश किये हीरों आधे कटे हीरे, किसी भी रूप में कटे हुए सहित मिश्रण के लिए यदि अपेक्षित हो, कटे और पालिश किए हुए हीरों के आयात और कटे और पालिश किये हीरों के निर्यात के लिए हीरा अग्रदाय लाइसेंस जारी किया जा सकता है।</p> <p>ऐसे लाइसेंसों के तहत निर्यात दायित्व की पूर्ति, इस बारे में जारी प्रक्रिया के अनुसार करनी होगी।</p>
पात्रता	<p>4.4.16.1 कटे और पालिश किए हीरों के निर्यातक जो स्तरधारी हो, को कटे और पालिश किए हीरों के पिछले वर्ष के निर्यात निष्पादन के 5 प्रतिशत तक कटे और पालिश किए हीरों के आयात के लिए लाइसेंस जारी किया जा सकता है।</p>

- निर्यात दायित्व 4.4.16.2 प्रत्येक खेप के प्रति निर्यात दायित्व की पूर्ति, सीमाशुल्क के जरिए ऐसे प्रत्येक खेप की निकासी की तारीख से पांच महीनों के अन्दर की जाएगी। तथापि, आयातक को न तो अलग-अलग आयात खेप का रिकार्ड रखना होगा न ही निर्यात दायित्व की पूर्ति हेतु आयात खेप के अनुसार निर्यात खेप भेजनी होगी।
- निजी/सार्वजनिक बांडिड गोदाम 4.4.17 कटे और पालिश किए गए हीरों, कटे और पालिश किए गए रंगीन रत्नों, अनकटे और सेट न किए हुए बहुमूल्य और अर्ध-बहुमूल्य पत्थरों के आयात और पुनः निर्यात के लिए एस ई जैड/डी टी ए में निजी एवं सार्वजनिक बान्डेड गोदाम स्थापित किए जा सकते हैं। कटे और पालिश किए गए हीरों और कटे और पालिश किए गए रंगदार रत्नों का आयात और पुनः निर्यात 5 प्रतिशत के न्यूनतम मूल्य संवर्धन की प्राप्ति के अनुसार होगा।
- हीरा और जवाहरात डॉलर खाते 4.4.18 अपरिष्कृत या कटे और पालिश किए हीरों की खरीद/बिक्री करने वाली फर्मों तथा कम्पनियों जिनका हीरों के आयात या निर्यात में कम से कम 3 वर्षों का अनुभव है और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों के दौरान 5 करोड़ या इससे अधिक का वार्षिक औसत कारोबार है, के नामजद हीरा डॉलर खातों के जरिये लाइसेंसों के बिना अपना व्यापार जारी रख सकती है के अधीन हीरा डॉलर लेखा स्कीम इस अध्याय के चालू लाइसेंसिंग स्कीम के अंतर्गत चलाई जाएगी। यह स्कीम वैकल्पिक होगी और जो ऐसे खातों में डॉलर बैंक वित्त और/या निर्यात आय से उपलब्ध होगा और इनका प्रयोग केवल (1) विदेशी स्थानीय स्रोतों से अपरिष्कृत हीरों की आयात/खरीद (2) स्थानीय स्रोतों से कटे और पालिश हीरों की खरीद (3) बैंक से डॉलर भरणों का भुगतान और (4) निर्यातकों के रुपये लेखा में हस्तांतरण के लिए किया जाएगा। इस हीरा डॉलर खाता योजना के ब्यौरे प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिए गए हैं।

प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित प्रक्रिया हीरा जड़ित आभूषणों पर भी लागू होगी।

एक गैर डी डी ए धारक को भी डी डी ए धारक को कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों की प्रतिपूर्ति करने की अनुमति है, भुगतान डालर में मिलेगा तथा इसे 7 दिन के भीतर रूपयों में बदलना होगा। कटे हुए एवं पॉलिश किए हुए हीरों की गैर डी डी ए धारक द्वारा की गई प्रतिपूर्ति को भी उसके निर्यात आभार को पूरा किया गया ही माना जाएगा और/या इसे प्रतिपूर्ति लाइसेंस का हक प्राप्त हो जाएगा।

अध्याय - पाँच

निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल स्कीम

ई.पी.सी.जी स्कीम 5.1

(कम्प्यूटर साफ्टवेयर सिस्टम एस के डी/सी के डी समेत) पूर्व उत्पादन, उत्पादन और पश्च उत्पादन के लिए पूंजीगत वस्तुओं का 5 प्रतिशत सीमाशुल्क के आधार पर इस योजना के तहत आयात किया जा सकता है। बशर्ते कि लाइसेंस के जारी होने की तिथि के 8 वर्षों के ऊपर ई पी सी जी स्कीम के तहत आयातित पूंजीगत माल पर बचाए गए शुल्क के 8 गुणा के बराबर निर्यात दायित्व की पूर्ति की जाए। पूंजीगत माल की अनुमति कृषि उत्पादों और उनके मूल्य संवर्धन असंगतियों के निर्यातों के लिए 0 प्रतिशत शुल्क पर होगी।

तथापि 100 करोड़ या इससे अधिक के लागत बीमा भाड़ा मूल्य सहित ई पी सी जी लाइसेंस होने पर निर्यात दायित्व 12 वर्षों से अधिक की अवधि में पूरा करना अपेक्षित होगा।

यदि ईपीसीजी स्कीम के तहत आयातों पर सी वी डी नकद रूप में अदा किया गया है तो, सी वी डी बचाएँ गए निवल शुल्क के लिए नहीं लिया जाएगा बशर्ते कि इसे सेन्चेट न किया गया हो।

पूंजीगत माल में स्पेयर्स, नवकृत स्पेयर्स सहित जिंक्स, फिक्चर, डाइज और माउल्ड्स शामिल होंगे। लाइसेंसधारक द्वारा पूंजीगत वस्तुओं के एसेम्बल या विनिर्माण हेतु ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के हिस्से-पुर्जों के आयात के लिए ई पी सी जी लाइसेंस भी जारी किया जा सकता है।

ईपीसीजी स्कीम के अधीन 10 वर्ष तक का पुराना पूंजीगत माल भी आयात किया जा सकता है।

मौजूदा प्लान्ट और मशीनरी के लिए स्पेयर्स (कार्यरत दशा में वापिस लाए गए/नवकृत स्पेयर्स सहित) टूल्स रिफ्रैक्ट्रीज़, कैटालिस्ट और कन्ज्यूमेबल भी ई पी सी जी स्कीम के तहत आयात किए जा सकते हैं तथापि मोटर कारों, खेल कूद के लिए उपयोगी वाहनों/बहुदेशीय वाहनों के आयात की अनुमति केवल होटलों, टूर एजेंटों, टूर प्रचालकों अथवा टूर परिवहन प्रचालकों को होगी जिनका चालू और पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में कुल विदेशी मुद्रा अर्जन 1.5 करोड़ रुपए हो। तथापि मोटर कारों, खेल कूद के लिए उपयोगी वाहनों/बहुदेशीय वाहनों के पुर्जों जैसे कि चैसिस इत्यादि ईपीसीजी स्कीम के तहत आयात नहीं किए जा सकते।

- 5.1क मौजूदा प्लान्ट और मशीनरी के लिए स्पेयर्स भी ई पी सी जी स्कीम के तहत आयात किए जा सकते हैं बशर्ते कि लाइसेंस जारी होने की तिथि से 8 वर्षों के ऊपर की अवधि में निर्यात दायित्व बचाए गए शुल्क के 8 गुणा के बराबर हो।
- परियोजनाओं के लिए ईपीसीजी 5.1ख परियोजनाओं को आपूर्ति के लिए पूंजीगत माल के आयात के लिए ईपीसीजी लाइसेंस भी जारी किया जा सकता है जो कि सीमाशुल्क छूट प्राप्त अधिसूचना सं. 21/2002 दिनांक 01.03.2002 के क्रम.सं.441 के तहत केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमाशुल्क बोर्ड द्वारा अधिसूचित हैं जिसमें आयातों पर मूल सीमाशुल्क 16 प्रतिशत की सी वी डी के साथ 10 प्रतिशत है।
- ऐसे ईपीसीजी लाइसेंसों के लिए निर्यात दायित्व बचाए गए शुल्क का आठ गुणा होगा। बचाया गया शुल्क उपर्युक्त सीमाशुल्क अधिसूचना के तहत प्रभावी शुल्क और ईपीसीजी स्कीम के तहत रियायती शुल्क के बीच का अन्तर होगा।
- पात्रता 5.2 इस स्कीम के अंतर्गत सहायक विनिर्माता(ओं) सहित अथवा उनके बिना विनिर्माता निर्यातक/विक्रेताओं, सहायक विनिर्माता(ओं) से जुड़े व्यापारी निर्यातक और सेवा प्रदायक पूंजीगत माल का आयात करने के पात्र हैं।
- पूंजीगत माल के आयात की शर्त 5.3 पूंजीगत माल का आयात, निर्यात दायित्व की पूर्ति तक वास्तविक उपयोक्ता शर्त के अधीन होगा।
- निर्यात दायित्व 5.4 स्कीम के अन्तर्गत निर्यात दायित्व पूरा करने के लिए निम्नलिखित शर्तें लागू होंगी:-

- (1) स्कीम के अन्तर्गत आयातित पूंजीगत वस्तुओं के उपयोग द्वारा विनिर्मित या उत्पादित ऐसी वस्तुओं के निर्यात द्वारा निर्यात दायित्व पूरा किया जाएगा। उन्हीं वस्तुओं के निर्यात द्वारा भी, जिसके लिए ई पी सी जी लाइसेंस प्राप्त किया गया है निर्यात दायित्व भी पूरा किया जा सकता है जिन्हें लाइसेंस धारक/उल्लिखित सहायक विनिर्माता(ओं) की विभिन्न विनिर्माण यूनिटों से प्राप्त, विनिर्मित अथवा उत्पादित किया गया हो।

जब पूंजीगत माल पूर्व/पश्च उत्पादन के लिए आयात किए गए हों और लाइसेंस स्पेयर्स के आयात के लिए लिया गया है तो लाइसेंस धारक उस प्लान्ट/प्रोजेक्ट से विनिर्मित उत्पादों के निर्यात द्वारा निर्यात दायित्व पूरा करेगा कि जिससे पूर्व/पश्च उत्पादन पूंजीगत माल/स्पेयर्स संबंधित है ईपीसीजी लाइसेंसधारक द्वारा दी गई सेवाओं अथवा विनिर्मित उत्पादों के लिए भंडारण और वितरण सुविधाएँ उपलब्ध करने के लिए पूंजीगत माल के आयात की अनुमति ईपीसीजी लाइसेंस के तहत होगी। इस योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व विगत तीन लाइसेंसिंग वर्षों में उसके द्वारा प्राप्त किए गए उसी उत्पाद और समान उत्पाद प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में बताई गई श्रेणियों को छोड़कर, के निर्यातों के औसत स्तर से ज्यादा होगा। विकल्प रूप से, ई पी सी जी लाइसेंस धारक द्वारा उसी फर्म/कम्पनी में विनिर्मित या प्राप्त अन्य मालों/सेवाओं के निर्यातों द्वारा भी निर्यात दायित्व पूरा किया जा सकेगा। तथापि, ऐसे मामलों में, ई पी सी जी स्कीम के तहत लगाया गया अतिरिक्त निर्यात दायित्व पिछले तीन वर्षों में यूनिट/कम्पनी/समूह कम्पनी/प्रबन्धित होटल द्वारा वैकल्पिक उत्पादों/सेवाओं का किए गए औसत निर्यातों से जहाँ तक कि उन मामलों में जहाँ प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 5.7.6 में दिए गए वैकल्पिक उत्पाद(i)/सेवा (i) के लिए औसत में छूट है।

शेष निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए लाइसेंस धारक द्वारा पूरे किए जाने वाले बढ़ रहे निर्यातों में निर्यातों की वास्तविक उत्पाद/सेवा और वैकल्पिक उत्पाद (i)/सेवा (i) का कोई भी संयोजन हो सकता है। माल का निर्यातक सेवाओं के निर्यात अथवा विलोमतः निर्यात दायित्व पुनः नियत करने का विकल्प चुन सकता है लाइसेंसधारक स्कीम के तहत शेष निर्यात दायित्व के अनुपात में लागत बीमा भाड़ा मूल्य के लिए बचाई गई शुल्क राशि के 8 गुणा पर आधारित शेष निर्यात दायित्व को पुनः नियत करने के लिए विकल्प चुन सकता है। निर्यात दायित्व के पुनः निर्धारण के लिए दिशा निर्देश प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 5.19 में दी गई है।

उपर्युक्त सुविधाएँ केवल विनिर्माता निर्यातकों/सेवा प्रदायकों को सभी लाइसेंसों पर उपलब्ध होंगी जहाँ बढ़ाई गई निर्यात दायित्व अवधि सहित निर्यात दायित्व अवधि आवेदन की तारीख पर वैध है। इस संबंध में एकान्तर मद और/या बचाई गई शुल्क राशि पर आधारित निर्यात दायित्व के पुनः निर्धारण के लिए आवेदन प्रस्तुत करने पर अथवा उसके बाद किए गए निर्यातों को निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए माना जाएगा।

(2) इस स्कीम के अधीन प्राप्त किए गए निर्यात दायित्व आयातक द्वारा अग्रिम लाइसेंस, डी एफ आर सी, डी ई पी बी या ड्राबैक योजना के अधीन समान उत्पाद के लिए प्राप्त किए गए निर्यात दायित्व के अतिरिक्त होगा।

(3) निर्यात दायित्व डीटीए को आईटीए-1 की आपूर्ति द्वारा भी पूरा किया जा सकता है बशर्ते कि वसूली मुक्त विदेशी मुद्रा में हो।

(4) निर्यात वास्तविक निर्यात होंगे। तथापि नीति के पैराग्राफ 8.2 (क), (ख), (घ), (च) (छ) और (ज) में यथाउल्लिखित मान्य निर्यात भी नीति के पैरा 8.3 के तहत उपलब्ध सामान्य लाभों के साथ निर्यात दायित्व को पूरा करने के लिए माने जाएंगे।

आर एण्ड डी सेवाओं के लिए प्राप्त मुक्त रूप से परिवर्तनीय मुद्रा और विदेशी मुद्रा में प्राप्त रायल्टी भुगतान भी ईपीसीजी स्कीम के तहत वसूली के लिए माने जाएंगे। एग्जिम नीति के पैरा 9.47 (4) के संबंध में, पतन निर्वहन सेवाओं के लिए रूपए के रूप में प्राप्त भुगतान भी, स्कीम के तहत निर्यात दायित्व पूर्ति के लिए माना जाएगा।

बीआईएफआर यूनिटों के लिए शर्त	5.5.1	<p>बी आई एफ आर के साथ पंजीकृत कोई फर्म/कम्पनी या यूनिट खरीदने वाली कोई फर्म/कम्पनी, जो कि बी आई एफ आर के अधीन है, को ऑपरेटिंग एजेन्सी द्वारा तैयार एवं बी आई एफ आर द्वारा अनुमोदित पुनः स्थापना पैकेज के अनुसार निर्यात दायित्व बढ़ाने की अनुमति होगी। तथापि, ऐसे मामलों में, जहाँ पुनः स्थापना पैकेज में निर्यात दायित्व विस्तार की अवधि का उल्लेख न हो, वहाँ निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए मामले के गुणावगुण के आधार पर लाइसेंस जारी करने की तारीख से 12 वर्षों की समयावधि अनुमत होगी।</p> <p>इसी प्रकार, लघु एस एस आई इकाईयाँ भी संबंधित राज्य सरकार की पुनः स्थापना योजना के अनुसार ऐसी ही सुविधा के लिए हकदार होगी। तथापि, ऐसे मामलों में, जहाँ राज्य पुनः स्थापना योजना में निर्यात दायित्व विस्तार अवधि निर्दिष्ट नहीं की गई वहाँ निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए मामले के गुणों पर लाइसेंस जारी करने की तारीख से 12 वर्षों की समयावधि अनुमत होगी।</p>
एग्रो इकाईयों के लिए ईपीसीजी	5.5.2	<p>कृषि निर्यात क्षेत्रों में कृषि इकाईयों को जारी ई पी सी जी लाइसेंसों के मामले में, निर्यात दायित्व की पूर्ति के लिए लाइसेंस को जारी करने की तारीख से 12 वर्षों की अवधि अनुमत होगा।</p> <p>कृषि निर्यात क्षेत्रों में कृषि इकाईयों को कृषि निर्यात क्षेत्र के भीतर ईपीसीजी के तहत आयातित पूंजीगत माल (i) के स्थानान्तरण की सुविधा भी होगी।</p> <p>बैंक गारण्टी के संबंध में विधिक वचनवद्धता/बंध पत्र ईपीसीजी लाइसेंस के लिए दिया जा सकता है जो कि कृषि निर्यात क्षेत्रों में इकाईयों को दिया गया है। वशर्त कि ईपीसीजी लाइसेंस परिशिष्ट 15 में अधिसूचित मुख्य कृषि उत्पाद (i) अथवा उनकी मूल्य संवर्धन वस्तुओं के निर्यात के लिए लिया गया है।</p>
स्वदेशी रूप से पूंजीगत माल को प्राप्त करना और घरेलू आपूर्तिकर्ता को लाभ	5.6	<p>ई पी सी जी लाइसेंस धारक व्यक्ति पूंजीगत वस्तुएं आयात करने के बजाए इन्हें घरेलू निर्माता से प्राप्त कर सकता है। ई पी सी जी लाइसेंसधारक को पूंजीगत वस्तुओं की आपूर्ति करने वाला घरेलू विनिर्माता नीति के पैरा 8.3 के तहत मान्य निर्यात लाभ पाने का पात्र होगा।</p>

- घरेलू आपूर्तिकर्ता 5.7 ई पी सी जी लाइसेंस धारक और घरेलू विनिर्माता के बीच ऐसे वस्तुओं की प्राप्ति के लिए हुए करार के मामले में, घरेलू निर्माता उक्त पूंजीगत वस्तुओं के विनिर्माण हेतु आवश्यक संघटकों के आयात हेतु स्कीम के तहत अग्रिम लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकता है।
- घरेलू विनिर्माता ई पी सी जी लाइसेंस धारक को पूंजीगत माल की आपूर्ति के बाद संघटकों की प्रतिपूर्ति भी कर सकता है।
- निर्यात दायित्व का निर्धारण 5.7क सीधे आयात के मामले में ई पी सी जी लाइसेंस के संबंध में निर्यात दायित्व को वास्तव में आयातित पूंजीगत माल (इसमें स्पेयर्स, जिग्स, फिक्चर्स, डाइज और मोल्ड्स शामिल हैं) के लागत-बीमा-भाड़ा मूल्य पर बचाये गये शुल्क के अनुसार होगा। घरेलू प्राप्ति के मामले में ई पी सी जी लाइसेंस के संबंध में निर्यात दायित्व को पूंजीगत माल (इसमें स्पेयर्स, जिग्स, फिक्चर्स, डाइज और मोल्ड्स शामिल हैं) के रेल पर्यन्त निःशुल्क मूल्य पर बचाये गये केन्द्रीय सीमा शुल्क के अनुसार होगा।
- 5.8 कृषि निर्यात क्षेत्रों में सेवा प्रदाताओं को उपलब्ध करवाए गए कृषि निर्यात क्षेत्रों के भीतर पूंजीगत माल को हटाने या दूसरी जगह ले जाने की सुविधा होगी बशर्ते कि वे ऐसे कार्यकलापों का सही रिकार्ड रखेंगे। तथापि लाइसेंसधारक द्वारा ऐसे उपकरण बेचे या ठेके पर नहीं किए जाएंगे।
- ईपीसीजी के तहत औसत निर्यातों का रख रखाव 5.9 पैरा 5.4 (झ) की शर्तों के अनुसार, ईपीसीजी लाइसेंसधारक को निर्यात दायित्व की सम्पूर्ण अवधि के दौरान प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दी गई छूट प्राप्त श्रेणियों को छोड़ कर उसी अथवा समान उत्पादों के लिए पिछले तीन लाइसेंसिंग वर्षों में निर्यातों के औसत के बराबर निर्यातों के औसत स्तर को बनाए रखना होगा।
- उपर्युक्त के बावजूद लाइसेंस धारक किसी विशेष वर्ष (i) में औसत निर्यातों का कम से कम 75 प्रतिशत तक बनाए रखेंगे बशर्ते कि यह अन्य वर्ष (i) में औसत पूरा करने के लिए अतिरिक्त निर्यातों द्वारा पूरा किया गया हो।
- मौजूदा ईपीसीजी मशीनरी का तकनीकी उन्नयन 5.10 ईपीसीजी लाइसेंस धारक ईपीसीजी लाइसेंस के तहत आयातित मौजूदा पूंजीगत माल के तकनीकी उन्नयन का चुनाव कर सकता है।
- मौजूदा पूंजीगत माल के तकनीकी उन्नयन को संचालित करने की शर्त निम्नानुसार है:-

- (1) ईपीसीजी के तहत आयातित मौजूदा पूंजीगत माल के तकनीकी उन्नयन के लिए आवेदन करने के लिए न्यूनतम समयावधि लाइसेंस जारी करने की तारीख से 5 वर्ष है।
- (2) पुराने पूंजीगत माल के तहत किए गए न्यूनतम निर्यात पहले ईपीसीजी लाइसेंस पर लगाए गए कुल निर्यात दायित्व का 40 प्रतिशत होना चाहिए।
- (3) निर्यात दायित्व को इस प्रकार पुनः निर्धारित किया जाएगा कि पूंजीगत माल दोनों के लिए निर्धारित कुल निर्यात दायित्व पूंजीगत माल दोनों पर बचाए गए शुल्क की कुल राशि का 6 गुणा होगा।
- (4) पूंजीगत माल की पुनः स्थापना संचालित करने की प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के पैरा 5.20 में दी गई है।

अध्याय - छः

**निर्यात अभिमुख यूनिटें (ई ओ यू) इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क
(ई एच टी पी) साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी)
और बायो टेक्नोलोजी पार्क (बी टी पी)**

- पात्रता 6.1 नीति के अनुसार (डी टी ए में अनुमत बिक्री को छोड़कर) अपने सारे उत्पादन और सेवाओं को निर्यात करने का दायित्व लेने वाली यूनिटें निर्यात अभिमुख यूनिट (ई. ओ. यू.) स्कीम, इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क (ई एच टी पी) योजना या बायो टेक्नोलोजी पार्क (बी टी पी) स्कीम, साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क (एस टी पी) योजना के अंतर्गत स्थापित की जा सकती हैं तथा ऐसी यूनिटें माल के निर्माण सहित मरम्मत, री मेकिंग, री कंडीशनिंग, री-इन्जीनियरिंग और सेवा प्रदान करने में लगी हो सकती हैं। तथापि इन योजनाओं के तहत व्यापारी यूनिट के लिए अनुमति नहीं होगी।
- माल का निर्यात तथा आयात 6.2 (क) ई ओ यू/एस टी पी/बी टी पी यूनिट सभी वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर सकती है सिवाय उन मदों के जो आई टी सी (एच एस) में निषिद्ध हैं। विशेष रसायन, जैविक, उपकरण और तकनीकियों (एस सी ओ एम ई टी) का निर्यात आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित शर्तों के पूरा होने पर किया जायेगा बशर्ते कि ये आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित शर्तें पूरी होती हों।
- (ख) एक निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी यूनिट उससे संबंधित गतिविधियों के लिए अपेक्षित नीति में यथा परिभाषित पूंजीगत माल सहित सभी प्रकार की वस्तुओं का बिना शुल्क दिए आयात कर सकती है बशर्ते कि ये आई टी सी (एच एस) में आयात की निषिद्ध मद न हो किसी अन्य कानून के तहत आयात लिए अनुमति दी जाएगी। यूनिटों को, ग्राहकों से ऋण पर पूंजीगत वस्तुओं सहित, मुफ्त में या स्वीकृति कार्यकलापों के लिए अपेक्षित वस्तुओं के आयात की भी अनुमति होगी। पूंजीगत माल का आयात स्वप्रमाणन आधार पर होगा।
- (ग) निर्यात अभिमुख विनिर्माण यूनिटों पर राज्य व्यापार व्यवस्था लागू नहीं होगी।
- (घ) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी में साफ्टवेयर एककों द्वारा प्रयोग के लिए केन्द्रीय सुविधा स्थापित करने हेतु कुछ विशिष्टीकृत

वस्तुओं का शुल्क मुक्त रूप से आयात कर सकती हैं या डीटीए से प्राप्त कर सकती है। सॉफ्टवेयर के निर्यात के लिए डीटीए की यूनिट द्वारा भी सॉफ्टवेयर विकास के लिए केन्द्रीय सुविधा ली जा सकती है। ये सॉफ्टवेयर एकक ई ओ यू/डी टी ए एकक हो सकते हैं, जो सॉफ्टवेयर के निर्यात की सुविधा का प्रयोग कर सकते हैं।

(ड.) कृषि, पशुपालन, जल कृषि पुष्प उत्पादन, बागवानी, मत्स्य पालन, अंगुरोत्पादन, मुर्गीपालन अथवा रेशम उत्पादन में संलग्न निर्यात अभिमुख यूनिटों को बाण्डेड क्षेत्र के बाहर प्रयोग के लिए केवल विशिष्ट माल को ले जाने की अनुमति दी जा सकती है।

(च) रत्न और आभूषण ई ओ यू यूनिटें नामित ऐजेंसियों से सोना/चाँदी/प्लेटिनम नामित ऐजेंसियों से सोना/चाँदी/प्लेटिनम प्राप्त कर रही यूनिटें सोना/चाँदी/प्लेटिनम आभूषणों का निर्यात रिलीज की तारीख से 60 दिन के अन्दर कर देंगी। हालाँकि यह नामित ऐजेंसियों से कीमती पत्थरों के एकमुश्त खरीद पर लागू नहीं होगा।

(छ) सेवा यूनिटों के अतिरिक्त ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट भारतीय रिजर्व बैंक की क्लियरेंस, यदि कोई हो, के अधीन राज्य ऋण के पुनः भुगतान/क्रेता के एस्करो रुपया लेखा के प्रति भारतीय रुपयों में रुस संघ को निर्यात कर सकती है।

(ज) यूनिटों द्वारा विनिर्मित माल के लिए आवश्यक स्पेयर्स और उपभोग्य की खरीद और आपूर्ति, निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 1.5 प्रतिशत तक के माल के सा निर्यात की अनुमति होगी। तथापि यह रियायती दर डी टी ए बिक्री अथवा आयकर छूट के लिए एन एफ ई गणना में नहीं गिना जाएगा।

पुराना पूंजीगत माल 6.3

पुराना पूंजीगत माल का बिना किसी आयु सीमा के शुल्क मुक्त आयात किया जा सकता है।

पूंजीगत माल के पट्टे 6.4

पार्टियों के बीच में हुई पक्की संविदा के आधार पर कोई निर्यात अभिमुख यूनिट/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी यूनिट घरेलू विदेशी पट्टे वाली कंपनी से बिना सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क का भुगतान किए पूंजीगत माल उठा सकती है। ऐसे मामले में घरेलू विदेशी पट्टे वाली कंपनी तथा निर्यात अभिमुख यूनिट/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/ बी टी पी यूनिट शुल्क मुक्त पूंजीगत माल आयात करने/खरीदने के लिए संयुक्त रूप से आयात दस्तावेज प्रस्तुत करेगी।

सकल विदेशी मुद्रा अर्जन (एन एफ ई) 6.5 ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी यूनिटें एक सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होंगी। शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जित (एन एफ ई) उत्पादन प्रारम्भ होने से पांच वर्षों की अवधि के लिए संघटित रूप से गिना जाएगा।

अनुज्ञा पत्र/आशय पत्र और विधिक वचनबद्धता 6.6 (क) अनुमोदन हो जाने पर, विकास आयुक्त/नामित अधिकारी द्वारा ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को अनुमति पत्र (एल ओ पी)/आशय पत्र (एल ओ आई) जारी करेगा। एल ओ पी/एल ओ आई का आरम्भ में वैधता अवधि तीन वर्ष होगी। जब से यूनिट ने उत्पादन आरम्भ किया होगा। इसकी वैधता अवधि को सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रारम्भिक वैधता की अवधि से आगे 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। तथापि, छः वर्ष से अधिक के विस्तार के प्रस्ताव पर विशेष परिस्थितियों में अनुमोदन बोर्ड द्वारा मामला दर मामला आधार पर विचार किया जाएगा। एक बार यूनिट ने उत्पादन आरम्भ कर दिया, तो इसकी गतिविधियों के लिए जारी किए गए अनुमति पत्र आशय पत्र 5 वर्ष की अवधि के लिए वैध होंगे। इस अवधि को विकास आयुक्त द्वारा, एक बार में 5 वर्ष की अवधि के लिए आगे बढ़ाया जा सकता है।

(ख) सम्बन्धित प्राधिकारी द्वारा ई ओ यू/ई पी जैड/ई एच टी पी/एस टी पी/ बी टी पी यूनिटों को जारी एल ओ पी/एल ओ आई को सभी प्रयोजन के लिए लाइसेंस माना जाएगा।

(ग) यूनिट संबंधित विकास आयुक्त को एक विधिक वचनबद्धता प्रस्तुत करेगी। सकारात्मक शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन की शर्त को अथवा एल ओ पी/एल ओ आई/आई एल/एल यू टी की शर्तों को न पूरा कर सकने पर वह विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 और किसी अन्य कानून के तहत नियम तथा आदेश जो बिना पूर्वाग्रह के बने हों, के अधीन दण्ड की भागी होगी और वह एकल ओ पी/एल ओ आई/आई एल रद्द अथवा मंसूख हो जाएगा।

(घ) जिन परियोजनाओं इमारत, की संयंत्र और मशीनरी पर 1 करोड़ रुपया न्यूनतम निवेश न हो उनको ई.ओ.यू. स्कीम के अन्तर्गत स्थापना के लिए विचार किया जाएगा। यह, हालांकि, मौजूदा यूनिटें और ई एच टी पी/एसटीपी/बीटीपी हैण्डिक्राफ्ट/ कृषि/पुष्प बागवानी/जल कृषि/ पुशपालन सूचना तकनीकी सेवाएं और बीओए द्वारा निर्धारित ऐसे अन्य क्षेत्रों में लागू नहीं होगा। क्षेत्रवार निवेश मानदण्ड बी ओ ए द्वारा निर्धारित होगा।

आवेदन और
अनुमोदन

6.7 ई ओ यू योजना के तहत यूनिटों की स्थापना के लिए आवेदनों पर सेवा क्षेत्र (आर एण्ड डी, साफ्टवेयर और सूचना प्रौद्योगिकी संबंध सेवाओं अथवा बी ओ ए द्वारा प्रत्यायोजित अन्य सेवा गतिविधियों को छोड़कर) की यूनिटों की स्थापना के लिए प्रस्तावों को छोड़कर, यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा 15 दिनों के भीतर मंजूरी/नामंजूरी दी जा सकती है जो प्रक्रिया पुस्तक खण्ड-1 में उल्लिखित शर्तों को पूरा करती हो। अथवा रद्द किया जायेगा।

(ख) अन्य मामलों में इस उद्देश्य के लिए गठित अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में निर्दिष्ट के अनुसार मंजूरी दी जाएगी।

(ग) औद्योगिक लाइसेंस की आवश्यकता वाले ईओयू की स्थापना के प्रस्ताव का अनुमोदन, अनुमोदन बोर्ड और औद्योगिक नीति और संवर्धन विभाग द्वारा प्रस्ताव के निपटान के बाद 45 दिन के अन्दर विकास आयुक्त द्वारा किया जा सकता है।

तैयार
उत्पाद/अवशेष/
स्क्रेप/शेष और उप-
उत्पाद की घरेलू
टैरिफ क्षेत्र (डी टी
ए) में बिक्री

6.8 निर्यात अभिमुख यूनिटों/इलैक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/साफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी यूनिटों का सारा उत्पादन निम्निलिखित के अधीन निर्यात किया जाएगा:-

(क) रत्न और आभूषण यूनिटों को छोड़कर यूनिट निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत तक माल का विक्रय कर सकता है जो लागू शुल्क भुगतान और नीति में निर्धारित न्यूनतम अर्जित निवल विदेशी मुद्रा को पूरा करने के अधीन होगी। नीति के पैरा तहत प्राइवेट बांडिड गोदाम की बिक्री को भी ई ओ यू/ई पी जैड यूनिटों द्वारा निर्यात के पोतपर्यन्त निःशुल्क मूल्य को निश्चित करने के प्रयोजन के लिए ध्यान में रखा जाएगा। मोटर कार, अल्कोहल युक्त शराब, पुस्तकें और चाय (इन्सटैंट टी को छोड़कर) और पुस्तकें या पैकेजिंग/लेबलिंग/सैग्रीगेशन/रेफ्रीजरेशन यूनिट कम्पैक्टिंग/माइक्रोनाइजेशन/पल्वेराइजेशन/ग्रेन्यूलेशन/मोनो-हाइड्रेट रूप के रसायन से एनहाइड्रस रूप में परिवर्तन अथवा विलोमत और ऐसी अन्य मदों जोकि समय-समय पर अधिसूचित की जाएगी, के मामले में रियायती शुल्क पर कोई डी टी ए बिक्री की अनुमति नहीं दी जाएगी।

एस ई जेड में यूनिट को की गई बिक्री भी ई ओ यू द्वारा निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य को निर्धारित करने के लिए ध्यान में रखी जाएगी। बशर्ते कि इन बिक्रियों हेतु किया गया भुगतान ई ई एफ सी एकाउण्ट से किया गया हो। डी टी ए को की गई बिक्री भी फार्मास्यूटिकल उत्पादों (थोक दवाइयों समेत) के पंजीकरण की अपरिहार्य आवश्यकता के मद्दे होगी।

(ख) सेवा के लिए, साफ्टवेयर यूनिटों सहित, डी टी ए में किसी भी रूप में बिक्री, आनलाइन डाटा संचार सहित निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 50 प्रतिशत / अर्जित विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत तक की भी अनुमति होगी, जहाँ ऐसी सेवाओं का भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।

(ग) रत्न और आभूषण यूनिट डी टी ए में पूर्व वर्ष के निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 10 प्रतिशत तक बेच सकती है बशर्ते कि नीति में यथानिर्धारित अर्जित निवल विदेशी मुद्रा को पूरा कर लिया गया है। सादे आभूषण की बिक्री के संबंध में, प्राप्तकर्ता नामित एंजेलियो से बिक्री पर यथा लागू शुल्क की रियायती दरों का भुगतान करेगा। रत्न जड़ित आभूषण के संबंध में, यथा लागू शुल्क का भुगतान करना होगा।

(घ) एल ओ पी में विशेष रूप से निषिद्ध न हुआ तो, सीमाशुल्क प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति से पैराग्राफ 6.8 (क) के तहत यथा लागू शुल्कों के भुगतान पर, डी टी ए में रिजेक्ट्स की बिक्री की जा सकती है। ऐसी बिक्री डी टी ए बिक्री हकदारी के मद्दे गिनी जाएगी। निर्यातों के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य के 5 प्रतिशत तक रिजेक्ट्स की बिक्री पर एन एफ ई प्राप्त करने की शर्त नहीं होगी।

(ङ) उत्पादन प्रक्रिया या तत्सम्बन्धी प्रक्रिया से निकलने वाले स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेष का यथा लागू रियायती शुल्क का भुगतान करने पर डी टी ए में बिक्री अथवा निर्यात शुल्क मुक्त स्कीम के तहत अधिसूचित मानक निविष्टि उत्पादन मानदण्ड के अनुसार किया जा सकता है जो निर्यात के पोत पर्यन्त निःशुल्क मूल्य का 50 प्रतिशत की समग्र सीमा के भीतर होगा। लेकिन ऐसी बिक्री न्यूनतम निवल विदेशी मुद्रा अर्जन की प्राप्ति के अधीन नहीं होगी। उन मर्दों के संबंध में जो मानदण्ड में शामिल नहीं हैं, विकास आयुक्त आंकड़ों के आधार पर छः माह की अवधि और छः माह के भीतर की अवधि के लिए तदर्थ मानदण्ड निर्धारित कर सकता है, उसे अनुमोदन बोर्ड द्वारा मानदण्ड निर्धारित करवाने होंगे। यूनिटों द्वारा जिन वेस्ट/स्क्रेप/अवशेष की बिक्री डी टी ए बिक्री की पात्रता या डी टी ए बिक्री पात्रता से बाहर बिक्री की अनुमति नहीं है उन पर शुल्क का पूर्ण भुगतान करना होगा। स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेष का भी निर्यात किया जा सकता है।

(च) यदि ऐसे स्क्रेप/अवशिष्ट/अवशेषों को सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से नष्ट किया जाता है तो उन पर कोई शुल्क/कर नहीं लगेगा।

(छ) इलेक्ट्रॉनिक्स हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर निर्माण करने वाली यूनिटों के मामले में, निवल विदेशी मुद्रा और डी टी ए बिक्री हकदारी, हार्डवेयर और साफ्टवेयर के लिए अलग से निर्धारित की जाएगी।

घरेलू टैरिफ क्षेत्र
में अन्य आपूर्तियां

6.9

अर्जित निवल विदेशी मुद्रा पूरा करने के लिए घरेलू टैरिफ क्षेत्र में ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों से निम्नलिखित आपूर्तियों की गणना की जाएगी:-

- (क) वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम लाइसेंस/शुल्क छूट के तहत डी एफ आर सी/विमुक्ति योजना/ई पी सी जी स्कीम के धारकों के संबंध में डी टी ए में की गई आपूर्तियां;
- (ख) डीटीए में क्रेता के एक्सचेंज अर्नस फॉरेन करंसी (ई ई एफ सी) खाते से भुगतान के प्रति डी टी ए में और विदेशों से विदेशी मुद्रा प्रेषण के प्रति की गई आपूर्तियां।
- (ग) अन्य निर्यातानुमुख इकाई/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बायोटेक्नोलोजी पार्क/एस ई जेड को आपूर्ति इन यूनिटों द्वारा ऐसे माल की खरीद के लिए अनुमति नीति के पैराग्राफ 6.2 के अन्तर्गत की जायेगी।
- (घ) नीति के और/या सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 के तहत स्थापित बांडेड गोदाम विशेष आर्थिक क्षेत्र की यूनिटों में की गई आपूर्तियां, जहाँ भुगतान विदेशी मुद्रा में प्राप्त होता है।
- (ङ.) माल और सेवाओं की आपूर्ति ऐसे संगठनों जो वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य छूट अधिसूचना के अनुसार शुल्क मुक्त आयात के हकदार हैं।
- (च) निर्यात से संबंधित सेवाओं की आपूर्ति (सेवा यूनिटों द्वारा) मुक्त विदेशी मुद्रा के लिए अथवा ऐसी सेवाओं के लिए जिनका भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा के बदले भारतीय रुपये में किया गया हो।
- (छ) सूचना तकनीकी समझौता (आईटीए-1) मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क टेलिकाम/इलेक्ट्रॉनिक मदों की आपूर्ति।

- अन्यों के माध्यम से निर्यात 6.10 एक ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट, अपने द्वारा विकसित विनिर्मित माल/साफ्टवेयर का निर्यात प्रक्रिया पुस्तक के पैरा-6.19 में उल्लिखित शर्तों के अनुसार दूसरे निर्यातक अथवा किसी अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जेड यूनिट के माध्यम से कर सकती है।
-
- डी.टी.ए. से आपूर्तियों हेतु हकदारी 6.11 (क) निर्यातोन्मुख/इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नोलोजी पार्क/सॉफ्टवेयर टेक्नोलोजी पार्क/बी टी पी की यूनिटों को घरेलू हकदारी टैरिफ क्षेत्र से की गई आपूर्तियों को “मान्य निर्यात” समझा जाएगा और डी टी ए आपूर्तिकर्ता निर्यात दायित्व, यदि कोई हो, के अलावा नीति के अध्याय 8 के अधीन संगत हकदारियों के लिए पात्र होगा। उपरोक्त के बावजूद, उपयुक्त डिसक्लेमर प्रस्तुत करने पर नीति के अध्याय 8 में विनिर्दिष्ट के अनुसार ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बी टी पी यूनिटें हकदारी प्राप्त करने के योग्य होंगी। मान्य निर्यात शुल्क वापसी का दावा करने के लिए जहाँ भी वापसी की सभी उद्योग दरें उपलब्ध नहीं हैं, विकास आयुक्त द्वारा ब्रान्ड दरें निर्धारित करवाई जाएंगी।
- (ख) बहुमूल्य और अर्द्धबहुमूल्य पत्थर, कृत्रिम पत्थर और प्रसंस्कृत मोतियों का डी टी ए से ई ओ यू को आपूर्ति करने वाले प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मदों के लिए और दरों पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस प्राप्त करने के हकदार होंगे।
- (ग) इसके अलावा ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जेड यूनिट निम्नलिखित के लिए पात्र होंगे।
- (1) भारत में विनिर्मित माल पर केन्द्रीय बिक्री कर की प्रतिपूर्ति ;
 - (2) भारत में विनिर्मित वस्तुओं पर, डी टी ए से खरीदी गई वस्तुओं पर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के भुगतान से छूट।
 - (3) लाइसेंस शुद्ध नीलामी केन्द्रों से प्राप्त थोक चाय पर अदा किए गए केन्द्रीय उत्पाद शुल्क अतिरिक्त उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति।
 - (4) घरेलू तेल कंपनियों से प्राप्त ईंधन पर अदा शुल्क को समय-समय पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित शुल्क वापसी की दर से संबंधित क्षेत्र के विकास आयुक्त द्वारा ई ओ यू/ई पी जेड/ई एच टी पी/एस टी पी को लौटा दिया जाएगा।
 - (5) सेवा शुल्क के भुगतान से छूट
- (ख) डी टी ए से ई ओ यू एकको को बहुमूल्य और अर्द्ध बहुमूल्य पत्थरों, सिंथेटिक पत्थरों और संसाधित मोतियों के आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मदों के लिए दरों पर प्रतिपूर्ति लाइसेंस पाने के पात्र होंगे।

पैराग्राफ (1) और (2) के अधीन बताए गए लाभ उपलब्ध होंगे बशर्ते कि आपूर्ति किया गया माल भारत में विनिर्मित हो।

अन्य हकदारियाँ

6.12 ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों की अन्य हकदारियाँ निम्नलिखित है :

(क) आयकर अधिनियम की धारा 10क और 10ख के उपबन्धों के अनुसवार आयकर के भुगतान से छूट ।

(ख) लघु उद्योग क्षेत्र के लिए आरक्षित मदों के विनिर्माण के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग से छूट

(ग) आफशोर बैंकिंग यूनिट उन्हीं शर्तों पर ऋण की सुविधा देगा जो एस ई जेड की यूनिटों को उपलब्ध हैं ।

(घ) निर्यात आय को 12 महीनों के भीतर प्राप्त करना होगा ।

(ङ.) ई ई एफ सी खाते में 100 प्रतिशत निर्यात अर्जन की अनुमति होगी ।

(च) यूनिटों को आयात करते समय या डी टी ए में जाब कार्य करते समय बैंक गारन्टी प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं होगी, जिन मामलों में यूनिट का (1) कारोबार 5 करोड़ रुपये या उससे अधिक है (2) यूनिट कम से कम 3 वर्षों से मौजूद है और (3) यूनिट का साफ सुथरा ट्रैक रिकार्ड है ।

(छ) एस ई जेड यूनिटों की तरह हो आटोमैटिक रूट के जरिए 100 प्रतिशत एफ डी आई निवेश की अनुमति दी जाएगी ।

अन्तर यूनिट
हस्तांतरण

6.13 (क) एक निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी यूनिट से अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी/एस ई जेड यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण की अनुमति दी जाएगी।

(ख) सीमाशुल्क प्राधिकारी को पूर्व सूचना देकर संबंधित विकास आयुक्त की पूर्व अनुमति से पूंजीगत वस्तुओं को किसी अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी/एस ई जेड यूनिटों को हस्तांतरित या ऋण पर दिया जा सकता है ।

(ग) किसी एक यूनिट द्वारा किसी दूसरे ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को वस्तुओं की आपूर्ति, दूसरे यूनिट द्वारा डी टी ए बिक्री पर शुल्क के भुगतान के प्रयोजन के लिए दूसरे यूनिट के लिए आयातित वस्तुएँ मानी जाएंगी ।

उप-ठेके

6.14

(क)(1) ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट जिनमें रत्न और आभूषण यूनिटें शामिल है, सीमा शुल्क प्राधिकारियों की वार्षिक अनुमति के आधार पर डी टी ए में यूनिटों द्वारा फुटकर ठेके के आधार पर माल के रूप और किस्म में परिवर्तन करना भी शामिल है, का डी टी ए में उप ठेके पर उत्पादन प्रक्रिया कर सकती है।

(2) ये यूनिटें सीमा शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से डी टी ए में जॉब वर्क के उप ठेके के लिए मूल्य की शर्तों में पिछले वर्ष के कुल उत्पादन का 50 प्रतिशत तक भी उप ठेके पर दे सकते हैं।

(ख) (1) ई ओ यू यूनिटों को डीटीए निर्यातक के बदले में निर्यात हेतु जॉब वर्क की अनुमति दी जा सकती हैं बशर्ते माल को ई ओ यू यूनिटों से सीधे निर्यात किया जाए और निर्यात दस्तावेज डीटीए/ईओयू यूनिट के नाम में संयुक्त रूप से तैयार किया जाए। ऐसे निर्यात हेतु, शुल्क वापसी की ब्रांड दर के माध्यम से निविष्टियों पर अदा किए शुल्क को वापिस लेने के लिए डीटीए यूनिटें हकदार होंगी।

(2) जब वर्क के आधार पर विदेशी आपूर्तिकर्ता द्वारा ई ओ यू को दिए गए निर्यात आदेश को पूरा करने के लिए वस्तुओं का शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति नहीं होगी । इस शर्त के अधीन होगी कि कोई डी टी ए क्लीयरेंस न दी जाए ।

(3) यूनिट में रखे गये रिकार्ड के अनुसार अन्य ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/एस ई जैड/बी टी पी एककों के माध्यम से उत्पादन और उत्पादन प्रक्रिया दोनों के उपठेके की प्रक्रिया किसी सीमा के बिना शुरू कर सकते हैं ।

(4) विकास आयुक्त के अनुमोदन से विदेश में उत्पादन प्रक्रिया के भाग के रूप में उप ठेके की अनुमति दी जाएगी ।

(ग) जब वर्कर के कार्य स्थल में पैदा हुए स्क्रेप/वेस्ट/टूकड़ों को या तो जब वर्कर के कार्य स्थल से लागू शुल्क के भुगतान पर दिया जा सकता है या सीमा शुल्क/उत्पाद शुल्क प्राधिकारी की उपस्थिति में नष्ट किया जा सकता है या आपूर्तिकर्ता यूनिट को वापिस किया जा सकता है। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों को नष्ट करने की अनुमति नहीं होगी।

(घ) रत्न और आभूषण ई ओ यू इकाइयों द्वारा अन्य इ ओ यू/ एस ई जैड/ डीटीए ईकाइयों में उपठेका/ विनिमय प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) निर्दिष्ट प्रक्रिया के तहत किया जा सकता है।

प्रयोग न किए
गए माल की
बिक्री

6.15 क) यदि कोई निर्यातानुमुख यूनिट/ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी की यूनिट से आयातित या डी टी ए से प्राप्त किए गये माल और सेवाओं का उपयोग नहीं कर पाती है तो (1) यह अन्य ई ओ यू/एसइजैड/ इ एच टी पी / एस टी पी/बी टी पी इकाइयों को हस्तांतरित कर सकती है या (2) सीमाशुल्क प्राधिकारियों के अनुमोदन से आयात लाइसेंस सौंपकर और लागू शुल्कों का भुगतान करके, यदि आवश्यक हो डी टी ए में उनका निपटान या (3) निर्यात कर सकती है। एक ई ओ यू/ई एचटीपी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट से अन्य ऐसे यूनिटों को किए गये मालों का हस्तांतरण प्राप्त कर्ता इकाई के लिए आयात माना जाएगा।

(ख) पूंजीगत वस्तुएं और पुराने/अतिरिक्त कल पूर्ण का निर्यात या अन्य इ ओ यू / ई एच टी पी/ एस टी पी/बी टी पी/एस ई जैड इकाइयों को हस्तांतरण या लागू शुल्क के भुगतान के बाद डी टी ए में निपटान किया जा सकता है। डी टी ए में निपटान की स्थिति में यथा लागू मूल्यहास का लाभ लागू होगा। यदि पूंजीगत माल कच्चा माल, उपभोज्य कलपूर्ण, वनिर्मित माल, प्रसंसाधित या पैकिंग किया गया और स्क्रेप/वेस्ट/रैमनेन्ट्स/रद्द माल को सीमाशुल्क प्राधिकारियों को सूचित करने के बाद यूनिट के भीतर नष्ट करने पर या सीमाशुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से यूनिट के बाहर नष्ट करने पर कोई सीमा शुल्क नहीं लगेगा। सोना, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती और अर्द्ध कीमती पत्थरों पर उपर्युक्त विनष्टीकरण लागू नहीं होगा।

(ग) वस्त्र क्षेत्र के मामले में लागत बीमा भाड़ा मूल्य या आयात की मात्रा, जो भी कम हो, के 2 प्रतिशत तक बचे हुए माल/कपड़े का निपटान सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर अनुमत होगा बशर्ते केन्द्रीय उत्पाद/सीमा शुल्क अधिकारी यह प्रमाणित करें कि यह बचा हुआ माल है।

(घ) इस्तेमाल की गई पैकिंग सामग्री के निपटान की अनुमति सौदा मूल्य पर शुल्क का भुगतान करने पर दी जाएगी ।

रिकडिंशनिंग/मरम्मत और पुनः इंजिनियरिंग करना 6.16 निर्यातोन्मुख/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी क्षेत्र की यूनिटों को रिकडिंशनिंग, मरम्मत, पुनर्निर्माण, परीक्षण, कैलीब्रेशन, गुणवत्ता सुधार, प्रौद्योगिकी उन्नयन और पुनः इंजीनियरिंग जैसे कार्यों के लिए तथा विदेशी मुद्रा में निर्यातों के लिए अनुमोदन बोर्ड की स्वीकृति से स्थापित किया जा सकता है। ऐसे यूनिट उपयुक्त कार्यों के लिए किसी भी किस्म के माल का आयात कर सकते हैं। प्रक्रिया पुस्तक के पैरा 6.29 और नीति के पैराग्राफों 6.8, 6.9, 6.10, 6.13 व 6.14 के प्रावधान ऐसे कार्यकलापों पर लागू नहीं होंगे।

आयातित/स्वदेशी वस्तुओं का प्रतिस्थापन/मरम्मत 6.17 (क) प्रतिस्थापन/मरम्मत वस्तुओं के निर्यात के संबंधित नीति के सामान्य प्रावधान ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों पर भी एक समान लागू होंगे यद्यपि प्रावधान के तहत न आने वाले मामलों पर विकास आयुक्त द्वारा गुण-दोष आधार पर विचार किया जाएगा।

(ख) डी टी ए में बेची गई वस्तुएं और खराब पाई गई वस्तुओं को सम्बन्धित अधिकार क्षेत्र के सीमाशुल्क/उत्पाद प्राधिकारियों की सूचना में मरम्मत/ बदलने के लिए लाया जा सकता है।

(ग) आयात करने पर/स्वदेशी रूप से प्राप्त करने पर वस्तुएं अथवा उनके का हिस्से जो त्रुटिपूर्ण अथवा उपयोग हेतु अन्यथा अनुपयुक्त अथवा आयात के बाद क्षतिग्रस्त हो जाएं/लौटाए और प्रतिस्थापन प्राप्त किए जा सकते हैं अथवा नष्ट किए जा सकते हैं। प्रतिस्थापित करने के मामलों में वस्तुएं विदेशी संभरकों अथवा भारत में उनके अधिकृत संभरकों/स्वदेशी संभरकों से वापिस ली जा सकती है। तथापि कीमती और अर्द्धकीमती धातुओं पर विनष्टीकरण लागू नहीं होगा।

ईओयू योजना से बहिर्गमन 6.18 (क) विकास आयुक्त के अनुमोदन से निर्यात अभिमुख यूनिट इस योजना को छोड़ सकती हैं। उस समय लागू सीमा-शुल्क और उत्पाद शुल्क के भुगतान करने पर और बहिर्गमन से संबंधित निवर्तमान औद्योगिक नीति के तहत इस योजना को छोड़ा जा सकता है।

(ख) अगर यूनिट ने इस योजना के अन्तर्गत दायित्व को प्राप्त नहीं किया है तो योजना से बहिर्गमन, के समय उसे जुर्माना देना होगा।

(ग) रत्न व जेवरात यूनिटों द्वारा कार्य करना बन्द करने पर आभूषण के निर्माण के लिए उपलब्ध स्वर्ण व अन्य बहुमूल्य धातु

मिश्रधातु, रत्न व अन्य सामग्री, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (वाणिज्य विभाग) द्वारा नामित ऐंजसी को उनके द्वारा निर्धारित कीमत पर हस्तांतरित करनी पड़ेगी।

(घ) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-14झ में निर्दिष्ट के अनुसार मानक शर्तों और उस योजना के अधीन पात्रता संबंधी मानदण्डों को पूरा करने वाले निर्यातोन्मुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट को एक बार के विकल्प के रूप में मौजूद ई पी सी जी योजनाओं के तहत पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क को भुगतान करने पर विकास आयुक्त द्वारा योजना छोड़ने की अनुमति दी जा सकती है।

(ड.) ई ओ यू योजना को छोड़ने का प्रस्ताव करने वाले यूनिटों को सैद्धांतिक रूप से अनुमोदन प्राप्त करना होगा और किए गए आयात एवं निर्यात के ब्यौरे केन्द्रीय उत्पाद/सीमाशुल्क प्राधिकारी को प्रस्तुत करने होंगे। इसकी जाँच करने के पश्चात उक्त प्राधिकारी शुल्क के भुगतान का मूल्यांकन करेगा और यूनिट मूल्यांकित शुल्क का भुगतान करेगा तथा उत्पाद प्राधिकारी से बेबाकी प्रमाणपत्र प्राप्त करेगा, ऐसे सीमाशुल्क के भुगतान करने और अन्तिम डीबान्डिंग पत्र प्राप्त करने की अवधि के बीच यूनिट पूंजीगत वस्तुओं या निविष्टियों को प्राप्त करने के लिए किसी छूट को पाने का पात्र नहीं होगा। तथापि वे डी ई ई सी/डी ई पी बी/डी एफ आर सी/शुल्क वापसी का दावा कर सकते हैं।

(च) जिन मामलों में यूनिट ने लागू आयात शुल्क का भुगतान करने के पश्चात विदेश से या उत्पाद शुल्क का भुगतान करने के पश्चात् घरेलू बाजार से मशीनें खरीद कर प्रारम्भ में डी टी ए यूनिट स्थापित किया गया है, और जिसे बाद में ई ओ यू में परिवर्तित कर दिया गया है, ऐसे मामलों में डीबान्डिंग के पश्चात डी टी ए में ऐसी पूंजीगत वस्तुएँ तो जाने के लिए किसी शुल्क का भुगतान नहीं करना होगा। इसी प्रकार ई पी सी जी योजना के तहत यहाँ डी टी ए यूनिटों के रूप में पूंजीगत वस्तुओं का आयात किया है और ई पी सी जी योजना के अन्तर्गत निर्यात दायित्व को पूर्णतः पूरा करने के पश्चात और स्वयं को ई ओ यू में परिवर्तित करवाने पर यूनिट से डी टी ए ऐसी पूंजीगत वस्तुओं को ले जाते समय पूंजीगत वस्तुओं से सीमाशुल्क नहीं लिया जाएगा।

- परिवर्तन 6.19 (क) मौजूदा डी टी ए यूनिटें भी किसी निर्यात अभिमुख यूनिट/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिट में परिवर्तन के लिए आवेदन कर सकती है और पहले से स्थापित संयंत्र, मशीनरी और उपस्कर के लिए योजना के अन्तर्गत आयकर अधिनियम की धारा 10(ख) के तहत लाभ उपलब्ध होंगे।
- (ख) विद्यमान ई एच टी पी/एस टी पी यूनिटें, ई ओ यू यूनिट में परिवर्तन/समाहित होने के लिए अथवा विलोमतः आवेदन कर सकती है। ऐसे मामलों में यूनिटें बांड के अधीन होंगी तथा संबद्ध योजनाओं के तहत लागू ड्यूटी एवं टैक्स छूट का लाभ उठा सकती है।
- एन एफ ई की निगरानी 6.20 ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटों के कार्य निष्पादन की निगरानी एकक अनुमोदन समिति के द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित मार्ग निर्देशों के अनुसार निगरानी की जाएगी।
- प्रदर्शनी के माध्यम से निर्यात/निर्यात प्रोत्साहन यात्रा/विदेशी शो रूम के जरिए निर्यात/शुल्क मुक्त दुकानें 6.21 ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी/बी टी पी यूनिटें निम्नलिखित के हकदार होंगे:
- (1) विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में प्रदर्शन करने/शामिल होने के लिए वस्तुओं का निर्यात करना।
 - (2) स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनियम जेबरात, बहुमूल्य, अर्धबहुमूल्य पत्थर, माणिक व अन्य व्यक्तिगत सामान।
 - (3) विदेशों में स्थापित/अनुमोदित दुकानों में प्रदर्शन/विक्रय के लिए मालों का निर्यात।
 - (4) विदेशों में स्थापित/अनुमोदित दुकानों या उनके वितरकों/एजेंटों के शो रूम में प्रदर्शन/बिक्री हेतु निर्यात।
 - (5) अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों में शो रूम/खुदरा दुकानों की स्थापना।
- वैयक्तिक सामानों का आयात/विदेशी बांड पैसेन्जर सहित निर्यात पार्सल 6.22 रत्न और आभूषणों का आयात/निर्यात व्यक्तिगत रूप से सीमा शुल्क द्वारा निर्धारित प्रक्रिया नियमों के अधीन किया जा सकता है। तथापि, निर्यात आय को सामान्य बैंकिंग चैनलों के द्वारा प्राप्त किया जा सकेगा। रत्न और आभूषण ईकाई के अलावा अन्य यूनिटों के लिए आयात निर्यात व्यक्तिगत रूप से करने की अनुमति दी जाएगी बशर्ते वस्तुएं वाणिज्यिक मात्रा में हो,
- डाक/कोरियर द्वारा निर्यात/आयात 6.23 निःशुल्क नमूनों सहित अन्य मालों को सीमा शुल्क नियमों के अधीन हवाई जहाज या विदेश डाक खाना या कोरियर द्वारा निर्यात/आयात किया जा सकता है।

- | | | |
|--|------|--|
| ई ओ यू यूनिटों का प्रशासन/विकास आयुक्त को प्रदत्त शक्तियाँ | 6.24 | ई ओ यू यूनिटों के प्रशासन और विकास आयुक्त को प्रदत्त शक्तियाँ का ब्यौरा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में दिया गया है। |
| रुग्ण यूनिटों का पुनरुत्थान | 6.25 | उपयुक्त प्राधिकारी द्वारा यूनिट को रुग्ण घोषित करने पर अनुमोदन बोर्ड द्वारा यूनिट के पुनरुत्थान या अधिग्रहण के लिए विचार किया जा सकता है। |
| ई एच टी पी/एस टी पी के लिए अनुमोदन | 6.26 | ई एच टी पी/एस टी पी योजनाओं के अधीन यूनिटों के मामलों में इस अध्याय के संबंधित पैरा के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति के विकास आयुक्त के बजाए सूचना व प्रौद्योगिकी मंत्रालय के संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा नामित अधिकारी द्वारा और अनुमोदन बोर्ड के बजाए अंतर्मंत्रालय स्थायी समिति (आई एम एस सी) द्वारा दी जाएगी। |
| बी टी पी का अनुमोदन | 6.27 | जैव प्रौद्योगिकी पार्कों को जैव प्रौद्योगिकी विभाग की सिफारिशों पर विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित किया जाए। बी टी पी में यूनिटों के मामले में इस अध्याय के संबंधित उपबन्धों के अधीन आवश्यक अनुमोदन/अनुमति प्रौद्योगिकी विभाग के नामजद अधिकारी द्वारा दी जाएगी। |

अध्याय - 7

विशेष आर्थिक क्षेत्र

टिप्पणी: विशेष आर्थिक ज़ोन वे विकास को स्रोत है जो विनिर्माण कार्यकलापों को बढ़ावा दे सकते हैं। निर्यात में वृद्धि कर सकते हैं और रोजगार के अवसर पैदा कर सकता है। निजी क्षेत्र को एसईजेड के विकास के साथ सक्रिय रूप से संबंध किया गया है। एसईजेड के लिए विशेष राजकोषीय और विनियन्त्रक तन्त्र की आवश्यकता है ताकि स्टेट आफ द आर्ट बुनियादी सुविधाओं और सहायक सेवाओं प्रदान करने के लिए एक मुक्त संचालक तन्त्र विकसित किया जा सकता है। निकट भविष्य में पारित किया जाने वाला है एसईजेड के संबंध में प्रस्तावित विधेयक विकासकर्ता और सह विकासकर्ता की अवेधारणा, वास्तविक एसईजेड के प्रावधान, आपका और सीमाशुल्क अधिनियम के तहत वित्तीय रियायतें, आफसरों बैंकिंग यूनिटों के लिए प्रावधान शामिल किये जाएंगे। एसईजेड योजना के अन्तर्गत उपलब्ध सुविधाओं के संबंध में एक संक्षिप्त नोट नीचे दिया गया।

- पात्रता 7.1 (क) विशेष आर्थिक क्षेत्र एक खास तौर से शुल्क एवं सीमाशुल्क मुक्त क्षेत्र है और यह व्यापार कार्यकलापों तथा शुल्क और प्रशुल्क के प्रयोजनों के लिए एक विदेशी क्षेत्र है।
(ख) डी टी ए से एस ई जेड में जाने वाली वस्तुओं और सेवाओं को मान्य निर्यात माना जाएगा और एस ई जेड से डी टी ए में आने वाली वस्तुओं और सेवाओं को आयात की गई वस्तुएं माना जाएगा।
(ग) एस. ई. जेड. एककों की स्थापना वस्तुओं के विनिर्माण और सेवाएँ प्रदान करने हेतु की जा सकती है।
- वस्तुओं का निर्यात और आयात 7.2 (क) एस ई जेड एकक, प्रतिबंधित सामान के अलावा आई टी सी (एच एस) में बताई कृषि उत्पादों, आंशिक रूप से प्रसंस्कृत सामग्री, सब-एसेम्बलीज और संघटकों सहित वस्तुओं और सेवाओं का निर्यात कर सकते हैं। यह उपोत्पादों, अस्वीकृत माल, उत्पादन प्रक्रिया के दौरान वेस्ट स्क्रेप का भी निर्यात कर सकते हैं। विशेष रसायन, जैविकों, सामग्रियों, उपकरणों और टेक्नालाजी (एस.सी.ओ.एम.ई.टी) का निर्यात, आई टी सी (एच एस) में उल्लिखित शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

व्यापार/सेवा यूनिट को छोड़कर एस ई जेड यूनिट, रूस संघ को भी खरीददार होने के कारण राज्य क्रेडिट/स्करो रुपया लेखा के भुगतान के प्रति भारतीय रुपयों में निर्यात कर सकता है बशर्ते कि भारतीय रिजर्व बैंक की निकासी, यदि कोई हो, की अनुमति प्राप्त हो।

(ख) एस. ई. जेड एकक अपने कार्यकलापों या इससे संबंधित कार्यों के लिए आवश्यक तथा नीति में यथा-परिभाषित पूंजीगत वस्तुओं सहित, चाहे नई हों

या पुरानी, सभी प्रकार की वस्तुओं के शुल्क के भुगतान के बिना आयात कर सकते हैं और डीटीए से खरीद सकते हैं। बशर्ते ये आई टी सी (एच एस) में आयात की निषिद्ध मदें न हों। वस्तुओं में उपयोग के लिए पूंजीगत माल के विनिर्माण हेतु कच्चा माल शामिल है। इन एककों को पूंजीगत वस्तुओं, बिना लागत के यहाँ ग्राहकों से ऋण के रूप में, सहित स्वीकृत कार्यकलापों के लिए आवश्यक वस्तुओं का आयात करने की भी अनुमति होगी।

(ग) एस. ई. जेड. एकक नीति के तहत नीति के अनुसार/अथवा सीमा शुल्क अधिनियम के भाग 65 के अधीन तथा भारत में अयोजित अन्तराष्ट्रीय प्रदर्शनियों डी टी ए में स्थापित बांडेड गोदामों से शुल्क का भुगतान किए बिना आवश्यक वस्तुएं प्राप्त कर सकती हैं।

(घ) एस. ई. जेड एकक, एस ई जेड एकको द्वारा उपयोग के लिए केन्द्रीय सुविधाएँ स्थापित करने हेतु भुगतान के बिना सभी किस्मों की वस्तुओं का आयात/डी टी ए से खरीद कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर विकास के लिए केन्द्रीय सुविधा सॉफ्टवेयर के निर्यात हेतु डीटीए में एककों द्वारा बढ़ोतरी भी की जा सकती है।

(ड.) रत्न और आभूषण एकक नामजद अभिकरणों के जरिए स्वर्ण/चांदी/प्लैटिनम भी प्राप्त कर सकते हैं।

(च) एस. ई. जेड. एकक, जोन में यूनिटों की स्थापना करने के लिए डी. टी. ए. से माल का शुल्क भुगतान किए बिना आयात/खरीद भी कर सकते हैं।

पूंजीगत
वस्तुओं को
पट्टे पर देना

7.3 एस. ई. जेड एकक पार्टियों के बीच पक्के ठेके के आधार पर घरेलू/विदेशी पट्टा कम्पनी से पूंजीगत वस्तुएं प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे मामलों में एस ई जेड यूनिट और घरेलू/विदेशी पट्टा कम्पनी, संयुक्त रूप से दस्तावेज प्रस्तुत करेगी ताकि शुल्क के भुगतान के बिना पूंजीगत वस्तुओं का आयात/प्राप्ति संभव हो सके।

निवल विदेशी
मुद्रा अर्जन
(एन एफ ई)

7.4 एस ई जेड एकक सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा अर्जन करने वाला एकक होगा। निवल विदेशी मुद्रा अर्जन परिकलन, प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 14-II में दिए गए फार्मूले के अनुसार वार्षिक उत्पादन शुरू होने से पाँच वर्षों की अवधि के लिए संचित रूप से किया जाएगा।

कार्य निष्पादन
की मानिट्रिंग

7.5 (क) एस ई जेड एककों के कार्य निष्पादन की मॉनिटरिंग अनुमोदन समिति द्वारा की जाएगी।

(ख) एस. ई. जेड एककों के कार्य निष्पादन की मानिट्रिंग प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-14II में दिए गए दिशा निर्देश के अनुसार की जाएगी।

विधिक वचन-बद्धता 7.6 एकक संबंधित विकास आयुक्त के साथ एक विधिक वचनबद्धता निष्पादित करेगा और सकारात्मक विदेशी मुद्रा अर्जन न कर पाने की स्थिति में विधिक वचनबद्धता या उस समय लागू अन्य किसी कानून के तहत दंडित किया जा सकता है।

अनुमोदन और आवेदन 7.7 (क) सेवा क्षेत्र में यूनिट स्थापित करने के अतिरिक्त एस ई जेड में इकाई स्थापित करने के लिए (सॉफ्टवेयर एवं सूचना प्रौद्योगिकी से संबंधित बिक्री एवं अनुमोदन बोर्ड द्वारा प्रत्यायोजित अन्य सेवाओं को छोड़कर) प्रक्रिया पुस्तक भाग-1 के परिशिष्ट -14-II के अनुलग्नक में यथा निर्दिष्ट प्रक्रिया के अनुसार 15 दिन के भीतर यूनिट अनुमोदन समिति द्वारा अनुमोदित अथवा निरस्त कर दिया जाएगा। अन्य सभी मामलों में अनुमोदन की स्वीकृति अनुमोदन बोर्ड द्वारा दी जाएगी।

(ख) औद्योगिक लाइसेंस हेतु एस ई जेड में यूनिट स्थापित करने के प्रस्ताव पर एस ई जेड बोर्ड की स्वीकृति के बाद विकास आयुक्त अनुमोदन कर सकते हैं। इसके लिए औद्योगिक नीति एवं उन्नयन की सहमति के 45 दिन के भीतर निर्णय लिया जाएगा।

डी टी ए बिक्री और आपूर्तियाँ 7.8 (क) एस.ई.जेड एकक, उस समय लागू आयात नीति के अनुसार लागू शुल्क का भुगतान करके डी.टी.ए. में उपोत्पादों और सेवाओं सहित वस्तुओं की बिक्री कर सकता है।

(ख) सेवा/व्यापार एककों द्वारा डी.टी.ए. बिक्री संचित रूप से सकारात्मक निबल विदेशी मुद्रा प्राप्त करने के अधीन होगी। इस प्रकार जो इकाइयाँ एकल एल ओ पी के मध्य विनिर्माण और सेवा/व्यापार कार्य-कलाप करती हैं उनकी डी टी ए बिक्री, संचित शुद्ध विदेशी मुद्रा अर्जन की प्राप्ति के अधीन होगी।

(ग) एस ई जेड एककों द्वारा डी टी ए में की गई निम्नलिखित आपूर्तियाँ सकारात्मक निबल विदेशी मुद्रा अर्जन को पूरा करने के उद्देश्य के लिए किया जाएगा।

(1) नीति के अध्याय 8 के अनुसार डी टी ए में की गई आपूर्तियाँ।

(2) सीमाशुल्क अधिनियम की धारा 65 के तहत स्थापित बांडिड गोदामों को की गई आपूर्तियाँ।

- (3) अन्य ई ओ यू/एस ई जेड/ई एच टी पी/एस टी पी एककों को की गई आपूर्तियाँ बशर्ते कि ऐसे माल यूनिटों द्वारा प्राप्ति के लिए अनुमत हैं।
- (4) वस्तुओं के शुल्क मुक्त आयात की विशेष हकदारी के तहत आपूर्तियाँ।
- (5) ऐसे संगठनों को माल और सेवाओं की आपूर्ति जिनकी वित्त मंत्रालय द्वारा जारी सामान्य छूट अधिसूचना की शर्तों पर ऐसी मदों का मुक्त आयात करने की पात्रता है।
- (6) मुक्त विदेशी मुद्रा या भारतीय रुपयों में की गई ऐसी सेवाओं के लिए प्रदत्त निर्यात से संबंधित सेवाओं (सेवा यूनिटों द्वारा) जिनके लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा मुक्त विदेशी मुद्रा में भुगतान माना गया है।
- (7) प्रक्रिया पुस्तक के परिशिष्ट-14-II में उल्लिखित सूचना और तकनीकी (आईटीए-1) मदों और अधिसूचित शून्य शुल्क टेलीकाम/इलैक्ट्रॉनिक मदों की आपूर्तियाँ।

डी टी ए से 7.9 डी टी ए से एस ई जेड को आपूर्ति वाली यूनिटें निम्नलिखित के लिए पात्र
आपूर्ति के हेतु होंगी :-
हकदारी

(क) डी टी ए आपूर्तिकर्ता निम्नलिखित के हकदार होंगे-

- (1) शुल्क वापसी अथवा डी इ पी वी के मद्दे शुल्क वापसी।
- (2) आपूर्ति कर्ता द्वारा निर्यात निष्पादन, यदि कोई हो पूरा करना।

(ख) एस. ई. जैड यूनिटें पात्र होगी,

- (1) केन्द्रीय बिक्री कर की छूट,
- (2) यूनिटों द्वारा प्राप्ति के लिए योग्य सभी वस्तुओं पर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पर छूट,
- (3) जहाँ तक इस संबंध में थोक चाय पर लागू लेवी का संबंध है एस ई जेड यूनिट द्वारा थोक चाय की खरीदों पर प्रदत्त केन्द्रीय उत्पाद शुल्क की प्रतिपूर्ति
- (4) विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा अधिसूचित ऐसी अधिसूचना की तारीख से शुल्क वापसी की दर पर डी टी ए से खरीदे गए ईंधन या किसी अन्य वस्तुओं पर भुगतान किये गये शुल्क की प्रतिपूर्ति।

(ग) घरेलू टेरिफ क्षेत्र से एस ई जेड में स्थित एकको को बहुमूल्य और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों, सिंथेटिक पत्थरों और संसाधित मोतियों के आपूर्तिकर्ता प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में उल्लिखित दरों और मदों के लिए प्रतिपूर्ति लाइसेंस पाने के पात्र होंगे।

(घ) उपर्युक्त पैराग्राफ (क) तथा (ख) (ii) के अधीन पात्रता उस आपूर्ति के लिए उपलब्ध होगी जो माल देश में विनिर्मित हो।

स्तर धारकों के 7.10 एस ई जेड एकक, उसके द्वारा निर्मित वस्तुओं/विकसित सॉफ्टवेयर इस नीति
माध्यम से के तहत मान्यता प्राप्त व्यापारिक निर्यातक/स्तरधारक या किसी अन्य ई ओ यू/
निर्यात ई पी जेड/एस ई जेड/ई एच टी पी/एस टी पी एकक के माध्यम से निर्यात भी
कर सकता है।

अन्तर यूनिट
हस्तांतरण

7.11 (क) एस ई जेड यूनिट, एस ई जेड यूनिट से आंशिक प्रसंसाधित/अर्ध-संसाधित माल या सेवाओं सहित अन्य एस ई जेड/ ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट को विनिर्मित माल के हस्तांतरण कर सकता है ।

(ख) किसी एस ई जेड यूनिट, उसी एस ई जेड के भीतर किसी अन्य यूनिट को उस आयातित प्राप्त माल का हस्तांतरण कर सकता है या दे सकता है जिसे बाकायदा गिना जाएगा लेकिन निर्यात निष्पादन की पूर्ति हेतु नहीं गिना जाएगा ।

(ग) आयातित/खरीदे गए पूंजीगत माल का विकास आयुक्त और सीमाशुल्क प्राधिकारियों की पूर्व अनुमति से अन्य एस ई जेड/ई एस जेड/ई ओ यू/ई एच टी पी/एस टी पी यूनिट को हस्तांतरण कर सकता है या उधार दे सकता है।

(घ) सब पैरा (क) और (ख) के अनुसार उसी एस ई जेड में माल के हस्तान्तरण के लिए अनुमति नहीं लेनी होगी परन्तु यूनिट कार्य का पूरा लेखा-जोखा रखेगी।

अन्य हकदारी

प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट 14-11 में एस ई जेड की अन्य हकदारी का उल्लेख किया गया है।

उप-ठेका

7.12 (क) एस ई जेड एकक सीमाशुल्क प्राधिकारी की वार्षिक अनुमति से डी टी ए में एककों या अन्य एस ई जेड/ई ओ यू/ई पी जेड/ई एच टी पी/एस टी पी के माध्यम से अपने उत्पादन के हिस्से या उत्पादन प्रक्रिया का ठेका दे सकता है । उत्पादन प्रक्रिया के भाग के उप-ठेके की विदेश में अनुमति विकास आयुक्त की मंजूरी से दी जा सकती है

(ख) अन्य एस ई जेड/ई ओ यू अथवा घरेलू टैरिफ क्षेत्र में यूनिटों के माध्यम से एस ई जेड रत्न और आभूषण एककों द्वारा उप ठेका निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा,

(1) जड़ित आभूषणों सहित तैयार या अर्द्ध-तैयार वस्तुओं जिनमें इस प्रकार निकाले गए स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के बराबर मात्रा और शुद्धता हो, को 30 दिन के भीतर जोन में वापिस लाया जाएगा। इसके अलावा किसी हीरे, बहुमूल्य या अर्द्ध बहुमूल्य पत्थरों को उप ठेके के लिए जोन से बाहर ले जाने की अनुमति नहीं होगी।

(2) बराबर मात्रा और शुद्धता के स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के बदले में डी टी ए से सादा स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के आभूषण प्राप्त करना।

(3) उप ठेके हेतु और अदला-बदली के प्रति यथा लागू एस ई जेड यूनिटें वेस्टेज हेतु पात्र होंगी ।

(4) स्वर्ण/चांदी/प्लेटिनम के बदले जोब वर्क या आभूषण की आपूर्ति का कार्य

हाथ में लेने वाला डी टी ए एकक मान्य निर्यात लाभ पाने का पात्र नहीं होगा।

(ग) रत्न और आभूषण एकक सहित सभी एकक सीमाशुल्क प्राधिकारी की अनुमति के बिना उसी एस ई जेड अन्य एककों के माध्यम से उत्पादन के हिस्से या उत्पादन प्रक्रिया को उप-ठेके पर दे सकते हैं जो कि आपूर्ति करने वाले और वस्तुओं को प्राप्त करने वाले एककों दोनों द्वारा रिकार्ड रखने के अधीन होगा।

(घ) रत्न और आभूषण एककों के अलावा, एस ई जेड एककों को डी टी ए निर्यातक की ओर से निर्यात के लिए जानकारी लेने की अनुमति होगी बशर्ते तैयार वस्तुओं एस ई जेड एककों को सीधे ही निर्यात किया जाए। ऐसे निर्यात के लिए डी टी ए एकक शुल्क वापसी की बान्ड दर की वापसी के पात्र होंगे।

(ङ.) जाब वर्क से उत्पन्न स्क्रेप/वेस्ट/रेमेनेन्ट्स को लागू शुल्क का भुगतान करके जाब वर्कर के परिसर से निकास किया जाएगा या एकक को वापिस किया जाएगा।

(च) प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-14-॥ में उल्लिखित प्रक्रिया की शर्तों के अधीन सीमा शुल्क प्राधिकारियों से वार्षिक अनुमति के आधार पर कृषि/बागवानी उत्पादों के उत्पादन/प्रसंसाधन में लगी हुई एस ई जेड यूनिटें, निविष्टि तथा उपकरण को घरेलू प्रशुल्क क्षेत्र को सौंप सकती है।

एस ई जेड
योजनाओं से
बहिर्गमन

7.13

(क) विकास आयुक्त के अनुमोदन से एस ई जेड एकक स्कीम से बाहर रह सकते हैं। स्कीम से ऐसा बहिर्गमन आयातित और स्वदेशी पूंजीगत वस्तुओं, कच्चा माल आदि और स्टॉक में तैयार वस्तुओं पर लागू सीमाशुल्क और उत्पाद शुल्क के भुगतान के अधीन होगी। यदि एकक ने सकारात्मक निवल विदेशी मुद्रा प्राप्त नहीं की है तो यह दण्ड के अधीन होगा जिसे विदेश व्यापार (विकास और विनियमन) अधिनियम 1992 के तहत न्याय निर्णय प्राधिकारी द्वारा लगाया जाएगा।

(ख) एक बार के विकल्प के रूप में एस ई जेड स्कीम से बाहर विकास आयुक्त द्वारा एस ई जेड एकक की मौजूदा ई पी सी जी किसी योजना के तहत पूंजीगत वस्तुओं पर शुल्क का भुगतान करने पर बहिर्गमन की अनुमति दी जाएगी बशर्ते एकक इस योजना के पात्रता संबंधी मानदण्डों और प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट - 14-॥ के अनुसार मानक शर्तों को पूरा करें।

समारोह/निर्यात संवर्धन दौरो/विदेशों में शो-रूम के माध्यम से निर्यात/शुल्क मुक्त दुकानों माध्यम से निर्यात	7.14 विशेष आर्थिक क्षेत्र:- (1) विकास आयुक्त की अनुमति से विदेशों में आयोजित समारोह में होल्डींग/विदेशों में प्रदर्शनियों में भाग लेने के लिए निर्यात कर सकते हैं। (2) सोना/चांदी/प्लेटिनम आभूषणों, बहुमूल्य, अर्द्ध-बहुमूल्य पत्थरों, बीड्स एवं वस्तुओं की व्यक्तिगत दुलाई। (3) विदेश में स्थापित अनुमति प्राप्त दुकानों पर प्रदर्शन/बिक्री के लिए आभूषणों के निर्यात की भी अनुमति है। (4) विदेश में स्थापित अनुमति प्राप्त दुकानों या इनमें वितरकों/एजेंटों के शोरूम में प्रदर्शन/बिक्री। (5) अन्तराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर शोरूम/खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना।
निर्यात/आयात पार्सल का व्यक्तिगत असवाब	7.15 रत्नों एवं आभूषणों के आयात/निर्यात पार्सलों को व्यक्तिगत असवाब के तौर पर ले जाने और रत्न और आभूषणों के आयात/निर्यात पार्सलों के अलावा, व्यक्तिगत असवाब के तौर पर लाने की अनुमति सीमाशुल्क द्वारा निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार दी जाएगी बशर्ते कि माल व्यावसायिक मात्रा में नहीं हो।
डाक/कुरियर द्वारा निर्यात	7.16 मुफ्त नमूने सहित वस्तुओं का एयरकुरियर या विदेशी डाकघर या कुरियर के माध्यम से निर्यात किया जा सकता है बशर्ते कि इसकी प्रक्रिया सीमाशुल्क कार्यालय द्वारा निर्धारित की गयी हो।
खराब माल/ स्क्रेप/वेस्ट/ अपशिष्ट का निपटारा	7.17 उत्पादन प्रक्रिया या इससे संबंधित कार्यकलापों से बने खराब माल/स्क्रेप/वेस्ट/अपशिष्ट को लागू शुल्क का भुगतान करने पर डी टी ए में बेचा जा सकता है। सीमाशुल्क प्राधिकारी को सूचित करके जोन के भीतर स्क्रेप/वेस्ट/अपशिष्ट/खराब माल को नष्ट करने पर या सीमाशुल्क प्राधिकारी की अनुमति से एस ई जेड के बाहर नष्ट करने पर कोई शुल्क देय नहीं होगा। उपरोक्त के अनुसार, स्वर्ण, चाँदी, प्लेटिनम, हीरा, कीमती तथा अर्द्ध कीमती पत्थरों पर यह लागू नहीं होगा।
वस्तुओं की प्रतिस्थापन/ मरम्मत	7.18 (क) प्रतिस्थापित/मरम्मत की गई वस्तुओं के निर्यात संबंधित नीति के प्रावधान एस ई जेड एककों पर भी समान रूप से लागू होंगे, इसके अलावा, जो मामले इन प्रावधानों के तहत नहीं आते उन पर विकास आयुक्त द्वारा गुण-दोष के आधार पर विचार किया जाएगा। (ख) डी टी ए में बेची गई वस्तुओं जिन्हें खराब पाया गया है उन्हें विकास आयुक्त को सूचित करते हुए मरम्मत/बदलने के लिए वापिस लाया जाएगा। (ग) आभूषण निर्माण हेतु रत्नों और कीमती धातुओं के संघटकों सहित वस्तुओं या इसके हिस्सों को आयातित/स्वदेशी रूप से प्राप्त किए जाने और खराब पाया

जाने या प्रयोग के लिए अन्यथा ठीक ना पाया जाना या जो वस्तुएं क्षतिग्रस्त हो गई हैं या आयात/प्राप्त के पश्चात् खराब हो गई हैं उन्हें वापिस किया जा सकता है और बदला जा सकता है या नष्ट किया जा सकता है। वस्तुओं को बदले जाने की स्थिति में वस्तुओं को विदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं या भारत इनके प्राधिकृत एजेंटों या स्वदेशी आपूर्तिकर्त्ताओं से वापिस लाया जा सकता है। तथापि, यह नष्ट करना रत्न, पत्थरों और कीमती धातुओं पर लागू नहीं होगा।

(घ) सीमाशुल्क प्राधिकारी को सूचित करके और रिकार्डों के रख रखाव के प्रति वस्तुओं को मरम्मत करने/बदलने, परीक्षण अंशांकन, गुणवत्ता, परीक्षण और अनुसंधान और विकास प्रयोजन के लिए डी टी ए को हस्तान्तरित किया जा सकता है।

- | | | |
|--|------|---|
| विशेष आर्थिक क्षेत्र का प्रबन्धन | 7.19 | (क) एस ई जेड विकास आयुक्त के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन होगा।
(ख) विशेष आर्थिक जोन यूनिटों में अन्य विनिर्दिष्ट माध्यम को छोड़कर सभी गतिविधियाँ स्वतः प्रमाणित प्रक्रिया द्वारा की जाएगी। |
| निजी/संयुक्त/राज्य क्षेत्र में एस ई जेड की स्थापना | 7.20 | प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-14-॥ में उल्लिखित ब्यौरों के अनुसार एस ई जेड सार्वजनिक, निजी, संयुक्त क्षेत्र या राज्य सरकार द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। |
| नमूने | 7.21 | एस ई जेड एकक उनके द्वारा रखे गए रिकार्डों के आधार पर और सीमाशुल्क प्राधिकारी की पूर्व अनुमति से:-
(1) लागू शुल्क के भुगतान पर, प्रदर्शन/बाजार संवर्धन के लिए डी टी ए में नमूनों की आपूर्ति या बिक्री कर सकते हैं।
(2) सीमाशुल्क प्राधिकारियों को उपयुक्त वचनवद्धता प्रस्तुत करने पर निर्धारित अवधि के भीतर वस्तुओं को वापिस लाया जाएगा बशर्ते कि शुल्क के भुगतान के बिना नमूनों को हटा लिया जाए।
(3) निर्यात मुफ्त नमूने, बिना सीमा के, वैक्स मोल्ड्स, चाँदी मोल्ड्स और रबर मोल्ड्स में निर्मित मुफ्त नमूनों समेत, निर्यात के सभी अनुमत साधन जो कुरियर एजेंसियों/डाक के माध्यम से किया गया है। |

अप्रयुक्त
सामग्री/
अप्रचलित माल
की बिक्री

7.22 (क) पूँजीगत माल और सेवाओं का प्रयोग करने में, वैध कारणों से, एस ई जेड यूनिट असमर्थ है तो उन्हें डी टी ए यूनिट में प्रभावी नीति के अनुसार तथा लागू शुल्कों का भुगतान करके बेचा जा सकता है।

(ख) जो पूँजीगत वस्तुएं और हिस्से पूर्ण प्रचलित/फालतू हो गए हैं उन्हें या तो निर्यात किया जा सकता है या लागू शुल्क का भुगतान करके डी टी ए में बेचा जा सकता है। यथा लागू मूल्यह्रास लाभ डी टी ए में बिक्री के मामले में उपलब्ध होंगे।

(ग) किसी शुल्क का भुगतान नहीं किया जाएगा। यदि पूँजीगत माल, कच्चा माल, उपभोग्य, स्पेयर्स, विनिर्मित वस्तुएँ, संसाधित अथवा पैकेज्ड वस्तुएँ तथा स्क्रेप/वेस्ट/उपशिष्ट को जोन के भीतर सीमाशुल्क प्राधिकारियों की सूचना में नष्ट किया जाता है अथवा जोन के बाहर सीमा शुल्क प्राधिकारियों की अनुमति से नष्ट किया जा सकता है। तथापि, कीमती और अर्द्ध कीमती धातुओं के लिए यह विनष्टीकरण लागू नहीं होगा।

(घ) संबंधित सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा एस ई जेड एकक को आयातित/स्वदेशी रूप से प्राप्त किए गए कम्प्यूटर और पेरिफैरलस का एकक द्वारा आयात करने/प्राप्त करने और प्रयोग के 2 वर्ष के पश्चात शुल्क का भुगतान किए बिना प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) के परिशिष्ट-14-11 में उल्लिखित व्यौरों के अनुसार मान्यता प्राप्त गैर वाणिज्यिक शैक्षिक संस्थाओं, पंजीकृत धर्म अस्पतालों इत्यादि को दान कर सकते हैं।

एस ई जेड
विकासकर्ता
हेतु हकदारी

7.23 (क) एस ई जेड में सुविधाओं के विकास, कार्यान्वयन और रख-रखाव हेतु विकासकर्ता निम्न हकदारी हेतु पात्र होगा :-

- (i) आयकर अधिनियम की धारा 80-1क के अनुसार आयकर में छूट।
- (ii) सीमाशुल्क/उत्पाद कर के भुगतान के बिना माल का आयात/खरीद।
- (iii) सेवा कर से छूट।
- (iv) केन्द्रीय बिक्री कर से छूट।

अध्याय-7क

मुक्त व्यापार और वेयरहाउसिंग जोन

- उद्देश्य 7क.1 इसका उद्देश्य है मुक्त मुद्रा में मुक्त रूप से व्यापारिक लेन-देन करने और आयात व निर्यात को सुगम बनाने हेतु व्यापार संबंधित ढाँचा बनाना । स्कीम में विभिन्न उत्पादों को गोदाम में रखने हेतु विश्व स्तर का ढाँचा बनाने, अत्याधुनिक (स्टेट आफ द आर्ट) उपकरण, परिवहन और प्रबंधन सुविधाएँ, कमर्शियल कार्यालय-स्थल, जल, विद्युत, संचार और सम्पर्क, एक स्थान पर आयात और निर्यात की निकासी हेतु औपचारिकता की परिकल्पना की गयी है ताकि समेकित जोनों को “अन्तरराष्ट्रीय व्यापार केन्द्रों” के तौर पर सुविधाएँ प्रदान की जाएँ । इन जोनों को समुद्री पत्तनों, वायुपत्तनों अथवा शुष्क पत्तनों के नजदीकी क्षेत्रों में स्थापित किया जाएगा ताकि रेल और सड़क से आसानी से पहुँचा जा सके ।
- श्रेणी 7क.2 मुक्त व्यापार और गोदाम जोन (एफटीडब्ल्यूजैड) व्यापार और गोदाम पर ध्यान देते हुए विशेष आर्थिक जोनों की विशेष श्रेणी होगी ।
- जोन की स्थापना 7क.3 (1) एफटीडब्ल्यूजैडों की स्थापना हेतु प्रस्ताव सार्वजनिक क्षेत्र के प्रतिष्ठानों अथवा सार्वजनिक क्षेत्र की लिमिटेज कम्पनियों अथवा अनुभवी ढाँचागत डेवेलपर्स के साथ तकनीकी सहयोग प्राप्त संयुक्त उधमों द्वारा किए जा सकते हैं । इन प्रस्तावों पर वाणिज्य विभाग के अनुमोदन बोर्ड द्वारा विचार किया जाएगा । अनुमोदन प्राप्त होने पर, डेवेलपर को ऐसे एफटीडब्ल्यूजैड के विकास, संचालन और रख रखाव हेतु अनुज्ञा पत्र जारी किया जाएगा ।
- (2) जोनों के विकास और स्थापना तथा उनकी ढाँचागत सुविधाओं हेतु 100 प्रतिशत तक विदेशी सीधे निवेश की अनुमति होगी ।
- (3) प्रस्ताव पर ढाँचागत सुविधाओं के निर्माण और विकास हेतु अनिवार्यतः 100 करोड़ रुपये का न्यूनतम परिव्यय आना चाहिए और उसका निर्माणाधीन न्यूनतम क्षेत्र पांच लाख वर्ग मीटर होना चाहिए ।
- (4) डेवेलपर को शुल्क मुक्त आयात करने की अनुमति होगी जैसे कि जोन के विकास और ढाँचे हेतु आवश्यक बिल्डिंग मैटेरियल और उपकरण । यह उपकरण और मैटेरियल जिसे डीटीए से प्राप्त

किया जाएगा को डीटीए आपूर्तिकर्ताओं से वास्तविक निर्यात के तौर पर ध्यान में रखा जाएगा ।

- (5) एक बार एफटीडब्ल्यूजेड विकसित हो जाने पर, डेवलपर को एफटीडब्ल्यूजेड में गोदाम/वर्कशाप/कार्यालय-क्षेत्र को व्यापारियों/निर्यातकों को बिक्री/लीज/किराए पर देने की भी अनुमति होगी ।

जोन का
रखरखाव

- 7क.4. विकासक स्वयं या उपयुक्त विशेष प्रयोजन प्रबन्ध के जरिये एफटीडब्ल्यूजेड की सामान्य सुविधाओं और सुरक्षा के उचित रख-रखाव के लिए भरोसे योग्य तंत्र सुनिश्चित करेगा ।

कार्यकलाप

- 7क.5 (1) इस योजना में वेयरहाउसिंग के लिए सभी वस्तुओं (निषिद्ध मदों, हथियार और गोला-बारूद, खतरनाक अपशिष्टों और स्लोमेट मदों के अलावा) का शुल्क मुक्त आयात करने की परिकल्पना की गई है । जहां तक आयात पर सीमा शुल्क के बारे में बांड का संबंध है, ये एकक एसईजेड में एककों के लिए लागू उपबन्धों के अधीन होंगे ।
- (2) ऐसी वस्तुओं के पुनः बेचने/पुनः अनवाय करने या पुनः निर्यात करने की अनुमति होगी । पुनः निर्यात की अनुमति बिना किसी प्रतिबन्ध के ही जायेगी । तथापि, स्लोमेट मदों के आयात की अनुमति अन्तर मंत्रालयीय समिति की इजाजत के बिना नहीं दी जायेगी ।
- (3) इन वस्तुओं को ऐसी बिक्री की तारीख पर यथा लागू सीमा शुल्क के भुगतान पर डीटीए में बिक्री की भी अनुमति दी जायेगी । शुल्क का भुगतान केवल सभी देय होगा जब डीटीए में वस्तुओं को बेचा/सुपुर्द किया जायेगा और बाँण्डेड वेयरहाउसों के मामले में कोई ब्याज नहीं लिया जायेगा ।
- (4) प्रोसेसिंग के बिना पैकिंग या पुनः पैकिंग और ग्राहक या विपसन आवश्यकताओं के अनुसार लेबलिंग एफटीडब्ल्यूजेड के भीतर की जा सकती है ।
- (5) एफटीडब्ल्यूजेड के भीतर वस्तुओं को गोदाम में रखने की अधिकतम अवधि दो वर्ष होगी, इस अवधि के बाद इनका अनिवार्य रूप से पुनः निर्यात करना होगा या इन्हें डीटीए में बेचना होगा ।

दो वर्ष की अवधि समाप्त होने पर, यथा लागू सीमा शुल्क स्वतः देय हो जायेगा जब तक कि यथा अनुमत छूट की अवधि, जो तीन माह से ज्यादा नहीं होगी, के भीतर इन वस्तुओं का पुनः निर्यात नहीं किया जाता ।

- | | | |
|--|-------------|--|
| <p>एन.एफ.ई.
मापदंड</p> | <p>7क.6</p> | <p>(1) आय कर अधिनियम की धारा 80 आईए के अनुसार आय कर से छूट ।</p> <p>(2) सेवा कर से छूट ।</p> <p>(3) मुक्त विदेशी मुद्रा के विनिमय की अनुमति दी जायेगी ।</p> <p>(4) एसईजेड के एककों को यथा लागू आवश्यक परिवर्तनों सहित अन्य लाभ ।</p> |
| <p>निवल विदेशी
मुद्रा संबंधी
मापदण्ड</p> | <p>7क.7</p> | <p>एफटीडब्ल्यूजेड में एकक निवल विदेशी मुद्रा अर्जक होंगे । एसईजेड यूनिटों पर लागू फार्मुले के अनुसार गोदाम और/अथवा व्यापारिक कार्यकलापों की शुरूआत से प्रत्येक पांच वर्षों की अवधि हेतु सकल विदेशी मुद्रा को संचयी तौर पर परिकलित किया जाएगा ।</p> |

अध्याय - आठ

मान्य निर्यात

- मान्य निर्यात 8.1 'मान्य निर्यात' का अर्थ उस लेन-देन से है जिसमें आपूर्ति किया गया माल देश से बाहर नहीं जाता और इन आपूर्तियों के लिए भुगतान या तो भारतीय रुपये में हो या मुक्त विदेशी मुद्रा में प्राप्त किया जाता है।
- संभरण की श्रेणियाँ 8.2 इस नीति के तहत निम्नलिखित श्रेणियों के माल का मुख्य/उप श्रेणियाँ ठेकेदारों द्वारा आपूर्ति को मान्य-निर्यात के रूप में माना जाएगा बशर्ते कि माल भारत में विनिर्मित हुआ हो :-
- (क) शुल्क मुक्त/शुल्क वापसी स्कीम के तहत जारी अग्रिम लाइसेंस/वार्षिक आवश्यकता के लिए अग्रिम लाइसेंस वार्षिक आवश्यकता वाले अग्रिम लाइसेंस /डी एफ आर सी के प्रति माल का संभरण:
 - (ख) निर्यातोन्मुख यूनिटों या निर्यात संसाधन क्षेत्रों अथवा एस ई जैड या साफ्टवेयर टेक्नालोजी पार्क्स (इएचटीपी) या वायोटेक्नालौजी पार्क (बी टी पी) अथवा इलेक्ट्रॉनिक हार्डवेयर टेक्नालोजी पार्कस में स्थित यूनिटों को माल की आपूर्ति।
 - (ग) निर्यात संवर्धन पूंजीगत माल (ई पी सी जी) स्कीम के अन्तर्गत लाइसेंसधारियों को पूंजीगत माल की आपूर्ति।
 - (घ) वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग द्वारा अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के तहत बहुपक्षीय या द्विपक्षीय अभिकरणों/निधियों द्वारा वित्त-पोषित परियोजनाओं को उन अभिकरणों/निधियों की प्रक्रियाओं के अनुसार माल का संभरण, जहां विधिक करारों में सीमाशुल्क को शामिल किए बिना टेंडर मूल्यांकन की व्यवस्था हो।
 - (ङ.) पूंजीगत माल की आपूर्ति जिसमें उर्वरक संयंत्रों की स्थापना हेतु इस पूंजीगत माल के लिए आवश्यक अनअसैम्बलड/डिसअसैम्बलड हालत में तथा कच्चा माल अर्न्तवर्ती, संघटक, कलपुर्जे शामिल हैं और एफ ओ आर मूल्य के 10 प्रतिशत तक हिस्से पुर्जों एवं वाणिज्यिक उत्पाद की आपूर्ति।

- (च) इस अध्याय के अन्तर्गत घरेलू संभरण के लिए शून्य सीमाशुल्क पर ऐसे माल के आयात की अनुमति देते हुए किसी परियोजना या प्रयोजन के लिए वित्त मंत्रालय की एक अधिसूचना के तहत घरेलू संभरण के लिए माल की आपूर्ति।
- (छ) ऊपर (च) में शामिल न किए गए पावर और रिफाइनरी को माल की आपूर्ति।
- (ज) शिपिंग कारपोरेशन को 100 प्रतिशत ई ओ यू (घरेलू भाड़ा कन्टेनरों के विनिर्माताओं) द्वारा समुद्री फ्रेट कन्टेनरों की आपूर्ति, बशर्ते उक्त कन्टेनरों का भारत से 6 महीनों या सीमाशुल्क प्राधिकारियों द्वारा अनुमत अवधि के भीतर निर्यात किया गया हो।
- (झ) संयुक्त राष्ट्र संघ के संगठनों द्वारा वित्त पोषित संगठनों को की गई आपूर्ति।
- (ञ) अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के विपरीत प्रतियोगी बोली के आधार पर न्यूक्लियर पावर प्रोजेक्टों को माल की आपूर्ति।

पैराग्राफ (घ), (ङ.), (च) और (छ) के तहत मान्य निर्यात के लाभ केवल तभी उपलब्ध होंगे यदि आपूर्ति अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली की प्रक्रिया के अन्तर्गत की गई है।

मान्य निर्यातों के लिए लाभ 8.3 मान्य निर्यात के रूप में पात्र माल के विनिर्माण और आपूर्ति के संदर्भ में मान्य निर्यात पर निम्नलिखित लाभ दिए जाएंगे बशर्ते कि प्रक्रिया पुस्तक खण्ड (1) में दी गयी शर्तों के अनुसार होगा -

अन्तर्वर्ती आपूर्ति/मान्य निर्यात के लिए अग्रिम लाइसेंस/ डी एफ आर सी

- (ख) मान्य निर्यात शुल्क वापसी।
- (ग) जहाँ आपूर्तियों अन्तर्राष्ट्रीय प्रतियोगी बोली के मद्दे की गई है वहाँ अन्तिम उत्पाद शुल्क से छूट होगी। अन्य मामलों में अन्तिम उत्पाद शुल्क वापिस किया जाएगा।

अध्याय - नौ

परिभाषाएं

- 9.1 इस नीति के उद्देश्य के लिए, जब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो, निम्नलिखित पैरों में दिए गए शब्दों और अभिव्यक्तियों के निम्नलिखित अर्थ होंगे:-
- 9.2 “उप्रांग” या “संलग्नी” का अर्थ है एक पुर्जा, उपसंयोजक अथवा संयोजक जो उपस्कर के मूल कार्यों को परिवर्तित किए बिना उपस्कर के एक अंश की कार्यक्षमता या कारगरता में सहयोग देता है।
- 9.3 “अधिनियम” का अर्थ है-विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1992, (1992 की संख्या 22)।
- 9.4 “वास्तविक उपयोक्ता” का अर्थ है वास्तविक उपयोक्ता जो औद्योगिक अथवा गैर-औद्योगिक हो सकता है।
- 9.5 “वास्तविक उपयोक्ता (औद्योगिक)” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयातित माल का प्रयोग अपनी निजी यूनिट में विनिर्माण के लिए अथवा फुटकर सहित किसी अन्य यूनिट में अपने निजी प्रयोग के लिए करता है।
- 9.6 “वास्तविक उपयोक्ता (गैर-औद्योगिक)” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो अपने स्वयं के इस्तेमाल के लिए आयातित सामग्री का निम्नलिखित में इस्तेमाल करता हो:-
1. कोई भी वाणिज्यिक प्रतिष्ठान जो कोई व्यवसाय, व्यापार या पेशा कर रहा हो, या
 2. कोई भी प्रयोगशाला, वैज्ञानिक या अनुसंधान और विकास संस्था, विश्वविद्यालय या अन्य शैक्षिक संस्था या अस्पताल, या
 3. कोई सेवा उद्योग।
- 9.7 “ए ई जैड” का अर्थ है महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा अधिसूचित कृषि निर्यात क्षेत्र।
- 9.8 “ए एल सी” अर्थात् “अग्रिम लाइसेंसिंग समिति” का अर्थ है शुल्क से मुक्त स्कीम के अधीन लाइसेंस प्रदान करने के लिए सिफारिश करने और महानिदेशक विदेश व्यापार द्वारा अधिसूचित किए जाने वाले निवेश उत्पादन मानदण्डों की सिफारिश करने वाली विदेश व्यापार महानिदेशालय की अग्रिम लाइसेंसिंग समिति।

- 9.9 “आवेदक” का अर्थ है वह व्यक्ति जिसकी तरफ से आवेदन किया जाए और जहाँ संदर्भ में आवश्यक हो, इसमें आवेदन पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति भी शामिल है।
- 9.10 “बी ओ ए” का अर्थ है अनुमोदन बोर्ड जैसा कि वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित है।
- 9.11 “बीटीपी” से अभिप्राय उन बायोटेक्नालोजी पार्कों से है जिन्हें बायोटेक्नोलोजी विभाग की सिफारिश पर विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा अधिसूचित किया गया है।
- 9.12 “पूँजीगत माल” का अर्थ है माल के, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष उत्पादन के लिए या सेवा अर्पित करने के लिए अपेक्षित संयंत्र, मशीनरी, उपस्कर या उपसाधित्र जिनमें प्रतिस्थापन, आधुनिकीकरण, प्रौद्योगिकी के उन्नयन या विस्तार के लिए अपेक्षित सामग्री भी शामिल हैं। पैकेजिंग मशीनरी और उपकरण, रिफ्रेक्टरीज, प्रशीतन उपकरण, उर्जा अर्जित करने वाले सेट, मशीन टूल्स, इनीशियल चार्ज के लिए कैटालिस्ट और परीक्षण अनुसंधान और विकास, गुणवत्ता और प्रदूषण नियंत्रण के लिए उपस्कर एवं उपकरण शामिल हैं। पूँजीगत माल के निर्माण, खनन, कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्प कृषि, बागवानी, मत्स्य पालन, मृगीपालन और रेशम-उत्पादन एवं अंगूरोत्पादन के साथ-साथ सेवा विभाग में भी उपयोग में लाया जा सकता है।
- 9.13 “सक्षम प्राधिकारी” का अर्थ है-वह प्राधिकारी जो अधिनियम अथवा उसके तहत बने नियमों एवं आदेशों अथवा इस नीति के तहत किसी शक्ति का प्रयोग करने, कर्तव्य को पूरा करने के लिए सक्षम हों।
- 9.14 “संघटक” का अर्थ उप संयोजन या संयोजन का वह पुर्जा जिससे एक विनिर्मित उत्पाद तैयार किया जाता है या जिसमें वह विघटित हो जाए। संघटक में उसके सहायक या उपषंगी भी शामिल हैं।
- 9.15 “उपभोज्य” माल का अर्थ है कोई मद जो विनिर्माण प्रक्रिया में शामिल हो या जिसकी आवश्यकता हो परन्तु जो तैयार उत्पाद का भाग न हो। मदें जिनका वास्तविक रूप में पूर्णतया उपभोग कर लिया जाता है, उन्हें उपभोज्य मदें माना जाएगा।
- 9.16 “उपभोक्ता माल” का अर्थ खपत के उस माल से है जो किसी अन्य संसाधन के बिना मनुष्य की आवश्यकताओं को सीधे ही पूरा कर सकता है और इसमें उपभोक्ता के लिए टिकाऊ उपभोज्य माल और उसके अनुषंगी भी शामिल होंगे।
- 9.17 “प्रतिसंतुलन व्यापार” (काउंटर ट्रेड) का अर्थ उस व्यवस्था से है जिसके अन्तर्गत भारत से/को किया जाना वाला आयात/निर्यात व्यापार समझौते या अन्यथा के तहत आयात/निर्यात करने वाले देश से सीधे अथवा तीसरे देश के जरिये संतुलित होता हों। प्रतिसंतुलन व्यापार

(काउंटर ट्रेड) के अन्तर्गत निर्यात/आयात की अनुमित एस्क्रो एकाउंट, वापस खरीदने की व्यवस्था, वस्तु विनिमय व्यापार या किसी ऐसी ही अन्य व्यवस्था के अन्तर्गत दी जा सकती है। ऐसा प्रतिसंतुलन पूर्णतया या आंशिक तौर पर नकद, माल और/या सेवाओं के रूप में हो सकता है।

- 9.18 “विकासकर्ता” का अर्थ है एक व्यक्ति या व्यक्तियों का निकाय, कम्पनी, फर्म और ऐसे ही अन्य निजी या सरकारी उद्यम, जो केन्द्रीय सरकार द्वारा यथाअनुमोदित विशेष आर्थिक क्षेत्रों में अन्य सुविधाओं को और बुनियादी सुविधाओं के एक भाग या सम्पूर्ण सुविधाओं का विकास, निर्माण करता है, डिजाइन तैयार करता है, स्थापना, संवर्धन करता है, प्रचार, वित्तीय सहायता प्रचालन, रख-रखाव या प्रबन्ध करता है।
- 9.19 “विकास आयुक्त” का अर्थ है विशेष आर्थिक क्षेत्र का विकास आयुक्त।
- 9.20 “डी एफ आर सी” का अर्थ है शुल्क वापसी स्कीम के अधीन जारी शुल्क मुक्त प्रतिपूर्ति प्रमाण-पत्र
- 9.21 “घरेलू टैरिफ क्षेत्र” का अर्थ है भारत के भीतर का क्षेत्र जो कि विशेष आर्थिक क्षेत्रों ओर ईओयू/ईएचटीपी/एसटीपी/बीटीपी से बाहर है।
- 9.22 “शुल्क वापसी” का अर्थ है भारत में विनिर्मित और निर्यात किए गए किसी माल के संबंध में किसी आयातित माल पर अथवा ऐसे माल के विनिर्माण में प्रयुक्त उत्पाद-शुल्क देय माल पर उगाहे जाने वाले शुल्क में कटौती। भारत में विनिर्मित पूंजीगत माल सहित आयातित कल-पुर्जे, यदि आपूर्ति की गई है, माल में शामिल है।
- 9.23 “ई. एच. टी. पी.” का अर्थ है इलेक्ट्रानिक हार्डवेयर टेक्नॉलाजी पार्क।
- 9.24 “ई.ओ.यू.” का अर्थ है निर्यात उन्मुख एकक।
- 9.25 “उत्पाद शुल्क देय माल” का अर्थ है -कोई माल जिसका भारत में निर्माण किया गया हो और वह केन्द्रीय उत्पाद शुल्क तथा नमक अधिनियम, 1994 (1994 का 1) के अधीन हो।
- 9.26 “निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो निर्यात करता है, निर्यात करना चाहता है और जो निर्यातक-आयातक कोड नम्बर धारक हो, जब तक अन्यथा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।
- 9.27 “निर्यात दायित्व” का अर्थ है:- लाइसेंस अथवा अनुज्ञा में शामिल उत्पाद अथवा उत्पादों का लाइसेंसिंग या सक्षम प्राधिकारी द्वारा यथा निर्धारित मात्रा अथवा मूल्य अथवा दोनों में निर्यात करने का दायित्व।

- 9.28 “कम्पनी समूह” से अभिप्राय दो या अधिक इन्टरप्राइजेज जो परोक्ष या अपरोक्ष रूप से ऐसी स्थिति में हों—
- (i) अन्य इन्टरप्राइजेज में मताधिकार का 26 प्रतिशत या अधिक भागीदारी होगा, या
 - (ii) अन्य इन्टरप्राइजेज में निदेशक मण्डल के सदस्यों का प्रतिशत 50 प्रतिशत से अधिक हो, या

समूह कम्पनी के लाभ के दावे या ग्रुप के अन्य सदस्यों द्वारा लाभ के दावों के लिए उनके निर्यात को गणना की जायेगी। समूह कम्पनी नीति की किसी अधिसूचित निर्यात संवर्धन योजना के अधीन आवेदन की तारीख को कम से कम 2 वर्ष पूर्व अवस्थित होना चाहिए।

- 9.29 “प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1)” का अर्थ प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-1) से है और “प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2)” का नीति के पैरा 2.4 के पैरा के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित प्रक्रिया-पुस्तक (खण्ड-2) से है।
- 9.30 “आयातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो आयात करता है, आयात करना चाहता है और जो आयातक-निर्यातक कोड नम्बर धारी हो जब तक अन्यथा विशेष रूप से छूट न दी गई हो।
- 9.31 “संरचनात्मक सुविधाओं” का अर्थ हे औद्योगिक, व्यावसायिक और सामाजिक संरचना या कोई अन्य सुविधा जो कि यथाअधिसूचित विशेष आर्थिक क्षेत्र के विकास के लिए हो।
- 9.32 “आई टी सी (एच एस)” का अर्थ निर्यात और आयात मदों के आई टी सी (एच एस) वर्गीकरण से है।
- 9.33 “जाबिंग” का अर्थ है-जाब वर्कर को आपूर्ति कच्चे माल या अर्ध-परिष्कृत माल का प्रसंस्करण या उसमें परिवर्तन करना ताकि प्रक्रिया का कोई हिस्सा या संपूर्ण प्रक्रिया पूरी हो सके जिसके परिणामस्वरूप वस्तु का विनिर्माण या परिष्करण हो या कोई भी कार्रवाई जो उपरोक्त प्रक्रिया के लिए जरूरी हो।
- 9.34 “लाइसेंसिंग प्राधिकारी” का अर्थ उस प्राधिकारी से है जो अधिनियम/आदेश के अधीन लाइसेंस देने के लिए सक्षम हो।
- 9.35 “लाइसेंसिंग वर्ष” का अर्थ उस वर्ष से है जो 1 अप्रैल से आरम्भ होकर आगामी वर्ष के 31 मार्च को समाप्त हो ।
- 9.36 “होटल प्रबंधन” से अभिप्राय तीन स्टार या ऊपर के होटल/होटल श्रृंखला द्वारा होटल चलाना/होटल श्रृंखला तथा होटल प्रबंधन चलाने के मध्य कम से कम तीन वर्ष के दौरान एक प्रबंधन चलाने के करार के अधीन प्रबंधन से है। प्रबंधन करार होटल चलाने के प्रबंधन/कार्यकलापों के क्षेत्र आवश्यक रूप शामिल किया जायेगा।

- 9.37 “विनिर्माण” का अर्थ है-विशेष नाम, गुण या उपयोग वाला नया उत्पाद जो हाथ अथवा मशीन से बनाया गया, उत्पन्न किया गया, गढ़ा गया, संयोजित किया गया, संसाधित किया गया अथवा तैयार किया गया हो और उसमें ऐसे संसाधन शामिल हैं, जैसे रेफ्रिजेशन, पुनः पैकिंग, पौलिशिंग, लेबलिंग, रि-कन्डीशनिंग, नरम्मत, रि-मेकिंग, रि-फर्बिशिंग, टेस्टिंग, कैलिब्रेशन, रि-इन्जीनिरिंग और अलग-अलग विनिर्माण में इस नीति के उद्देश्य के लिए कृषि, जलचर पालन, पशु पालन, पुष्पोदपादन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन और रेशम-उत्पादन, अंगूरोत्पादन एवं खनन भी शामिल हैं।
- 9.38 “विनिर्माता निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो माल का निर्माण करता है तथा उनका निर्यात करता है अथवा ऐसे माल का निर्यात करना चाहता है।
- 9.39 “एम. ए. आई.” का बाज़ार पहुंच पहल से है।
- 9.40 “व्यापारी निर्यातक” का अर्थ उस व्यक्ति से है जो व्यापार के कार्य और निर्यात के कार्य में संलग्न हो अथवा माल निर्यात करना चाहता हो।
- 9.41 “एन एफ ई” का अर्थ निर्यात की प्रतिशतता के रूप में निवल विदेशी मुद्रा अर्जन से है।
- 9.42 “अधिसूचना” का अर्थ उस अधिसूचना से है जो सरकारी राजपत्र में प्रकाशित की जाए।
- 9.43 “आदेश” का अर्थ है अधिनियम के तहत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाया गया आदेश।
- 9.44 “पुर्जे” का अर्थ है उपसंयोजन या संयोजन का एक तत्व जो सामान्यतया स्वयं उपयोगी न हो और जो रख-रखाव के उद्देश्य के लिए आगे से असंयोजन के लिए संशोधन करने के योग्य न हो। “पुर्जा” एक संघटक अथवा उपसाधन हो सकता है।
- 9.45 “व्यक्ति” का अर्थ है कोई व्यक्ति विशेष फर्म, सोसायटी, कम्पनी, कार्पोरेशन अथवा अन्य कोई वैध व्यक्ति।
- 9.46 “नीति” का अर्थ है समय-समय पर यथासंशोधित निर्यात और आयात नीति, 2002-2007
- 9.47 “निर्धारित” का अर्थ है विदेश व्यापार (विकास और विनियम) अधिनियम, 1992 (1992 की संख्या 22) अथवा इसके अन्तर्गत बनाये गए नियम और आदेश या नीति के तहत निर्धारित से है।

9.48 “सार्वजनिक सूचना” का अर्थ नीति के पैरा 4.11 के प्रावधानों के अधीन प्रकाशित सार्वजनिक सूचना से है।

9.49 “कच्ची सामग्री” का अर्थ है:

1. मूल सामग्री जिसकी माल के विनिर्माण में आवश्यकता होती है, परन्तु वह अभी कच्ची, प्राकृतिक, अपरिष्कृत अथवा अविनिर्मित अवस्था में हो, और
2. किसी विनिर्माण के लिए वह सामग्री या माल जिसकी उसे विनिर्माण प्रक्रिया में आवश्यकता होती हो, चाहे वह सामग्री या माल वास्तव में पहले से विनिर्मित हो या संसाधित किया जाए या वह अब भी कच्ची या प्राकृतिक अवस्था में हो।

9.50 “पंजीकरण सह सदस्यता प्रमाण पत्र” (आर.सी.एम.सी) का तात्पर्य नीति या प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-1) में यथा निर्धारित किसी निर्यात संवर्धन परिषद या किसी अन्य सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रदान किए गए पंजीकरण सह-सदस्यता प्रमाण-पत्र से है।

9.51 “नियमों” का अर्थ है अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाए गए नियम।

9.52 “सेवाओं” में, सेवाओं के व्यापार पर सामान्य करार के अन्तर्गत आने वाला सभी व्यापारिक सेवाएं और मुक्त विदेशी मुद्रा अर्जित करना शामिल है।

9.53 “सेवा प्रदान करने वाला” का अर्थ है वह व्यक्ति जो:-

1. भारत से किसी और देश के लिए सेवा प्रदान करता है,
2. भारत में किसी और देश के उपभोक्ता को भारत से प्रदान की गई सेवा की आपूर्ति करता है, और
3. भारत से किसी अन्य देश की धरती पर व्यापारिक या भौतिक उपस्थिति के माध्यम से सेवा की आपूर्ति करता है।
4. भारत में निर्यातों से सम्बन्धित सेवा की आपूर्ति जिसका भुगतान मुक्त विदेशी मुद्रा में किया गया हो या भारतीय मुद्रा जिसे भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अन्यथा मुक्त विदेशी मुद्रा माना हो।

9.54 “एस ई जेड” का तात्पर्य विशेष आर्थिक क्षेत्र है जिसे वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, वाणिज्य विभाग द्वारा अधिसूचित किया गया है।

9.55 “जहाज” का अर्थ समुद्र से किए जाने वाले व्यापार या समुद्रतट पर किए जाने वाले व्यापार के लिए प्रयुक्त सभी प्रकार के पोतों से है इसमें पुराने पोत भी शामिल हैं।

- 9.56 “एस आई ओ एन” का अर्थ विदेश व्यापार महानिदेशालय द्वारा प्रक्रिया पुस्तक (खण्ड-2) 2002-2007 में अधिसूचित अनुमोदन बोर्ड द्वारा अनुमोदित मानक निवेश उत्पादन मानदण्डों से है।
- 9.57 “अतिरिक्त पुर्जा” का तात्पर्य प्रतिस्थापन के लिए किसी उप-असेम्बली या असेम्बली के अर्थात् किसी समान या एक ही तरह के भाग या उप-असेम्बली के स्थान पर रखे जाने वाले किसी भाग से है। अतिरिक्त पुर्जे में संघटक या सहायक उपकरण शामिल होते हैं।
- 9.58 “विनिर्दिष्ट” का तात्पर्य इस नीति के प्रावधानों द्वारा या के तहत विनिर्दिष्ट से है।
- 9.59 “स्टार धारक” का आशय उस निर्यातक से है जो विदेश व्यापार महानिदेशक या विकास आयुक्त द्वारा निर्यात सदन/व्यापार सदन अथवा विदेश व्यापार महानिदेशक द्वारा स्टार व्यापार सदन/सुपर स्टार व्यापार सदन के रूप में मान्यता दी गई हो।
- 9.60 “एस टी पी” का अर्थ साफ्टवेयर टेक्नालॉजी पार्क से है।
- 9.61 “सहायक विनिर्माण” का अर्थ है कोई भी व्यक्ति जो किसी उत्पाद या हिस्सों/उपार्गों/संघटकों का विनिर्माण निर्यात के लिए निर्यातक को उत्पादक और आपूर्ति करता है। सहायक विनिर्माता का नाम निर्यात दस्तावेजों पर अवश्य निर्दिष्ट करना चाहिए।
- 9.62 “तीसरी पार्टी द्वारा निर्यात” का आशय है निर्यातक या विनिर्माता द्वारा तीसरी पार्टी की ओर से किए गए निर्यात। ऐसे मामलों में शिपिंग बिल निर्यातक/विनिर्माता और तीसरी पार्टी दोनों के नामों का उल्लेख होगा।
- 9.63 “विनिमय मूल्य” विनिमय मूल्य से अभिप्राय “ट्रांजेक्शन वैल्यू” जो कि शासकीय विभाग के सीमा शुल्क मूल्यांकन नियम में बताई गई है।
- 9.64 “यूनिट अनुमोदन समिति” का अर्थ है इसके क्षेत्राधिकार के अन्तर्गत आने वाली विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाई से सम्बन्धित विषयों पर प्रस्तावों पर विचार-विमर्श करने के लिए विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए अधिसूचित समिति।
- 9.65 “वन्य प्राणी” का अर्थ है कोई वन्य प्राणी (सुरक्षा) अधिनियम, 1972 के खण्ड- 2(36) में परिभाषित है।

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY**(Department of Commerce)****NOTIFICATION**

New Delhi, the 31st August, 2004

No. 1/2004—2009

S. O. 973(E).—In exercise of powers conferred by Section 5 of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) read with paragraph 1.2 of the Foreign Trade Policy, 2004—2009, the Central Government hereby notifies the Foreign Trade Policy 2004—2009 as contained in Annexure to this notification. The Policy shall come into force from 1st September, 2004.

This issues in public interest.

[F. No. 01/94/180/Foreign Trade Policy/AM05/PC-IV]

GOPAL K. PILLAI, Director General of Foreign Trade
and Ex Officio Addl. Secy.

ANNEXURE

FOREIGN TRADE POLICY

PREAMBLE

CONTEXT

For India to become a major player in world trade, an all encompassing, comprehensive view needs to be taken for the overall development of the country's foreign trade. While increase in exports is of vital importance, we have also to facilitate those imports which are required to stimulate our economy. Coherence and consistency among trade and other economic policies is important for maximizing the contribution of such policies to development. Thus, while incorporating the existing practice of enunciating an annual Exim Policy, it is necessary to go much beyond and take an integrated approach to the developmental requirements of India's foreign trade. This is the context of the new Foreign Trade Policy.

OBJECTIVES

Trade is not an end in itself, but a means to economic growth and national development. The primary purpose is not the mere earning of foreign exchange, but the stimulation of greater economic activity. The Foreign Trade Policy is rooted in this belief and built around two major objectives. These are:

- (i) To double our percentage share of global merchandise trade within the next five years; and
- (ii) To act as an effective instrument of economic growth by giving a thrust to employment generation.

STRATEGY

These objectives are proposed to be achieved by adopting, among others, the following strategies:

- (i) Unshackling of controls and creating an atmosphere of trust and transparency to unleash the innate entrepreneurship of our businessmen, industrialists and traders.
- (ii) Simplifying procedures and bringing down transaction costs.
- (iii) Neutralizing incidence of all levies and duties on inputs used in export products, based on the fundamental principle that duties and levies should not be exported.
- (iv) Facilitating development of India as a global hub for manufacturing, trading and services.
- (v) Identifying and nurturing special focus areas which would generate additional employment opportunities, particularly in semi-urban and rural areas, and developing a series of 'Initiatives' for each of these.
- (vi) Facilitating technological and infrastructural upgradation of all the sectors of the Indian

economy, especially through import of capital goods and equipment, thereby increasing value addition and productivity, while attaining internationally accepted standards of quality.

- (vii) Avoiding inverted duty structures and ensuring that our domestic sectors are not disadvantaged in the Free Trade Agreements/Regional Trade Agreements/Preferential Trade Agreements that we enter into in order to enhance our exports.
- (viii) Upgrading our infrastructural network, both physical and virtual, related to the entire Foreign Trade chain, to international standards.
- (ix) Revitalising the Board of Trade by redefining its role, giving it due recognition and inducting experts on Trade Policy.
- (x) Activating our Embassies as key players in our export strategy and linking our Commercial Wings abroad through an electronic platform for real time trade intelligence and enquiry dissemination.

PARTNERSHIP:

The new Policy envisages merchant exporters and manufacturer exporters, business and industry as partners of Government in the achievement of its stated objectives and goals. Prolonged and unnecessary litigation vitiates the premise of partnership. In order to obviate the need for litigation and nurture a constructive and conducive atmosphere, a suitable Grievance Redressal Mechanism will be established which, it is hoped, would substantially reduce litigation and further a relationship of partnership.

The dynamics of a liberalized trading system sometimes results in injury caused to domestic industry on account of dumping. When this happens, effective measures to redress such injury will be taken.

ROADMAP:

This Policy is essentially a roadmap for the development of India's foreign trade. It contains the basic principles and points the direction in which we propose to go. By virtue of its very dynamics, a trade policy cannot be fully comprehensive in all its details. It would naturally require modification from time to time. We propose to do this through continuous updation, based on the inevitable changing dynamics of international trade. It is in partnership with business and industry that we propose to erect milestones on this roadmap.

KAMAL NATH
MINISTER FOR COMMERCE & INDUSTRY

NEW DELHI
31ST AUGUST, 2004

CHAPTER-1A**LEGAL FRAMEWORK**

<i>Preamble</i>	1.1	The Preamble spells out the broad framework and is an integral part of the Foreign Trade Policy.
<i>Duration</i>	1.2	In exercise of the powers conferred under Section 5 of The Foreign Trade (Development and Regulation Act), 1992 (No. 22 of 1992), the Central Government hereby notifies the Foreign Trade Policy for the period 2004-2009 incorporating the Export and Import Policy for the period 2002-2007, as modified. This Policy shall come into force with effect from 1 st September, 2004 and shall remain in force upto 31 st March, 2009, unless as otherwise specified.
<i>Amendments</i>	1.3	The Central Government reserves the right in public interest to make any amendments to this Policy in exercise of the powers conferred by Section-5 of the Act. Such amendment shall be made by means of a Notification published in the Gazette of India.
<i>Transitional Arrangements</i>	1.4	Any Notifications made or Public Notices issued or anything done under the previous Export/Import policies, and in force immediately before the commencement of this Policy shall, in so far as they are not inconsistent with the provisions of this Policy, continue to be in force and shall be deemed to have been made, issued or done under this Policy. Licences, certificates and permissions issued before the commencement of this Policy shall continue to be valid for the purpose and duration for which such licence, certificate or permission was issued unless otherwise stipulated.
	1.5	In case an export or import that is permitted freely under this Policy is subsequently subjected to any restriction or regulation, such export or import will ordinarily be permitted notwithstanding such restriction or regulation, unless otherwise stipulated, provided that the shipment of the export or import is made within the original validity of an irrevocable letter of credit established before the date of imposition of such restriction.

CHAPTER -1B**SPECIAL FOCUS INITIATIVES*****Special Focus Initiatives***

- 1B.1 With a view to doubling our percentage share of global trade within 5 years and expanding employment opportunities, especially in semi urban and rural areas, certain special focus initiatives have been identified for the agriculture, handlooms, handicraft, gems & jewellery and leather sectors.

Government of India shall make concerted efforts to promote exports in these sectors by specific sectoral strategies that shall be notified from time to time.

New Sectoral Initiatives to be announced

Further Sectoral Initiatives in other sectors will also be announced from time to time.

For the present, the thrust sectors indicated below shall be extended the following facilities:

(i) Agriculture:

- (a) A new scheme called the Vishesh Krishi Upaj Yojana (Special Agricultural Produce Scheme) for promoting the export of fruits, vegetables, flowers, minor forest produce, and their value added products has been introduced (Para 3.8).
- (b) Funds shall be earmarked under ASIDE for development of Agri Export Zones (AEZ)
- (c) Import of capital goods shall be permitted duty free under the EPCG Scheme
- (d) Units in AEZ shall be exempt from Bank Guarantee under the EPCG Scheme.
- (e) Capital goods imported under EPCG shall be permitted to be installed anywhere in the AEZ.
- (f) Import of restricted items, such as panels, shall be allowed under the various export promotion schemes.
- (g) Import of inputs such as pesticides shall be permitted under the Advance Licence for agro exports.
- (h) New towns of export excellence with a threshold limit of Rs 250 crore shall be notified.

(ii) Handlooms:

- (a) Specific funds would be earmarked under MAI/MDA Scheme for promoting handloom exports.

- (b) Duty free import entitlement of specified trimmings and embellishments shall be 5% of FOB value of exports during the previous financial year.
- (c) Duty free import entitlement of hand knotted carpet samples shall be 1% of FOB value of exports during the previous financial year.
- (d) Duty free import of old pieces of hand knotted carpets on consignment basis for re-export after repair shall be permitted.
- (e) New towns of export excellence with a threshold limit of Rs 250 crore shall be notified.

(iii) Handicrafts:

- (a) New Handicraft SEZs shall be established which would procure products from the cottage sector and do the finishing for exports.
- b) Duty free import entitlement of trimmings and embellishments shall be 5% of the FOB value of exports during the previous financial year. The entitlement is broad banded, and shall extend also to merchant exporters tied up with supporting manufacturers.
- (c) The Handicraft Export Promotion Council shall be authorized to import trimmings, embellishments and consumables on behalf of those exporters for whom directly importing may not be viable.
- (d) Specific funds would be earmarked under MAI & MDA Schemes for promoting Handicraft exports.
- (e) CVD is exempted on duty free import of trimmings, embellishments and consumables.
- (f) New towns of export excellence with a reduced threshold limit of Rs 250 crore shall be notified.

(iv) Gems & Jewellery:

- (a) Import of gold of 18 carat and above shall be allowed under the replenishment scheme.
- (b) Duty free import entitlement of consumables for metals other than Gold, Platinum shall be 2% of FOB value of exports during the previous financial year.
- (c) Duty free import entitlement of commercial samples shall be Rs. 100,000.
- (d) Duty free re-import entitlement for rejected jewellery shall be 2% of the FOB value of exports.

- (e) Cutting and polishing of gems and jewellery, shall be treated as manufacturing for the purposes of exemption under Section 10A of the Income Tax Act.
- (v) Leather and Footwear:
 - (a) Duty free import entitlement of specified items shall be 5% of FOB value of exports during the preceding financial year.
 - (b) The duty free entitlement for the import of trimmings, embellishments and footwear components for footwear (leather as well as synthetic), gloves, travel bags and handbags shall be 3% of FOB value of exports of the previous financial year. The entitlement shall also cover packing material, such as printed and non printed shoeboxes, small cartons made of wood, tin or plastic materials for packing footwear.
 - (c) Machinery and equipment for Effluent Treatment Plants shall be exempt from basic customs duty.
 - (d) Re-export of unsuitable imported materials such as raw hides & skins and wet blue leathers is permitted.
 - (e) CVD is exempted on lining and interlining material notified at S.No 168 of Customs Notification No 21/ 2002 dated 01.03.2002.
 - (f) CVD is exempted on raw, tanned and dressed fur skins falling under Chapter 43 of ITC(HS).

***Optimum
Development
programme for
Pragati Maidan***

- 1B.2 In order to showcase our industrial and trade prowess to its best advantage and leverage existing facilities to enhance the quantity of space and service, Pragati Maidan will be transformed into a world-class complex with visitor friendliness ingress and egress system. The complex utilisation will be improved, increased and diversified. there shall be brand new, state-of-the-art, environmentally-controlled, air-conditioned exhibition areas, and Permanent Exhibition Marts. In addition, a large Convention Centre to accommodate ten thousand delegates will be developed, with multiple and flexible hall spaces, auditoria and meeting rooms with hi-tech equipment. A year-round Food and Beverage destination will be developed, with a large number of outlets covering all cuisines and pricing levels. There will be a multi-level park to accommodate over nine thousand vehicles within the envelope of Pragati Maidan.

CHAPTER-1C

BOARD OF TRADE

<i>Board of Trade</i>	1C.1	The Board of Trade shall be revamped and given a clear and dynamic role in advising government on relevant issues connected with Foreign Trade Policy. There would be a process of continuous interaction between the Board of Trade and Government in order to achieve the desired objective of boosting India's exports.
<i>Terms of Reference</i>	1C.2	<p>The Board of Trade would have the following terms of reference:</p> <ol style="list-style-type: none"> I To advise the Government on Policy measures for preparation and implementation of both short and long term plans for increasing exports in the light of emerging national and international economic scenario; II To review export performance of various sectors, identify constraints and suggest industry specific measures to optimize export earnings; III To examine the existing institutional framework for imports & exports and suggest practical measures for further streamlining to achieve the desired objectives; IV To review the policy instruments and procedures for imports & exports and suggest steps to rationalize and channelise such schemes for optimum use; V To examine issues which are considered relevant for promotion of India's foreign trade, and to strengthen the international competitiveness of Indian goods and services. VI To commission studies for furtherance of the above objectives.
<i>Composition</i>	1C.3	Government shall nominate an eminent person or expert on trade policy to be President of the Board of Trade. Government shall also nominate 25 persons, of whom at least 10 will be experts in trade policy. In addition, Chairmen of recognized Export Promotion Councils and President or Secretary-Generals of National Chambers of Commerce will be ex-officio members.
<i>Meetings</i>	1C.4	The Board will meet at least once every quarter and make recommendations to Government on issues pertaining to its terms of reference.
<i>Sub-committee</i>	1C.5	The Board of Trade will have the power to set up sub-committees and to co-opt experts to these, to make recommendations on specific sectors and objectives.
<i>Secretariat and Budget Head</i>	1C.6	Board of Trade will have a Secretariat and Budget Head and shall be serviced by the Department of Commerce.

CHAPTER-2

GENERAL PROVISIONS REGARDING IMPORTS AND EXPORTS

- | | | |
|--|-----|--|
| <i>Exports and Imports free unless regulated</i> | 2.1 | Exports and Imports shall be free, except in cases where they are regulated by the provisions of this Policy or any other law for the time being in force. The item wise export and import policy shall be, as specified in ITC(HS) published and notified by Director General of Foreign Trade, as amended from time to time. |
| <i>Compliance with Laws</i> | 2.2 | Every exporter or importer shall comply with the provisions of the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992, the Rules and Orders made thereunder, the provisions of this Policy and the terms and conditions of any licence/certificate/permission granted to him, as well as provisions of any other law for the time being in force. All imported goods shall also be subject to domestic Laws, Rules, Orders, Regulations, technical specifications, environmental and safety norms as applicable to domestically produced goods. No import or export of rough diamonds shall be permitted unless the shipment parcel is accompanied by Kimberley Process (KP) Certificate required under the procedure specified by the Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC). |
| <i>Interpretation of Policy</i> | 2.3 | <p>If any question or doubt arises in respect of the interpretation of any provision contained in this Policy, or regarding the classification of any item in the ITC(HS) or Handbook (Vol. 1) or Handbook (Vol. 2), or Schedule Of DEPB Rate the said question or doubt shall be referred to the Director General of Foreign Trade whose decision thereon shall be final and binding.</p> <p>If any question or doubt arises whether a licence/certificate/permission has been issued in accordance with this Policy or if any question or doubt arises touching upon the scope and content of such documents, the same shall be referred to the Director General of Foreign Trade whose decision thereon shall be final and binding.</p> |
| <i>Procedure</i> | 2.4 | The Director General of Foreign Trade may, in any case or class of cases, specify the procedure to be followed by an exporter or importer or by any licensing or any other competent authority for the purpose of implementing the provisions of the Act, the Rules and the Orders made thereunder and this Policy. Such procedures shall be included in the Handbook (Vol. 1), Handbook (Vol. 2), Schedule of DEPB Rate and in ITC(HS) and published by means of a Public |

Notice. Such procedures may, in like manner, be amended from time to time.

The Handbook (Vol.1) is a supplement to the Foreign trade Policy and contains relevant procedures and other details. The procedure of availing benefits under various schemes of the Policy are given in the Handbook (Vol.1).

Exemption from Policy/Procedure

- 2.5 Any request for relaxation of the provisions of this Policy or of any procedure, on the ground that there is genuine hardship to the applicant or that a strict application of the Policy or the procedure is likely to have an adverse impact on trade, may be made to the Director General of Foreign Trade for such relief as may be necessary. The Director General of Foreign Trade may pass such orders or grant such relaxation or relief, as he may deem fit and proper.

The Director General of Foreign Trade may, in public interest, exempt any person or class or category of persons from any provision of this Policy or any procedure and may, while granting such exemption, impose such conditions as he may deem fit. Such request may be considered only after consulting Advance Licensing Committee (ALC), if the request is in respect of a provision of Chapter-4 (excluding any provision relating to Gem & Jewellery sector) of the Policy/Procedure. However, any such request in respect of a provision other than Chapter-4 and Gem & Jewellery sector as given above may be considered only after consulting Policy Relaxation Committee.

Principles of Restriction

- 2.6 LEFT may, through a notification, adopt and enforce any measure necessary for:-
- i. Protection of public morals.
 - ii. Protection of human, animal or plant life or health.
 - iii. Protection of patents, trademarks and copyrights and the prevention of deceptive practices.
 - iv. Prevention of use of prison labour.
 - v. Protection of national treasures of artistic, historic or archaeological value.
 - vi. Conservation of exhaustible natural resources.
 - vii. Protection of trade of fissionable material or material from which they are derived; and
 - viii. Prevention of traffic in arms, ammunition and implements of war.

<i>Restricted Goods</i>	2.7	Any goods, the export or import of which is restricted under ITC(HS) may be exported or imported only in accordance with a licence/certificate/permission or a public notice issued in this behalf.
<i>Terms and Conditions of a Licence/Certificate/Permission</i>	2.8	<p>Every licence/certificate/permission shall be valid for the period of validity specified in the licence/certificate/permission and shall contain such terms and conditions as may be specified by the licensing authority which may include:</p> <ol style="list-style-type: none"> The quantity, description and value of the goods; Actual User condition; Export obligation; The value addition to be achieved; and The minimum export price.
<i>Licence/Certificate/Permission not a Right</i>	2.9	No person may claim a licence/certificate/permission as a right and the Director General of Foreign Trade or the licensing authority shall have the power to refuse to grant or renew a licence/certificate/permission in accordance with the provisions of the Act and the Rules made there under.
<i>Penalty</i>	2.10	If a licence/certificate/permission holder violates any condition of the licence/certificate/permission or fails to fulfill the export obligation, he shall be liable for action in accordance with the Act, the Rules and Orders made there under, the Policy and any other law for the time being in force.
<i>State Trading</i>	2.11	Any goods, the import or export of which is governed through exclusive or special privileges granted to State Trading Enterprise(s), may be imported or exported by the State Trading Enterprise(s) as specified in the ITC(HS) Book subject to the conditions specified therein. The Director General of Foreign Trade may, however, grant a licence/certificate/permission to any other person to import or export any of these goods. In respect of goods the import or export of which is governed through exclusive or special privileges granted to State Trading Enterprise(s), the State Trading Enterprise(s) shall make any such purchases or sales involving imports or exports solely in accordance with commercial considerations, including price, quality, availability, marketability, transportation and other conditions of purchase or sale. These enterprises shall act in a non discriminatory manner and shall afford the enterprises of other countries adequate opportunity, in accordance with customary business practices, to compete for participation in such purchases or sales.

Importer-Exporter Code Number	2.12	No export or import shall be made by any person without an Importer-Exporter Code (IEC) number unless specifically exempted. An Importer-Exporter Code (IEC) number shall be granted on application by the competent authority in accordance with the procedure specified in the Handbook (Vol. I).
Trade with Neighbouring Countries	2.13	The Director General of Foreign Trade may issue, from time to time, such instructions or frame such schemes as may be required to promote trade and strengthen economic ties with neighbouring countries.
Transit Facility	2.14	Transit of goods through India from or to countries adjacent to India shall be regulated in accordance with the bilateral treaties between India and those countries and will be subject to such restrictions as may be specified by DGFT in accordance with International Conventions.
Trade with Russia under Debt-Repayment Agreement	2.15	In the case of trade with Russia under the Debt Repayment Agreement, the Director General of Foreign Trade may issue, from time to time, such instructions or frame such schemes as may be required, and anything contained in this Policy, in so far as it is inconsistent with such instructions or schemes, shall not apply.
Actual User Condition	2.16	<p>Capital goods, raw materials, intermediates, components, consumables, spares, parts, accessories, instruments and other goods, which are importable without any restriction, may be imported by any person.</p> <p>However, if such imports require a licence/certificate/permission, the actual user alone may import such goods unless the actual user condition is specifically dispensed with by the licensing authority.</p>
Second Hand Goods	2.17	<p>All second hand goods, excepting second hand capital goods, shall be restricted for imports and may be imported only in accordance with the provisions of this Policy, ITC(HS), Handbook (Vol. I), Public Notice or a licence/certificate/permission issued in this behalf.</p> <p>Import of second hand capital goods, including refurbished/reconditioned spares, shall be allowed freely.</p>
Import of samples	2.18	Import of samples shall be governed by the provisions given in Handbook (Vol. I).
Import of Gifts	2.19	Import of gifts shall be permitted where such goods are otherwise freely importable under this Policy. In other cases,

a Customs Clearance Permit (CCP) shall be required from the DGFT.

<i>Passenger Baggage</i>	2.20	<p>Bonafide household goods and personal effects may be imported as part of passenger baggage as per the limits, terms and conditions thereof in the Baggage Rules notified by the Ministry of Finance.</p> <p>Samples of such items that are otherwise freely importable under this Policy may also be imported as part of passenger baggage without a licence/certificate/permission.</p> <p>Exporters coming from abroad are also allowed to import drawings, patterns, labels, price tags, buttons, belts, trimming and embellishments required for export, as part of their passenger baggage without a licence/certificate/permission.</p>
<i>Import on Export basis</i>	2.21	<p>New or second hand capital goods, equipments, components, parts and accessories, containers meant for packing of goods for exports, jigs, fixtures, dies and moulds may be imported for export without a licence/certificate/permission on execution of Legal Undertaking/Bank Guarantee with the Customs Authorities provided that the item is freely exportable without any conditionality/requirement of licence/permission as may be required under ITC(HS) Schedule II.</p>
<i>Re-import of goods repaired abroad</i>	2.22	<p>Capital goods, equipments, components, parts and accessories, whether imported or indigenous, except those restricted under ITC (HS) may be sent abroad for repairs, testing, quality improvement or up gradation or standardization of technology and re-imported without a licence/certificate/permission.</p>
<i>Import of goods used in projects abroad</i>	2.23	<p>After completion of the projects abroad, project contractors may import, without a licence/certificate/permission, used goods including capital goods provided they have been used for at least one year.</p>
<i>Sale on High Seas</i>	2.24	<p>Sale of goods on high seas for import into India may be made subject to this Policy or any other law for the time being in force.</p>
<i>Import under Lease Financing</i>	2.25	<p>Permission of licensing authority is not required for import of new capital goods under lease financing.</p>
<i>Clearance of Goods from Customs</i>	2.26	<p>The goods already imported/shipped/arrived, in advance, but not cleared from Customs may also be cleared against the licence/certificate/permission issued subsequently.</p>

Execution of BG/LUT	2.27	Wherever any duty free import is allowed or where otherwise specifically stated, the importer shall execute a Legal Undertaking (LUT)/Bank Guarantee (BG)/Bond with the Customs Authority before clearance of goods through the Customs, in the manner as may be prescribed. In case of indigenous sourcing, the licence/certificate/permission holder shall furnish LUT /BG /Bond to the licensing authority before sourcing the material from the indigenous supplier/nominated agency.
Exemption from Bank Guarantee	2.27.1	All the exporters who have an export turnover of at least Rupees 5 crore in the current or preceding licencing year and have a good track record of three years of exports will be exempted from furnishing a BG for any of the schemes under this Policy and may furnish a LUT in lieu of BG.
Private/Public Bonded Warehouses for Imports	2.28	<p>Private/Public bonded warehouses may be set up in the Domestic Tariff Area as per the terms and conditions of notification issued by Department of Revenue.</p> <p>Any person may import goods except prohibited items, arms and ammunition, hazardous waste and chemicals and warehouse them in such private/public bonded warehouses.</p> <p>Such goods may be cleared for home consumption in accordance with the provisions of this Policy and against Licence/certificate/permission, wherever required. Customs duty as applicable shall be paid at the time of clearance of such goods.</p> <p>If such goods are not cleared for home consumption within a period of one year or such extended period as the custom authorities may permit, the importer of such goods shall re-export the goods.</p>
Free Exports	2.29	<p>All goods may be exported without any restriction except to the extent such exports are regulated by ITC(HS) or any other provision of this Policy or any other law for the time being in force.</p> <p>The Director General of Foreign Trade may, however, specify through a public notice such terms and conditions according to which any goods, not included in the ITC(HS), may be exported without a licence/certificate/permission.</p>
Export of Samples	2.30	Export of samples and Free of charge goods shall be governed by the provisions given in Handbook (Vol. 1).

<i>Export of Passenger Baggage</i>	2.31	Bona fide personal baggage may be exported either along with the passenger or, if unaccompanied, within one year before or after the passenger's departure from India. However, items mentioned as Restricted in ITC(HS) shall require a licence/certificate/permission.
<i>Export of Gifts</i>	2.32	<p>Goods, including edible items, of value not exceeding Rs. 5,00,000/- in a licensing year, may be exported as a gift.</p> <p>However, items mentioned as restricted for exports in ITC(HS) shall not be exported as a gift, without a licence/certificate/permission.</p>
<i>Export of Spares</i>	2.33	Warranty spares, whether indigenous or imported, of plant, equipment, machinery, automobiles or any other goods, except restricted under ITC (HS), may be exported along with the main equipment or subsequently but within the contracted warranty period of such goods subject to approval of RBI.
<i>Third Party Exports</i>	2.34	Third party exports, as defined in Chapter 9 shall be allowed under the Policy.
<i>Export of Imported Goods</i>	2.35	<p>Goods imported, in accordance with this Policy, may be exported in the same or substantially the same form without a licence/certificate/permission provided that the item to be imported or exported is not mentioned as restricted for import or export in the ITC(HS).</p> <p>Exports of such goods imported against payment in freely convertible currency would be permitted against payment in freely convertible currency.</p>
	2.36	Goods, including those mentioned as restricted item for import (except prohibited items) may be imported under Customs Bond for export in freely convertible currency without a licence/certificate/permission provided that the item is freely exportable without any conditionality/requirement of licence/permission as may be required under ITC (HS) Schedule II.
<i>Export of Replacement Goods</i>	2.37	Goods or parts thereof on being exported and found defective/damaged or otherwise unfit for use may be replaced free of charge by the exporter and such goods shall be allowed clearance by the customs authorities provided that the replacement goods are not mentioned as restricted items for exports in ITC (HS).
<i>Export of Repaired Goods</i>	2.38	Goods or parts, except restricted under ITC (HS), thereof on being exported and found defective, damaged or otherwise unfit for use may be imported for repair and subsequent re-export.

		Such goods shall be allowed clearance without a licence/certificate/permission and in accordance with customs notification issued in this behalf.
<i>Private Bonded Warehouses for Exports</i>	2.39	<p>Private bonded warehouses exclusively for exports may be set up in DTA as per the terms and conditions of the notifications issued by Department of Revenue.</p> <p>Such warehouses shall be entitled to procure the goods from domestic manufacturers without payment of duty. The supplies made by a domestic supplier to the notified warehouses shall be treated as physical exports provided the payments for the same are made in free foreign exchange.</p>
<i>Denomination of Export Contracts</i>	2.40	<p>All export contracts and invoices shall be denominated either in freely convertible currency or Indian rupees but the export proceeds shall be realised in freely convertible currency.</p> <p>However export proceeds against specific exports may also be realized in rupees provided it is through a freely convertible Vostro account of a non resident bank situated in any country other than a member country of Asian Clearing Union (ACU) or Nepal or Bhutan. Additionally, the rupee payment through the Vostro account must be against payment in free foreign currency by the buyer in his non resident bank account. The free foreign exchange remitted by the buyer to his non resident bank (after deducting the bank service charges) on account of this transaction would be taken as the export realization under the export promotion schemes of this Policy.</p> <p>Contracts for which payments are received through the Asian Clearing Union (ACU) shall be denominated in ACU Dollar. The Central Government may relax the provisions of this paragraph in appropriate cases. Export contracts and Invoices can be denominated in Indian rupees against EXIM Bank/ Government of India line of credit.</p>
<i>Realisation of Export Proceeds</i>	2.41	If an exporter fails to realise the export proceeds within the time specified by the Reserve Bank of India, he shall, without prejudice to any liability or penalty under any law for the time being in force, be liable to action in accordance with the provisions of the Act, the Rules and Orders made there under and the provisions of this Policy.
<i>Free movement of export goods</i>	2.42	Consignments of items meant for exports shall not be withheld/delayed for any reason by any agency of the Central/State Government. In case of any doubt, the authorities concerned may ask for an undertaking from the exporter.

<i>No seizure of Stock</i>	2.42.1	No seizure of stock shall be made by any agency so as to disrupt the manufacturing activity and delivery schedule of export goods. In exceptional cases, the concerned agency may seize the stock on the basis of prima facie evidence. However, such seizure should be lifted within 7 days.
<i>Export Promotion Councils</i>	2.43	The basic objective of Export Promotion Councils is to promote and develop the exports of the country. Each Council is responsible for the promotion of a particular group of products, projects and services. The list of the councils, and their main functions are given in Handbook (Vol. 1).
<i>Registration-cum-Membership Certificate</i>	2.44	Any person, applying for (i) a licence/certificate/permission to import/export, [except items listed as restricted items in ITC(HS)] or (ii) any other benefit or concession under this policy shall be required to furnish Registration-cum-Membership Certificate (RCMC) granted by the competent authority in accordance with the procedure specified in the Handbook (Vol.1) unless specifically exempted under the Policy.
<i>Electronic Data Interchange</i>	2.45	In an attempt to speed up transactions, reduce physical interface and impart transparency in activities related to exports, digitally signed electronic applications with payment through the electronic fund transfer would be encouraged. Such applications shall be cleared within 24 hours and the applicant shall be required to furnish only 50% of the fee mentioned in Appendix- 29 of Handbook (Vol. 1).
<i>Regularization of EO default and settlement of customs duty and interest through Settlement Commission</i>	2.46	With a view to providing assistance to firms who have defaulted under the Foreign Trade Policy for reasons beyond their control as also facilitating the merger, acquisition and rehabilitation of sick units, it has been decided to empower the Settlement Commission in the Central Board of Excise and Customs to decide such cases also with effect from 01.04.2005.
<i>Easing of documentation requirements</i>	2.47	Pending the finalization of Single Common Document (SCD) for international trade, the government departments dealing with exports and imports will honour the permission/licence/certificate issued by the other government departments based on the verification of the export documents like shipping bill, bank realization certificate, packing list, bill of lading etc. and will not insist upon fresh submission of these documents.
<i>Exemption from Service Tax in DTA</i>	2.48.1	For all goods and services which are exported from units in Domestic Tariff Area (DTA), remission of service tax levied shall be allowed.

<i>Exemption from Service Tax in EOU/EHTP/STP/SEZ/BTP</i>	2.48.2	Units in EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ shall be exempted from service tax.
--	--------	---

GRIEVANCE REDRESSAL

<i>DGFT as a facilitator of exports/imports</i>	2.49	DGFT has a commitment to function as a facilitator of exports and imports. The focus is on good governance, which depends on clean, transparent and accountable delivery systems.
<i>Citizen's Charter</i>	2.49.1	DGFT has in place a Citizen's Charter which lays down its commitment to serve importers and exporters. It also gives time schedules for providing services to clients, and details of grievance committees at different levels.
<i>Grievance Redressal Mechanism</i>	2.49.2	In order to facilitate speedy redressal of grievances of trade and industry, a new grievance redressal mechanism has been put into place by a Government Resolution.
<i>Web chat</i>	2.49.3	The office of the Director General of Foreign Trade has opened a chat window on its website for interacting with the trade and industry to reply to queries on the Foreign Trade Policy. This web based interface would be held from 3.00 pm to 5.00 pm on second Wednesday of every month.

CHAPTER-3

PROMOTIONAL MEASURES

***Assistance to States
for Infrastructure
Development of
Exports (ASIDE)***

- 3.1 The State Governments shall be encouraged to participate in promoting exports from their respective states. For this purpose, Department of Commerce has formulated a scheme called ASIDE.

Suitable provision has been made in the Annual Plan of the Department of Commerce for allocation of funds to the states on the twin criteria of gross exports and the rate of growth of exports.

The States shall utilise this amount for developing infrastructure such as roads connecting production centres with the ports, setting up of Inland Container Depots and Container Freight Stations, creation of new State level export promotion industrial parks/zones, augmenting common facilities in the existing zones, equity participation in infrastructure projects, development of minor ports and jetties, assistance in setting up of common effluent treatment facilities, stabilizing power supply and any other activity as may be notified by Department of Commerce from time to time.

***Market Access
Initiative (MAI)***

- 3.2 The Market Access Initiative (MAI) scheme is intended to provide financial assistance for medium term export promotion efforts with a sharp focus on a country and product.

The financial assistance is available for Export Promotion Councils, industry and Trade associations, Agencies of State Governments, Indian Commercial Missions abroad and other eligible entities as may be notified from time to time.

A whole range of activities can be funded under the MAI scheme. These include market studies, setting up of showroom/warehouse, sales promotion campaigns, international departmental stores, publicity campaigns, participation in international trade fairs, brand promotion, registration charges for pharmaceuticals, and testing charges for engineering products etc. Each of these export promotion activities can receive financial assistance from the government ranging from 25% to 100% of the total cost depending upon the activity and the implementing agency, as indicated in the detailed guidelines. The full text of the guidelines can be seen at <http://commerce.nic.in>.

**Marketing
Development
Assistance (MDA)**

- 3.2.1 The Marketing Development Assistance (MDA) Scheme is intended to provide financial assistance for a range of export promotion activities implemented by export promotion councils, industry and trade associations on a regular basis every year.

As per the revised MDA guidelines with effect from 1st April, 2004 assistance under MDA is available for exporters with annual export turnover upto Rs. 5 crores.

These include participation in Trade Fairs and Buyer Seller meets abroad or in India, export promotion seminars, etc.

Further, assistance for participation in Trade Fairs abroad and travel grant is available to such exporters if they travel to countries in one of the four Focus Areas, such as, Latin America, Africa, CIS Region, ASEAN countries, Australia and New Zealand.

For participation in trade fairs, etc, in other areas financial assistance without travel grant is available.

**Meeting Legal
expenses for Trade
related matters**

- 3.2.1.1 Financial assistance would be provided to deserving exporters on the recommendation of Export Promotion Councils for meeting the cost of legal expenses relating to trade related matters.

**Towns of Export
Excellence**

- 3.3 A number of towns in specific geographical locations have emerged as dynamic industrial clusters contributing handsomely to India's exports. It is necessary to grant recognition to these industrial clusters with a view to maximizing their potential and enabling them to move higher in the value chain and tap new markets.

Selected towns producing goods of Rs. 1000 crore or more will be notified as Towns of Exports Excellence on the basis of potential for growth in exports. However for the Towns of Export Excellence in the Handloom, Handicraft, Agriculture and Fisheries sector, the threshold limit would be Rs. 250 crores.

Common service providers in these areas shall be entitled for the facility of the EPCG scheme.

The recognised associations of units will be able to access the funds under the Market Access Initiative scheme for creating focused technological services.

Further such areas will receive priority for assistance for rectifying identified critical infrastructure gaps from the ASIDE scheme.

The notified towns of export excellence are listed in Appendix 41.

Brand Promotion and Quality

3.4.1

The Central Government aims to encourage manufacturers and exporters to attain internationally accepted standards of quality for their products. The Central Government will extend support and assistance to Trade and Industry to launch a nationwide programme on quality awareness and to promote the concept of total quality management.

Test Houses

3.4.2

The Central Government will assist in the modernisation and upgradation of test houses and laboratories in order to bring them at par with international standards.

Quality Complaints/ Disputes

3.4.3

The Regional Sub-Committee on Quality Complaints (RSCQC) set up at the Regional Offices of the Directorate General of Foreign Trade shall investigate quality complaints received from foreign buyers. The guidelines for settlement of quality complaints, in particular, and such other complaints, in general, is given in Appendix-37 of Handbook (Vol. 1).

Trade disputes affecting trade relations

3.4.4

If it comes to the notice of the Director General of Foreign Trade or he has reason to believe that an export or import has been made in a manner that:

- (i) is gravely prejudicial to the trade relations of India with any foreign country; or
- (ii) is gravely prejudicial to the interest of other persons engaged in exports or imports;
- (iii) has brought disrepute to the country;

The Director General Foreign Trade may take action against the exporter or importer concerned in accordance with the provisions of the Act, the Rules and Orders made thereunder and this Policy.

STAR EXPORT HOUSES

Star Export House

3.5.1

Merchant as well as Manufacturer Exporters, Service Providers, Export Oriented Units (EOUs) and Units located in Special Economic Zones (SEZs), Agri Export Zone (AEZ's), Electronic Hardware Technology Parks (EHTPs), Software Technology Parks (STPs) and Bio Technology Parks (BTPs) shall be eligible for applying for status as Star Export Houses.

Status Category

3.5.2 The applicant shall be categorized depending on his total FOB/ FOR export performance during the current plus the previous three years:

Category	Performance (in rupees)
One Star Export House	15 crore
Two Star Export House	100 crore
Three Star Export House	500 crore
Four Star Export House	1500 crore
Five Star Export House	5000 crore

- Note
1. Units in Small Scale Industry/Tiny Sector/Cottage Sector, Units registered with KVICs/KVIBs, Units located in North Eastern States, Sikkim and J&K, Units exporting handloom/handicrafts/hand knotted or silk carpets, exporters exporting to countries in Latin America/CIS/ sub-Saharan Africa as listed in Appendix-17C, units having ISO 9000 (series)/ISO 14000 (series)/WHOGMP/HACCP/SEI CMM level-II and above status granted by agencies listed in Appendix-28A, exports of services and exports of agro products shall be entitled for double weightage of exports made for grant of Star Export House status.
 2. Exports made on re-export basis shall not be counted for the purpose of recognition.
 3. Exports made by a subsidiary of a limited company shall be counted towards export performance of the limited company for the purpose of recognition only if the limited company has a majority share holding in the subsidiary company.

Privileges

- 3.5.2.1 A Star Export House shall be eligible for the following facilities:
- i) Licence/certificate/permissions and Customs clearances for both imports and exports on self-declaration basis.
 - ii) Fixation of Input-Output norms on priority within 60 days;
 - iii) Exemption from compulsory negotiation of documents through banks. The remittance, however, would continue to be received through banking channels;
 - iv) 100% retention of foreign exchange in EEFC account;
 - v) Enhancement in normal repatriation period from 180 days to 360 days;

- vi) Entitlement for consideration under the Target Plus Scheme;
- vii) Exemption from furnishing of Bank Guarantee in Schemes under this Policy.

<i>Validity Period</i>	3.5.3	All status certificates issued or renewed on or after 01.09.2004 shall be valid from 1st April of the licensing year during which the application for the grant of such recognition is made upto 31st March, 2009, unless otherwise specified. On the expiry of such certificate, application for renewal of status certificate shall be required to be made within a period as prescribed in the Handbook (Vol.1). During the said period, the star export house shall be eligible to claim the usual facilities and benefits.
-------------------------------	-------	---

SERVICES EXPORTS

<i>Services exports</i>	3.6.1	Services include all the 161 tradable services covered under the General Agreement on Trade in Services where payment for such services is received in free foreign exchange. A list of services is given in Appendix-36 of Handbook (Vol. 1). All provisions of this Policy shall apply mutatis mutandi to export of services as they apply to goods, unless otherwise specified.
--------------------------------	-------	--

<i>Export Promotion Council for Services</i>	3.6.2	Service exporters are required to register themselves with the Federation of Indian Exporters Organisation. However, software exporters shall register themselves with Electronic and Software Export Promotion Council.
---	-------	--

<i>New Export Promotion Council for Services</i>		In order to give proper guidance and encouragement to the Services Sector, an exclusive Export Promotion Council for Services shall be set up.
---	--	--

The Services Export Promotion Council shall:

- (i) Map opportunities for key services in key markets and develop strategic market access programmes for each component of the matrix.
- (ii) Co-ordinate with sectoral players in undertaking intensive brand building and marketing programmes in target markets.
- (iii) Make necessary interventions with regard to policies, procedures and bilateral/multilateral issues, in co-ordination with recognised nodal bodies of the services industry.

<i>Common Facility Centres</i>	3.6.3	Government shall promote the establishment of Common Facility Centres for use by home-based service providers,
---------------------------------------	-------	--

particularly in areas like Engineering & Architectural design, Multi-media operations, software developers etc., in State and District-level towns, to draw in a vast multitude of home-based professionals into the services export arena.

SERVED FROM INDIA SCHEME

Objective

- 3.6.4.1 The objective is to accelerate the growth in export of services so as to create a powerful and unique 'Served From India' brand, instantly recognized and respected the world over.

Eligibility

- 3.6.4.2 All Service providers who have a total foreign exchange earning of at least Rs.10 lakhs in the preceding or current financial year shall be eligible to qualify for a duty credit entitlement.

For individuals who are service providers, the total foreign exchange earned criteria would be Rs.5 lakhs in the preceding financial year.

Entitlement

- 3.6.4.3 All Service providers (other than hotels and restaurants) shall be entitled to duty credit equivalent to 10% of the foreign exchange earned by them in the preceding financial year.

Hotels & Restaurants

- 3.6.4.4 Hotels of one-star and above (including managed hotels and heritage hotels) approved by the Department of Tourism, and other Service providers in the tourism sector registered with the Department of Tourism, shall be entitled to duty credit equivalent to 5% of the foreign exchange earned by them in the preceding financial year.

Stand-alone restaurants will be entitled to duty credit equivalent to 20% of the foreign exchange earned by them in the preceding financial year.

Note: In the case of one and two star hotels and stand-alone restaurants, the foreign exchange earned through International Credit Cards and sources as may be notified only shall be taken into account for the purposes of computation of duty credit entitlement under the scheme.

Imports allowed

- 3.6.4.5 Duty credit entitlement may be used for import of any capital goods including spares, office equipment, professional equipment, office furniture and consumables, related to the main line of business of the applicant.

In the case of hotels and stand-alone restaurants, the duty credit entitlement may also be used for the import of food items and alcoholic beverages.

Non Transferability 3.6.4.6 The entitlement and the goods imported shall be non-transferable.

Healthcare & Education 3.6.4.7 In order to enable Healthcare and Educational Institutions to have world-class state-of-the-art infrastructure, service providers in these sectors shall, as for other service sectors, be entitled to duty credit equivalent to 10% of the foreign exchange earned by them in the previous financial year.

- (i) The foreign exchange turnover for Healthcare Institutions would include amounts earned through medical treatment, surgery, testing, consultancy and health care provided by the institution.
- (ii) The foreign exchange turnover for Educational Institutions would include amounts earned through the courses and consultancy provided by the institution.
- (iii) In either case, it will not include foreign exchange remittances through any other source including equity participation, donations etc.
- (iv) The capital goods and the consumer goods imported under the duty free entitlement shall have a nexus with the activities of the healthcare or educational institutions concerned.

Special provisions 3.6.4.8 Government reserves the right in public interest to specify from time to time the category or type of service exports which shall not be eligible for calculation of either eligibility or of entitlement.

Similarly, Government may from time to time also notify the goods which shall not be allowed for import under the duty free entitlement certificate issued under the scheme.

TARGET PLUS SCHEME

Objective 3.7.1 The objective of the scheme is to accelerate growth in exports by rewarding Star Export Houses who have achieved a quantum growth in exports. High performing Star Export Houses shall be entitled for a duty credit based on incremental exports substantially higher than the general annual export target fixed (Since the target fixed for 2004-05 is 16 %, the lower limit of performance for qualifying for rewards is pegged at 20% for the current year).

Eligibility Criteria 3.7.2 All Star Export Houses (including Status Holders as defined in para 3.7.2 of Exim Policy 2002-07) which have achieved a

minimum export turnover in free foreign exchange of Rs. 10 crores in the previous licencing year are eligible for consideration under the Target Plus Scheme.

Entitlement

3.7.3

The entitlement under this scheme would be contingent on the percentage incremental growth in fob value of exports in the current year over the previous year, as under:

Percentage incremental growth	Duty Credit Entitlement (as a % of the incremental growth)
20% and above but below 25%	5%
25% or above but below 100%	10%
100% and above	15% (of 100%)

Note: (1) Incremental growth beyond 100% will not qualify for computation of duty credit entitlement.

- (2) For the purpose of this scheme, the export performance shall not be transferred to or transferred from any other exporter. In the case of third party exports, the name of the supporting manufacturer/manufacturer exporter shall be declared.
- (3) Exporters shall have the option to apply for benefit either under the Target Plus Scheme or under the Vishesh Krishi Upaj Yojana, but not both in respect of the same exported product(s). Provided that in calculating the entitlement under Para 3.7.3 the total eligible exports shall be taken into account for computing the percentage incremental growth but the duty credit entitlement shall be arrived at on the eligible exports reduced by the amount on which the benefit is claimed under para 3.8.2.
- (4) All exports including exports under free shipping bill verified and authenticated by Customs and Gems & Jewellery shipping bills but excluding exports specified under para 3.7.5, shall be eligible for benefits under the Target Plus Scheme.

Applicant Companies 3.7.4

Companies which are Star Export Houses as well as part of a Group company shall have an option to either apply as an individual company or as a Group based on the growth in the Group's turnover as a whole. (For the purpose of this scheme the definition of Group Company' as given in Chapter 9 will be applicable. Furthermore, only such companies of the Group as are Star Export Houses will be considered).

If a Group company chooses to apply based on the export of one or more of its individual Star Export House companies, the entitlement would be calculated considering the export

performance of the applicant company during the previous licencing year and current year. It shall be necessary that the adjusted export performance of all the Star Export House companies of the Group during the current licencing year does not fall below the combined performance of all Star Export House companies of the Group in the previous licencing year.

In case the Group chooses to apply based on the overall growth in Group's turnover (i.e the turnover of all the Star Export House companies), any one of the Star Export House companies of the Group may file an application on behalf of all the Star Export House companies of the Group.

3.7.5 The following exports shall not be taken into account for calculation of export performance or for computation of entitlement under the scheme:

- (a) Export of imported goods covered under Para 2.35 of the Foreign Trade Policy or exports made through transshipment.
- (b) Export turnover of units operating under SEZ/EOU/EHTP/STPI/BTP Schemes or products manufactured by them and exported through DTA units
- (c) Deemed exports (even when payments are received in Free Foreign Exchange and payment is made from EEFC account).
- (d) Service exports.
- (e) Rough, uncut and semi polished diamonds and other precious stones.
- (f) Gold, silver, platinum and other precious metals in any form, including plain jewellery thereof. However exports of studded jewellery and any item as may be notified from time to time will be counted for the entitlement under the scheme.
- (g) Export performance made by one exporter on behalf of another exporter.

Imports allowed

3.7.6 The Duty Credit may be used for import of any inputs, capital goods including spares, office equipment, professional equipment and office furniture provided the same is freely importable under ITC (HS), for their own use or that of supporting manufacturers as declared in Appendix 17 D.

Agricultural products listed in Chapter 1 to 24 of ITC (HS) except as may be notified from time to time, shall not be permissible for imports under this scheme.

<i>Cenvat/Drawback</i>	3.7.7	Additional customs duty/excise duty paid in cash or through debit under Target Plus shall be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback as per rules framed by the Department of Revenue.
-------------------------------	-------	---

<i>Special Provision</i>	3.7.8	Government reserves the right in public interest, to specify from time to time the category of exports and export products, which shall not be eligible for calculation of incremental growth/entitlement.
---------------------------------	-------	--

Similarly, Government may from time to time also notify the list of goods, which shall not be allowed for import under the duty credit entitlement certificate issued under the scheme.

VISHESH KRISHI UPAJ YOJANA (SPECIAL AGRICULTURAL PRODUCE SCHEME)

<i>Objective</i>	3.8.1	The objective of the scheme is to promote export of fruits, vegetables, flowers, minor forest produce, and their value added products, by incentivising exporters of such products.
-------------------------	-------	---

<i>Entitlement</i>	3.8.2	Exporters of such products shall be entitled for duty credit scrip equivalent to 5% of the FOB value of exports for each licencing year commencing from 1st April, 2004. The scrip and the items imported against it would be freely transferable.
---------------------------	-------	--

<i>Imports allowed</i>	3.8.3	The Duty Credit may be used for import of inputs or goods including capital goods as may be specified, provided the same is freely importable under ITC(HS).
-------------------------------	-------	--

Imports from a port other than the port of export shall be allowed under TRA facility as per the terms and conditions of the notification issued by Department of Revenue.

<i>Cenvat/Drawback</i>	3.8.4	Additional customs duty/excise duty paid in cash or through debit under Vishesh Krishi Upaj Yojana shall be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback as per rules framed by the Department of Revenue.
-------------------------------	-------	--

<i>Special Provision</i>	3.8.5	Government reserves the right in public interest, to specify from time to time the export products which shall not be eligible for calculation of entitlement.
---------------------------------	-------	--

CHAPTER-4

DUTY EXEMPTION & REMISSION SCHEMES

Duty Exemption and Remission Schemes 4.1

Duty exemption schemes enable duty free import of inputs required for export production. An Advance Licence is issued as a duty exemption scheme. A Duty Remission Scheme enables post export replenishment/remission of duty on inputs used in the export product. Duty remission schemes consist of (a) DFRC (Duty Free Replenishment Certificate) and (b) DEPB (Duty Entitlement Passbook Scheme).

DFRC permits duty free replenishment of inputs used in the export product. DEPB allows drawback of import charges on inputs used in the export product.

Re-import of exported goods under Duty Exemption/Remission Scheme 4.1.1

Goods exported under Advance Licence/DFRC/DEPB may be re-imported in the same or substantially the same form subject to such conditions as may be specified by the Department of Revenue from time to time.

Value Addition 4.1.2

The value addition for the purposes of this chapter shall be:-

$$V.A = \frac{A - B}{B} \times 100, \text{ where}$$

V.A Value Addition

A FOB value of the export realised /FOR value of supply received.

B CIF value of the imported inputs covered by the licence, plus any other imported materials used on which the benefit of duty drawback is being claimed.

ADVANCE LICENCE***Advance Licence*** 4.1.3

An Advance Licence is issued to allow duty free import of inputs, which are physically incorporated in the export product (making normal allowance for wastage). In addition, fuel, oil, energy, catalysts etc. which are consumed in the course of their use to obtain the export product, may also be allowed under the scheme.

Duty free import of mandatory spares upto 10% of the CIF value of the licence which are required to be exported/supplied with the resultant product may also be allowed under Advance Licence.

Advance Licences are issued on the basis of the inputs and export items given under SION. However, they can also be issued on the basis of Adhoc norms or self declared norms as per para 4.7 of Handbook.

Duty free import of mandatory spares upto 10% of the CIF value of the licence which are required to be exported/supplied with the resultant product may also be allowed under Advance Licence.

Advance Licence can be issued for:-

- a) Physical exports:- Advance Licence may be issued for physical exports including exports to SEZ to a manufacturer exporter or merchant exporter tied to supporting manufacturer(s) for import of inputs required for the export product.
- b) Intermediate supplies:- Advance Licence may be issued for intermediate supply to a manufacturer-exporter for the import of inputs required in the manufacture of goods to be supplied to the ultimate exporter/deemed exporter holding another Advance Licence
- c) Deemed exports:- Advance Licence can be issued for deemed export to the main contractor for import of inputs required in the manufacture of goods to be supplied to the categories mentioned in paragraph 8.2 (b), (c), (d), (e), (f), (g), (i) and (j) of the Policy.

In addition, in respect of supply of goods to specified projects mentioned in paragraph 8.2 (d), (e), (f), (g) and (j) of the Policy, an Advance Licence for deemed export can also be availed by the sub-contractor of the main contractor to such project provided the name of the sub contractor(s) appears in the main contract.

Such licence for deemed export can also be issued for supplies made to United Nations Organisations or under the Aid Programme of the United Nations or other multilateral agencies and paid for in free foreign exchange.

- 4.1.4 Advance Licence is issued for duty free import of inputs, as defined in paragraph 4.1.1 subject to actual user condition. Such licences (other than Advance Licence for deemed exports) are exempted from payment of basic customs duty, additional customs duty, education cess, anti dumping duty and safeguard duty, if any.

Advance Licence for deemed export shall be exempted from

basic customs duty, additional customs duty and education cess only. However in case of supplies to EOU/EHTP/STP/BTP under such licences, anti-dumping duty and safeguard duty shall also be exempted.

4.1.5 Advance Licence and/or materials imported there under shall not be transferable even after completion of export obligation.

4.1.6 Advance Licences (including Advance Licence for deemed exports and intermediate supply) shall be issued with a positive value addition.

However, for exports for which payments are not received in freely convertible currency, the same shall be subject to value addition as specified in Appendix-32 of Handbook (Vol.1).

4.1.7 Advance Licence shall be issued in accordance with the Policy and procedure in force on the date of issue of licence and shall be subject to the fulfilment of a time bound export obligation as may be specified.

4.1.8 The facility of Advance Licence shall also be available where some or all of the inputs are supplied free of cost to the exporter.

In such cases, for calculation of value addition, the notional value of free of cost inputs along with value of other duty-free inputs shall be taken into consideration. However, if all the inputs are supplied free of cost, it shall be covered under paragraph 4.2.7 of the Policy.

Export Obligation

4.1.9 The period for fulfilment of the export obligation under Advance Licence shall be as prescribed in the Handbook (Vol.1). Supplies to SEZ would also be counted for fulfillment of export obligation under the Advance Licence for physical exports.

Advance Licence for Annual Requirement

4.1.10 Advance Licence can also be issued on the basis of annual requirement for physical exports, intermediate supplies or deemed exports.

One to Five Star Export House shall be entitled for the Advance Licence for annual requirement.

However, if the status holders are holding the certificate as merchant exporter, they are also entitled to the Advance Licence for Annual Requirement provided they agree to the endorsement of the name(s) of the supporting manufacturer(s) on the relevant licence.

The entitlement under this scheme shall be upto 200% of the FOB/FOR value of export in the preceding licensing year. Such licence shall have positive value addition.

Advance Release Orders

4.1.11 An Advance Licence holder, holder of advance licence for annual requirement and holder of DFRC intending to source the inputs from indigenous sources/State Trading Enterprises/EOU/SEZ/EHTP/STP/BTP units in lieu of direct import has the option to source them against Advance Release Orders denominated in foreign exchange/Indian rupees.

The transferee of a DFRC shall also be eligible for ARO facility. However, supplies may be obtained against the licence from EOU/EHTP/BTP/STP/SEZ units, without conversion into ARO.

Back-to-Back Inland Letter of Credit

4.1.12 An Advance Licence holder, holder of advance licence for annual requirement and holder of DFRC may, instead of applying for an Advance Release Order, avail of the facility of Back-to-Back Inland Letter of Credit in accordance with the procedure specified in Handbook (Vol. 1).

Prohibited Items

4.1.13 Prohibited items of imports mentioned in ITC(HS) shall not be imported under the licence issued under the scheme.

Admissibility of Drawback

4.1.14 In the case of an Advance Licence, the drawback shall be available in respect of any of the duty paid materials, whether imported or indigenous, used in the goods exported, as per the drawback rate fixed by Ministry of Finance (Directorate of Drawback). The Drawback shall however be restricted to the duty paid materials as mentioned in the licence.

DUTY FREE REPLENISHMENT CERTIFICATE

Duty Free Replenishment Certificate (DFRC)

4.2 DFRC is issued to a merchant-exporter or manufacturer-exporter for the import of inputs used in the manufacture of goods without payment of basic customs duty.

However, such inputs shall be subject to the payment of additional customs duty equal to the excise duty at the time of import.

4.2.1 DFRC shall be issued on minimum value addition of 25% except for items in gems and jewellery sector for which value addition as given in paragraph 4.56.1 of the Handbook (Vol. 1) shall be applicable.

4.2.2 DFRC may be issued in respect of exports for which payments

are received in non-convertible currency. Such exports shall, however, be subject to value addition and conditions as specified in Appendix-32 of Handbook (Vol.1).

DFRC may also be issued for supplies effected under paragraph 8.2 of the Policy.

- 4.2.3 DFRC shall be issued only in respect of products covered under the Standard Input Output Norms as notified by DGFT.

However, in respect of Standard Input Output Norms which are subject to “actual user” condition or where the export proceeds have not been realised or for import of fuel under the general norms, DFRC shall be issued with actual user condition for these inputs.

However, for fuel which is canalized, the import entitlement may be transferred to any canalizing agency.

In cases where Standard Input Output Norms allow import of Acetic Anhydride, Ephedrine and Pseudo Ephedrine, DFRC shall be issued provided these items are specifically deleted from the list of import items.

DFRC will not be issued against SION which prescribe a prior import condition for inputs.

- 4.2.4 DFRC shall be issued for import of inputs as per SION as indicated in the shipping bills. The validity of such licences shall be 24 months. DFRC and or the material(s) imported against it shall be freely transferable. However, DFRC with actual user condition or the material(s) imported against it shall not be transferable.

- 4.2.5 The export products, which are eligible for modified VAT, shall be eligible for CENVAT credit/service tax credit.

However, non excisable, non dutiable or non CENVAT products, shall be eligible for drawback at the time of exports in lieu of additional customs duty to be paid at the time of imports under the scheme.

- 4.2.6 The exporter shall be entitled for drawback benefits in respect of any of the duty paid materials, whether imported or indigenous, used in the export product as per the drawback rate fixed by Directorate of Drawback (Ministry of Finance).

The drawback shall however be restricted to the duty paid materials not covered under SION.

<i>Jobbing, repairing etc. for re-export</i>	4.2.7	Import of goods, including those mentioned as restricted in ITC(HS) but excluding prohibited items, supplied free of cost, may be permitted for the purpose of jobbing without a licence/certificate/permission as per the terms of notification issued by Department of Revenue from time to time.
--	-------	---

Similarly, import of goods for carrying out repairs, re-conditioning, re-engineering, testing etc. shall be allowed as per the terms and conditions of the Customs notification even though the goods may be restricted for imports under the Exim Policy/ITC(HS) Classification of Imports and Exports Book.

DUTY ENTITLEMENT PASSBOOK SCHEME

<i>Duty Entitlement Passbook Scheme (DEPB)</i>	4.3	The objective of DEPB is to neutralise the incidence of Customs duty on the import content of the export product. The neutralisation shall be provided by way of grant of duty credit against the export product.
--	-----	---

The DEPB scheme will continue to be operative until it is replaced by a new scheme which will be drawn up in consultation with exporters.

4.3.1	Under the DEPB, an exporter may apply for credit, as a specified percentage of FOB value of exports, made in freely convertible currency.
-------	---

The credit shall be available against such export products and at such rates as may be specified by the Director General of Foreign Trade by way of public notice issued in this behalf, for import of capital goods, raw materials, intermediates, components, parts, packaging material etc.

4.3.2	The holder of DEPB shall have the option to pay additional customs duty, if any, in cash as well.
-------	---

<i>Validity</i>	4.3.3	The DEPB shall be valid for a period of 24 months from the date of issue.
-----------------	-------	---

<i>Transferability</i>	4.3.4	The DEPB and/or the items imported against it are freely transferable. The transfer of DEPB shall however be for import at the port specified in the DEPB, which shall be the port from where exports have been made.
------------------------	-------	---

Imports from a port other than the port of export shall be allowed under TRA facility as per the terms and conditions of the notification issued by Department of Revenue.

Applicability of Drawback

- 4.3.5 Normally, the exports made under the DEPB Scheme shall not be entitled for drawback. However, the additional customs duty/excise duty paid in cash or through debit under DEPB shall be adjusted as CENVAT Credit or Duty Drawback as per rules framed by the Department of Revenue.

GEMS AND JEWELLERY***Scheme for Gems and Jewellery***

- 4.4 Exporters of gems and jewellery are eligible to import their inputs by obtaining Replenishment (REP) Licences from the licensing authorities in accordance with the procedure specified in this behalf.

Replenishment Licence

- 4.4.1 The exporters of gems and jewellery products listed in Appendix-26 of the Handbook (Vol.1) shall be eligible for grant of Replenishment Licences at the rate and for the items mentioned in the said Appendix to import and replenish their inputs.

Replenishment licence may also be issued for import of consumables as per the details given in paragraph 4.80 of Handbook (Vol. 1).

Export of Cut & Polished Diamonds for Certification/Grading

- 4.4.2 Gems and Jewellery exporters with a track record of at least three years and having an annual average turnover of Rs.5 crores and above during the preceding three licensing years or the authorized offices /agencies in India of Gemological Institute of America (GIA), The Robert Mouawad Campus, International Gemological Institute (IGI) and European Gemological Laboratory (EGL) in USA, Hoge Road Voor Diamond, Antwerp, (HRD), World Diamond Centre of Diamonds High Council, Antwerp, Belgium, Central Gem Laboratory, Miyagi Building, 5-15-14 Ueno Taito-Ku, Tokyo, Japan may be permitted to export cut & polished diamonds each weighing 0.25 of a carat and above to the said laboratories/agencies, for the purpose of certification/grading reports by them with a condition that the same should be re-imported with the certificate/grading reports issued by them without any import duty at the time of re-import.

- 4.4.2.1 At the time of export of cut and polished diamonds for certification/grading, exporter should give an undertaking to the customs that the cut and polished diamonds will be re-imported within three months of exports for certification/grading.

The export invoice should clearly indicate the estimated value, height, circumference, weight of each diamond to be exported

		for certification/grading so that at the time of their import, the above specification could be compared with the original ones to establish their identity. Subsequently these cut and polished diamonds would be exported as per the provisions of the Policy.
<i>Schemes for Gold/Silver/Platinum Jewellery</i>	4.4.3	Exporters of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof may import their essential inputs such as gold, silver, platinum, mountings, findings, rough gems, precious and semi-precious stones, synthetic stones and unprocessed pearls etc. in accordance with the procedure specified in this behalf.
<i>Nominated Agencies</i>	4.4.4	Exporters (excepting EOU/SEZ) availing the schemes of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof may obtain gold/silver/platinum from the nominated agencies. The nominated agencies are MMTC Ltd, Handicraft and Handloom Export Corporation (HHEC), State Trading Corporation (STC), the Project and Equipment Corporation of India Ltd (PEC), and any agency or Five Star Export House authorised by Reserve Bank of India (RBI). A bank authorised by RBI is allowed export of gold scrap for refining and import in the form of standard gold bars. The detailed procedure for the import of gold will be notified by RBI separately.
<i>Items of Export</i>	4.4.5	The following items, if exported, would be eligible for the facilities under these schemes: (a) Gold jewellery, including partly processed jewellery and any articles including medallions and coins (excluding the coins of the nature of legal tender), whether plain or studded, containing gold of 8 carats and above; (b) Silver jewellery including partly processed jewellery, silverware, silver strips and any articles including medallions and coins (excluding the coins of the nature of legal tender and any engineering goods) containing more than 50% silver by weight; (c) Platinum jewellery including partly processed jewellery and any articles including medallions and coins (excluding the coins of the nature of legal tender and any engineering goods) containing more than 50% platinum by weight.
<i>Value Addition</i>	4.4.6	The value addition will be as given as per paragraph 4.56.1 of Handbook (Vol. 1).
<i>Wastage Norms</i>	4.4.7	Under the schemes for gold/silver/platinum jewellery, the wastage or manufacturing loss shall be admissible as per paragraph 4.56 of the Handbook (Vol. 1).

***Export against
Supply by
Foreign Buyer***

4.4.8

Where export orders are placed on the nominated agencies/status holder/exporters of three years standing having an annual average turnover of Rs. Five Crore during the preceding three licensing years, the foreign buyer may supply to the nominated agencies/status holder/exporter, in advance and free of charge, gold/silver/platinum, alloys, findings and mountings of gold/silver/platinum for manufacture and export.

The exports may be made by the nominated agencies directly or through their associates or by the status holder/exporter as the case may be. The import and export of findings shall be on net to net basis. The foreign buyer may also supply to the nominated agencies/status holder/exporter in advance and free of charge plain, semi finished gold/silver/platinum jewellery including findings/mountings/components for repairs/re-make and export subject to minimum value addition of 10%. However, if the so imported semi finished gold/silver/platinum jewellery is exported as studded jewellery, value addition of 15% shall be achieved. In such cases of export, wastage of 2% may be permitted.

The procedures in this regard shall be as prescribed in the Handbook (Vol. 1)

***Export Promotion
Tours/Export of
Branded Jewellery***

4.4.9

The nominated agencies and their associates, with the approval of Department of Commerce, and others, with the approval of Gem & Jewellery Export Promotion Council (GJEPC), may export gold/silver/platinum jewellery and articles thereof for holding/participating in exhibitions abroad.

Personal carriage of gold/silver/platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles and export of branded jewellery is also permitted. These exports shall be subject to the conditions as given in the Handbook (Vol.1).

***Export Against
Supply by
Nominated
Agencies***

4.4.10

The exporter may obtain the gold/silver/platinum as an input for export products from nominated agencies in advance or as replenishment after exports in accordance with the procedure specified in this behalf.

***Export Against
Advance Licence***

4.4.11

An Advance Licence may be granted for the duty free import of:

- (a) Gold of fineness not less than 0.995 and mountings, sockets, frames and findings of 8 carats and above;
- (b) Silver of fineness not less than 0.995 and mountings, sockets, frames and findings containing more than 50% silver by weight;

- (c) Platinum of fineness not less than 0.900, mountings, sockets, frames and findings containing more than 50% platinum by weight.

- 4.4.12 Such licences shall carry an export obligation which will be required to be fulfilled in accordance with the procedure specified in this behalf.

The Advance Licence holder may obtain gold/silver/platinum from the nominated agencies in lieu of direct import in accordance with the procedure specified in this behalf.

***Gem Replenishment
Licence***

- 4.4.13 Gem Replenishment (Gem & Jewellery REP) Licence may be issued under the schemes for export of gold/silver/platinum jewellery and articles thereof as given in paragraph 4.4.8, 4.4.9, 4.4.10 and 4.4.11 of the Policy. In the case of plain gold/silver/platinum jewellery and articles, the value of such licences shall be determined with reference to the realisation in excess of the prescribed minimum value addition.

In the case of studded gold/silver/platinum jewellery and articles thereof, the value of Gem Replenishment Licence shall be determined by taking into account the value of studdings used in items exported, after accounting for the value addition on gold/silver/platinum including admissible wastage. Such Gem REP licences shall be freely transferable.

***Gem REP Rate
and Item***

- 4.4.14 The scale of replenishment and the item of import will be as prescribed in Appendix 26A of Handbook (Vol. 1).

***Personal Carriage
of Export/Import
Parcels***

- 4.4.15 Personal carriage of gems and jewellery export parcels by foreign bound passengers and personal carriage of gems & jewellery import parcels by an Indian importer/foreign national may be permitted as per the conditions given in Handbook (Vol. 1).

***Diamond Imprest
Licence***

- 4.4.16 Diamond Imprest Licence for import of cut & polished diamonds including semi processed diamonds, half cut diamonds, broken in any form, for mixing with cut & polished diamonds or for export as it is, may be issued for export of cut & polished diamonds.

Such licences shall carry an export obligation, which has to be discharged in accordance with the procedure specified in this behalf.

Eligibility

- 4.4.16.1 An exporter of cut & polished diamonds who is status holder may be issued a licence for import of cut & polished diamonds

upto 5% of the export performance of the preceding year of cut & polished diamonds.

Export Obligation

4.4.16.2 The export obligation against each consignment shall be fulfilled within a period of five months from the date of clearance of such consignment through Customs. However, at no point of time, the importer shall be required to maintain records of individual import consignments nor will they be required to co-relate export consignments with the corresponding import consignments towards fulfilment of export obligation.

Private/Public Bonded Warehouse

4.4.17 Private/Public Bonded Warehouses may be set up in SEZ/DTA for import and re-export of cut & Polished diamonds, cut & polished coloured gemstones, uncut & unset precious & semi-precious stones. Import & re-export of cut & polished diamonds & cut & polished coloured gemstones will be subject to achievement of minimum value addition of 5%.

Diamond & Jewellery Dollar Accounts

4.4.18 Firms and companies dealing in the purchase/sale of rough or cut and polished diamonds/precious metal jewellery plain, minakari and/or studded with/without diamond and/or other stones with a track record of at least 3 years in import or export of diamonds/coloured gemstones/diamond and coloured gemstones studded jewellery/plain gold jewellery and having an average annual turnover of Rs. 5 crore or above during preceding three licensing years may also carry out their business through designated Diamond Dollar Accounts.

The Diamond Dollar Account Scheme shall operate under the current licensing scheme of this chapter. This scheme shall be optional and those importers/exporters who wish to continue to use Rupee Accounts shall be allowed to do so under the existing policies.

Dollars in such accounts available from bank finance and/or export proceeds shall be used only for

- (i) Import/purchase of rough diamonds from overseas/local sources,
- (ii) Purchase of cut and polished diamonds, coloured gemstones and plain gold jewellery from local sources,
- (iii) Import/purchase of gold from overseas/nominated agencies and repayment of dollar loans from the bank; and

- (iv) Transfer to the Rupee Account of the exporter. Details of this Diamond Dollar Accounts Scheme (DDAS) are given in the Handbook (Vol. 1). The procedure outlined in the Handbook (Vol. 1) shall also apply to diamond studded jewellery.

A non DDA holder is also permitted to supply cut and polished diamonds to DDA holder, receive payment in dollars and convert same into rupees within the period of 7 days and cut and polished diamonds and coloured gemstones so supplied by non-DDA holder will also be counted towards the discharge of his export obligation and/or entitled him to replenishment licence as the case may be.

CHAPTER-5**EXPORT PROMOTION CAPITAL GOODS SCHEME*****EPCG Scheme*****5.1**

The scheme allows import of capital goods for pre production, production and post production (including CKD/SKD thereof as well as computer software systems) at 5% Customs duty subject to an export obligation equivalent to 8 times of duty saved on capital goods imported under EPCG scheme to be fulfilled over a period of 8 years reckoned from the date of issuance of licence. Capital goods would be allowed at 0% duty for exports of agricultural products and their value added variants.

However, in respect of EPCG licences with a duty saved of Rs. 100 crore or more, the same export obligation shall be required to be fulfilled over a period of 12 years.

In case CVD is paid in cash on imports under EPCG, the incidence of CVD would not be taken for computation of net duty saved provided the same is not CENVATED.

The capital goods shall include spares (including refurbished/reconditioned spares), tools, jigs, fixtures, dies and moulds. EPCG licence may also be issued for import of components of such capital goods required for assembly or manufacture of capital goods by the licence holder.

Second hand capital goods without any restriction on age may also be imported under the EPCG scheme.

Spares (including refurbished/reconditioned spares), tools, refractories, catalyst and consumable for the existing and new plant and machinery may also be imported under the EPCG scheme.

However, import of motor cars, sports utility vehicles/all purpose vehicles shall be allowed only to hotels, travel agents, tour operators or tour transport operators whose total foreign exchange earning in current and preceding three licencing years is Rs. 1.5 crores. However, the parts of motor cars, sports utility vehicles/all purpose vehicles such as chassis etc cannot be imported under the EPCG Scheme.

5.1A

Spares (including refurbished/reconditioned spares), tools, spare refractories, catalyst & consumable for the existing plant and machinery may also be imported under the EPCG Scheme subject to an export obligation equivalent to 8 times of duty

		saved to be fulfilled over a period of 8 years reckoned from the date of issuance of licence.
<i>EPCG for Projects</i>	5.1B	<p>An EPCG licence can also be issued for import of capital goods for supply to projects notified by the Central Board of Excise and Customs under S.No 441 of Customs Exemption Notification No 21/2002 dated 01.03.2002 wherein the basic customs duty on imports is 10% with a CVD of 16%.</p> <p>The export obligation for such EPCG licences would be eight times the duty saved. The duty saved would be the difference between the effective duty under the aforesaid Customs Notification and the concessional duty under the EPCG Scheme.</p>
<i>Eligibility</i>	5.2	The scheme covers manufacturer exporters with or without supporting manufacturer(s)/vendor(s), merchant exporters tied to supporting manufacturer(s) and service providers.
<i>Conditions for import of Capital Goods</i>	5.3	Import of capital goods shall be subject to Actual User condition till the export obligation is completed.
<i>Export obligation</i>	5.4	<p>The following conditions shall apply to the fulfillment of the export obligation:-</p> <p>(i) The export obligation shall be fulfilled by the export of goods capable of being manufactured or produced by the use of the capital goods imported under the scheme.</p> <p>The export obligation may also be fulfilled by the export of same goods, for which EPCG licence has been obtained, manufactured or produced in different manufacturing units of the licence holder/specified supporting manufacturer (s).</p> <p>When Capital Goods are imported for pre/post- production or license is taken for import of spares, the license holder shall fulfill the export obligation by export of products manufactured from the plant /project to which the pre/ post- production capital goods/spares are related.</p> <p>The import of capital goods for creating storage and distribution facilities for products manufactured or services rendered by the EPCG licence holder would be permitted under the EPCG Scheme.</p> <p>The export obligation under the scheme shall be, over and above, the average level of exports achieved by him</p>

in the preceding three licensing years for same and similar products except for categories mentioned in Handbook (Vol. 1).

Alternatively, export obligation may also be fulfilled by exports of other good(s) manufactured or service(s) provided by the same firm/company or group company/managed hotel which has the EPCG licence.

However, in such cases, the additional export obligation imposed under EPCG scheme shall be over and above the average exports achieved by the unit/company/group company/managed hotel in preceding three licensing years for both the original and the substitute product(s) /service(s) even in cases where the average is exempt for the substitute product(s)/service(s) as given in para 5.7.6 of the Handbook (Vol 1).

The incremental exports to be fulfilled by the licence holder for fulfilling the remaining export obligation can include any combination of exports of the original product/service and the substitute product(s)/service(s). The exporter of goods can opt to get the export obligation refixed for the export of services and vice versa.

The licensee can also opt for the re-fixation of the balance export obligation based on 8 times of the duty saved amount for the CIF value in proportion to the balance Export obligation under the scheme. The guidelines for the re-fixation of export obligation is given in para 5.19 of the Handbook (Vol . 1).

The aforesaid facilities shall only be available to manufacturer exporters/service provider on all the licences where export obligation period including extended export obligation period valid on the date of application. In this regard, exports made only on or after submission of application for alternate item and/or re-fixation of the export obligation based on duty saved amount will be taken into account for fulfillment of export obligation.

- (ii) The export obligation under the scheme shall be, in addition to any other export obligation undertaken by the importer, except the export obligation for the same product under Advance Licence, DFRC, DEPB or Drawback scheme.

(iii) The export obligation can also be fulfilled by the supply of ITA-1 items to the DTA provided the realization is in free foreign exchange.

(iv) Exports shall be physical exports. However, deemed exports as specified in paragraph 8.2 (a), (b), (d), (f), (g) & (j) of Policy shall also be counted towards fulfilment of export obligation alongwith the usual benefits available under paragraph 8.3 of the Policy.

Royalty payments received in freely convertible currency and foreign exchange received for R& D services shall also be counted for discharge under the EPCG scheme. Payment received in rupee terms for the port handling services, in terms of Chapter 9 of the Foreign Trade Policy shall also be counted for export obligation discharge under the Scheme.

***Provision for
BIFR units***

5.5.1 Any firm/company registered with BIFR or any firm/company acquiring a unit, which is under BIFR shall be allowed EO extension as per the rehabilitation package prepared by the operating agency subject to subsequent approval of BIFR.

However, in cases where the rehabilitation package does not specify the EO extension period, a time period upto 12 years reckoned from the date of issue of licence would be permitted on merits of the case for fulfillment of export obligation.

Similarly, SSI units shall also be entitled for similar facility as per the rehabilitation scheme of the concerned State government. However, in cases where the State rehabilitation scheme does not specify the export obligation extension period, a time period upto 12 years reckoned from the date of issue of licence would be permitted on merits of the case for fulfillment of export obligation

EPCG for agro units 5.5.2

In the case of EPCG licences issued to agro units in the agri export zones, a period of 12 years reckoned from the date of issue of the licence would be permitted for the fulfillment of export obligation.

The agro units in the agri export zones would also have the facility of moving the capital good (s) imported under the EPCG within the agri export zone.

An LUT/Bond in lieu of BG may be given for EPCG licence granted to units in the Agri Export Zones provided the EPCG

licence is taken for export of the primary agricultural product (s) notified in Appendix 15 or their value added variants.

Indigenous Sourcing of Capital Goods and benefits to Domestic Supplier 5.6

A person holding an EPCG licence may source the capital goods from a domestic manufacturer instead of importing them. The domestic manufacturer supplying capital goods to EPCG licence holders shall be eligible for deemed export benefit under paragraph 8.3 of the Policy.

Benefits to Domestic Supplier 5.7

In the event of a firm contract between the EPCG licence holder and domestic manufacturer for such sourcing, the domestic manufacturer may apply for the issuance of Advance Licence for deemed exports for the import of inputs including components required for the manufacturer of said capital goods. The domestic manufacturer may also replenish the inputs including components after supply of capital goods to the EPCG licence holders.

Fixation of Export Obligation 5.7A

In case of direct imports, the export obligation relating to the EPCG licence shall be reckoned with reference to the duty saved value on the CIF value of capital goods (including spares, jigs, fixtures, dies and moulds) actually imported. In case of domestic sourcing, the export obligation relating to EPCG shall be reckoned with reference to the notional Customs duties saved on the FOR of capital goods (including spares, jigs, fixtures, dies and moulds).

5.8 Service provider in Agri export zone shall have the facility to move or shift the capital goods within the zone provided he maintains accurate record of such movements. However, such equipments shall not be sold or leased by the licence holder.

Maintenance of Average exports under EPCG 5.9

As per the provisions of para 5.4(i), the EPCG licence holder would have to maintain the average level of exports equivalent to the average of the exports in the preceding three licencing years for the same and similar products except for exempted categories given in Handbook (Vol. 1) during the entire period of export obligation.

Notwithstanding the above, the licence holder shall maintain atleast 75% of the average exports in any particular year(s) provided the same is offset by excess exports to fulfil the average in other year(s).

Technological Upgradation of existing EPCG machinery 5.10

EPCG licence holders can opt for Technological Upgradation of the existing capital good imported under the EPCG licence.

The conditions governing the Technological Upgradation of the existing capital good are as under:

- (i) The minimum time period for applying for Technological Upgradation of the existing capital good imported under EPCG is 5 years from the date of issuance of the licence.
- (ii) The minimum exports made under the old capital good must be 40% of the total export obligation imposed on the first EPCG licence.
- (iii) The export obligation would be refixed such that the total export obligation mandated for both the capital goods would be the sum total of 6 times the duty saved on both the capital goods.
- (iv) The procedure governing the replacement of capital good is given in para 5.20 of the Handbook (Vol. 1).

CHAPTER-6

**EXPORT ORIENTED UNITS (EOUs), ELECTRONICS HARDWARE
TECHNOLOGY PARKS (EHTPs), SOFTWARE TECHNOLOGY
PARKS (STPs) AND BIO-TECHNOLOGY PARKS (BTPs)**

Eligibility

- 6.1 Units undertaking to export their entire production of goods and services (except permissible sales in the DTA), may be set up under the Export Oriented Unit (EOU) Scheme, Electronic Hardware Technology Park (EHTP) Scheme, Software Technology Park (STP) Scheme or Bio-Technology Park (BTP) scheme for manufacture of goods, including repair, re-making, reconditioning, re-engineering, and rendering of services. Trading units, however, are not covered under these schemes.

***Export and Import
of Goods***

- 6.2
- (a) An EOU/EHTP/STP/BTP unit may export all kinds of goods and services except items that are prohibited in the ITC (HS). Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) shall be subject to fulfillment of the conditions indicated in the ITC (HS).
 - (b) An EOU/EHTP/STP/BTP unit may import and/or procure from DTA or bonded warehouses in DTA/international exhibition held in India without payment of duty all types of goods, including capital goods, required for its activities, provided they are not prohibited items of import in the ITC (HS). Any permission required for import under any other law shall be applicable. The units shall also be permitted to import goods including capital goods required for the approved activity, free of cost or on loan/lease from clients. The import of capital goods will be on a self certification basis.
 - (c) State Trading regime shall not apply to EOU manufacturing units.
 - (d) EOU/EHTP/STP/BTP units may import/procure from DTA without payment of duty certain specified goods for creating a central facility which will be used by software units. These software units can be EOU/DTA units who will use the facility for export of software.
 - (e) An EOU engaged in agriculture, animal husbandry, aquaculture, floriculture, horticulture, pisciculture, viticulture, poultry or sericulture may be permitted to remove specified goods in connection with its activities for use outside the bonded area.

- (f) Gems and jewellery EOUs may source gold/silver/platinum through the nominated agencies also. Units obtaining gold/silver/platinum from the nominated agencies shall export gold/silver/platinum jewellery within 60 days from the date of release. This shall not, however, apply to outright purchase of precious metal from the nominated agencies.
- (g) EOU/EHTP/STP/BTP units, other than service units, may export to Russian Federation in Indian Rupees against repayment of State Credit/Escrow Rupee Account of the buyer subject to RBI clearance, if any.
- (h) Procurement and supply of spares and consumables required for the goods manufactured by the units may be allowed to be exported along with goods upto 1.5% of FOB value of exports. This shall, however, not count towards NFE calculation, for concessional rate DTA sales or for Income Tax exemption.

***Second Hand
Capital Goods***

6.3

Second hand capital goods without any age limit, may also be imported duty free.

***Leasing of
Capital Goods***

6.4

An EOU/EHTP/STP/BTP unit may, on the basis of a firm contract between the parties, source the capital goods from a domestic/foreign leasing company without payment of customs/excise duty. In such a case, the EOU/EHTP/STP/BTP unit and the domestic/foreign leasing company shall jointly file the documents to enable import/procurement of the capital goods without payment of duty.

***Net Foreign Exchange
Earnings (NFE)***

6.5

EOU/EHTP/STP/BTP unit shall be a positive net foreign exchange earner. Net Foreign Exchange Earnings (NFE) shall be calculated cumulatively in blocks of five years, starting from the commencement of production.

***Letter of Permission/
Letter of Intent and
Legal Undertaking***

6.6

- (a) On approval, a Letter of Permission (LOP)/Letter of Intent (LOI) shall be issued by the Development Commissioner/ Designated officer to EOU/EHTP/STP/BTP unit. The LOP/LOI shall have an initial validity of 3 years by which time the unit should have commenced production. Its validity may be extended further up to 3 years by the competent authority. However, proposals for extension beyond six years shall be considered in exceptional circumstances, on a case-to-case basis by the BOA. Once the unit commences production, LOP/LOI issued shall be valid for a period of 5 years for its activities. This period may be extended further by the Development Commissioner for a period of 5 years at a time.

- (b) LOP/LOI issued to EOU/EHTP/STP/BTP units by the concerned authority would be construed as a licence for all purposes.
- (c) The unit shall execute a legal undertaking with the Development Commissioner concerned. Failure to ensure positive NFE or to abide by any of the terms and conditions of the LOP/LOI/IL/LUT shall render the unit liable to penal action under the provisions of the Foreign Trade (Development & Regulation) Act, 1992 and the Rules and Orders made there under without prejudice to action under any other law/rules and cancellation or revocation of LOP/LOI/IL.

Investment Criteria

- (d) Only projects having a minimum investment of Rs. 1 crore in plant and machinery shall be considered for establishment as EOUs under the scheme. This shall, however, not apply to existing units and units in EHTP / STP/BTP, Handicrafts/Agriculture/Floriculture/Aquaculture/Animal Husbandry/Information Technology, Services, Brass hardware, handmade Jewellery and such other sectors as may be decided by the BOA. Sector-wise investment criteria shall be fixed by BOA.

Application & Approvals

6.7

- (a) Applications for setting up of units under EOU scheme other than proposals for setting up of unit in the services sector (except R&D, software and IT enabled services, or any other service activity as may be delegated by the BOA), shall be approved or rejected by the Units Approval Committee within 15 days as per the criteria indicated in Handbook (Vol-I).
- (b) In other cases, approval may be granted by the Board of Approval (BOA) set up for this purpose as indicated in the Handbook (Vol-I).
- (c) Proposals for setting up EOU requiring industrial licence may be granted approval by the Development Commissioner after clearance of the proposal by the Board of Approval and Department of Industrial Policy and Promotion within 45 days.

DTA Sale of Finished Products/Rejects/Waste/Scrap/Remnants and By-products

6.8

The entire production of EOU/EHTP/STP/BTP units shall be exported subject to the following:

- (a) Units, other than gems and jewellery units, may sell goods upto 50% of FOB value of exports subject to fulfillment of positive NFE on payment of concessional duties. Within the entitlement of DTA sale, the unit may sell in

DTA its products similar to the goods which are exported or expected to be exported from the units. No DTA sale at concessional duty shall be permissible in respect of motor cars, alcoholic liquors, books and tea (except instant tea) or by a packaging/labeling /segregation/refrigeration unit/compacting/micronisation/pulverization/granulation/conversion of mono-hydrate form of chemical to anhydrous form or vice-versa and such other items as may be notified from time to time.

Sales made to a unit in SEZ shall also be taken into account for the purpose of arriving at FOB value of export by EOU provided payment for such sales are made from EEFC Account. Sale to DTA would also be subject to mandatory requirement of registration of pharmaceutical products (including bulk drugs).

- (b) For services, including software units, sale in the DTA in any mode, including on line data communication shall also be permissible up to 50% of FOB value of exports and /or 50% of foreign exchange earned, where payment of such services is received in foreign exchange.
- (c) Gems and jewellery units may sell upto 10% of FOB value of exports of the preceding year in DTA subject to fulfillment of positive NFE. In respect of sale of plain jewellery, the recipient shall pay concessional rate of duty as applicable to sale from nominated agencies. In respect of studded jewellery, duty shall be payable as applicable.
- (d) Unless specifically prohibited in the LOP, rejects may be sold in the Domestic Tariff Area (DTA) on payment of duties as applicable to sale under paragraph 6.8(a) on prior intimation to the Customs authorities. Such sales shall be counted against DTA sale entitlement. Sale of rejects upto 5% of FOB value of exports shall not be subject to achievement of NFE.
- (e) Scrap/waste/remnants arising out of production process or in connection therewith may be sold in the DTA as per the Standard Input-Output norms notified under the Duty Exemption Scheme on payment of concessional duties as applicable within the overall ceiling of 50% of FOB value of exports. Such sales shall not, however, be subject to achievement of positive NFE. In respect of items not covered by the norms, the Development Commissioner may fix ad-hoc norms on the basis of data for a period of six months and within this period, he shall get the norms fixed by the BOA. Sale of waste/scrap/remnants by units not entitled to DTA sale or sales beyond the DTA sale entitlement, shall be on payment of full duties. The scrap/waste/remnants may also be exported.

- (f) There shall be no duties/taxes on scrap/waste/remnants in case the same are destroyed with the permission of Customs authorities.
- (g) By-products included in the LOP may also be sold in the DTA subject to achievement of positive NFE on payment of applicable duties within the overall entitlement of paragraph 6.8(a). Sale of by-products by units not entitled to DTA sales or beyond the entitlements of paragraph 6.8 (a) shall also be permissible on payment of full duties.
- (h) EOU/EHTP/STP/BTP units may sell finished products, which are freely importable under the Policy in the DTA under intimation to the Development Commissioner against payment of full duties provided they have achieved the positive NFE.
- (i) In the case of units manufacturing electronics hardware and software, the NFE and DTA sale entitlement shall be reckoned separately for hardware and software.
- (j) In case of DTA sale of goods manufactured by EOU/EHTP/STP/BTP, where basic duty and CVD is nil, such goods may be considered as non-excisable for the purpose of payment of duty.
- (k) In case of new EOUs, advance DTA sale will be allowed based on its estimated exports for the first year.

Other Supplies in DTA 6.9

Following supplies effected from EOU/EHTP/STP/BTP units to DTA will be counted for the purpose of fulfillment of positive NFE:

- (a) Supplies effected in DTA to holders of advance licence/ advance licence for annual requirement/DFRC under the duty exemption/remission scheme/EPCG scheme.
- (b) Supplies effected in DTA against payment from the Exchange Earners Foreign Currency (EEFC) Account of the buyer in the DTA or against foreign Exchange remittance received from overseas.
- (c) Supplies to other EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ units provided that such goods are permissible for procurement in terms of paragraph 6.2 of the Policy.
- (d) Supplies made to bonded warehouses set up under the policy and/or under section 65 of the customs act and Free Trade & Warehousing Zones, where payment is received in foreign exchange.
- (e) Supplies of goods and services to such organizations which are entitled for duty free import of such items in terms of general exemption notification issued by the Ministry of Finance.

- (f) Supply of services (by services units) relating to exports paid for in free foreign exchange or for such services rendered in Indian Rupees which are otherwise considered as having been paid for in free foreign exchange by RBI.
- (g) Supplies of Information Technology Agreement (ITA -1) items and notified zero duty telecom/electronic items.

Export through others 6.10

An EOU/EHTP/STP/BTP unit may export goods manufactured/software developed by it through another exporter or any other EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ unit subject to the conditions mentioned in para 6.19 of Handbook.

Entitlement for supplies from the DTA 6.11

- (a) Supplies from the DTA to EOU/EHTP/STP/BTP units will be regarded as “deemed exports” and the DTA supplier shall be eligible for the relevant entitlements under chapter 8 of the Policy besides discharge of export obligation, if any, on the supplier. Notwithstanding the above, EOU/EHTP/STP/BTP units shall, on production of a suitable disclaimer from the DTA supplier, be eligible for obtaining the entitlements specified in chapter 8 of the Policy. For the purpose of claiming deemed export duty drawback, they shall get Brand Rates fixed by the Development Commissioner wherever All Industry Rates of Drawback are not available.
- (b) Suppliers of precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from DTA to EOU shall be eligible for grant of Replenishment Licenses at the rates and for the items mentioned in the Handbook (Vol. 1).
- (c) In addition, the EOU/EHTP/STP/BTP units shall be entitled to the following:-
 - i. Reimbursement of Central Sales Tax on goods manufactured in India
 - ii. Exemption from payment of Central Excise Duty on goods procured from DTA on goods manufactured in India.
 - iii. Reimbursement of Central Excise Duty/additional excise duty paid on bulk tea procured from licenced auction centres.
 - iv. Reimbursement of Duty paid on fuels procured from domestic oil companies as per the rate of Drawback notified by the DGFT from time to time.
 - v. Exemption from payment of service tax.

Other Entitlements	6.12	<p>Other entitlements of EOU/EHTP/STP/BTP units are as under:</p> <ul style="list-style-type: none"> (a) Exemption from payment of Income Tax as per the provisions of Section 10A and 10B of Income Tax Act. (b) Exemption from industrial licensing for manufacture of items reserved for SSI sector. (c) An Offshore Banking Unit will extend credit on the same terms and condition as extended to units to SEZ. (d) Export proceeds will be realized within 12 Months. (e) Will be allowed to retain 100% of its export earning in the EEFC account. (f) The Units will not be required to furnish bank guarantee at the time of import or going for job work in DTA, where the unit has (i) a turnover of rupees 5 crores or above, (ii) the unit is in existence for at least three years and (iii) unit having an unblemished track record. (g) 100% FDI investment permitted through Automatic Route similar to SEZ units.
Inter Unit Transfer	6.13	<ul style="list-style-type: none"> (a) Transfer of manufactured goods from one EOU/EHTP/STP/BTP unit to another EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ unit will be allowed. (b) Capital goods may be transferred or given on loan to other EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ units with prior permission of the concerned Development Commissioner and prior intimation to Customs authorities. (c) Goods supplied by one unit of EOU/EHTP/STP/BTP to another unit shall be treated as imported goods for the second unit for the purpose of payment of duty, on DTA sale by the second unit.
Sub-Contracting	6.14	<ul style="list-style-type: none"> (a) (i) EOU/EHTP/STP/BTP units, including gem and jewellery units, may on the basis of annual permission from the Customs authorities, subcontract production processes to DTA through job work which may also involve change of form or nature of goods, through job work by units in the DTA. (ii) These units may also subcontract upto 50% of the overall production of the previous year in value terms for job work in DTA with the permission of the Customs Authorities. (b) (i) EOU may, on the basis of annual permission from the Customs authorities, undertake job work for export, on behalf of DTA exporter, provided that the

goods are exported directly from EOU and export document shall jointly be in the name of DTA/EOU. For such exports, the DTA units will be entitled for refund of duty paid on the inputs by way of All Industry Rates of drawback/Brand Rate of duty drawback.

- (ii) Duty free import of goods for execution of export order placed on EOU by Foreign Supplier on job work basis would be allowed subject to the condition that no DTA clearance shall be allowed.
- (iii) Subcontracting of both production and production processes may also be undertaken without any limit through other EOU/EHTP/STP/SEZ/BTP units on the basis of records maintained in the unit.
- (iv) Subcontracting of part of production process may also be permitted abroad with the approval of the Development Commissioner.
- (c) Scrap/waste/remnants generated through job work may either be cleared from the job worker's premises on payment of applicable duty on transaction value or destroyed in the presence of Customs/Excise authorities or returned to the unit. Destruction shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.
- (d) Sub-contracting/exchange by gems and jewellery EOUs through other EOUs or SEZ units or units in DTA shall be as per procedure indicated in Handbook (Vol-I).

Sale of Un-utilised Material

6.15

- (a) In case an EOU/EHTP/STP/BTP unit is unable to utilize the goods and services, imported or procured from DTA, it may be (i) transferred to another EOU/SEZ/EHTP/STP/BTP unit or (ii) disposed off in the DTA with the approval of the Customs authorities on payment of applicable duties and submission of import licence, if required, or (iii) exported. Such transfer from EOU/EHTP/STP/BTP unit to another such unit would be treated as import for the receiving unit.
- (b) Capital goods and spares that have become obsolete/surplus, may either be exported, transferred to another EOU/EHTP/STP/BTP/SEZ or disposed of in the DTA on payment of applicable duties. The benefit of depreciation, as applicable, will be available in case of disposal in DTA. No duty shall be payable in case capital goods, raw material, consumables, spares, goods manufactured, processed or packaged, and scrap/waste/remnants/rejects are destroyed within the Unit after intimation to the

Custom authorities or destroyed outside the Unit with the permission of Custom authorities. Destruction as stated above shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.

- (c) In the case of textile sector, disposal of leftover material/fabrics upto 2% of cif value or quantity of import whichever is lower, on payment of duty on transaction value may be allowed, subject to certification of central excise/custom officers that these are leftover items.
- (d) Disposal of used packing material will be allowed on payment of duty on transaction value.

***Reconditioning/
Repair and
Re-engineering***

6.16

EOU/EHTP/STP/BTP units may be set up with the approval of BOA to carry out reconditioning, repair, remaking, testing, calibration, quality improvement, up-gradation of technology and re-engineering activities for export in foreign currency. The provisions of paragraphs 6.8, 6.9, 6.10, 6.13, 6.14 of policy and para 6.29 of Handbook shall not, however, apply to such activities.

***Replacement/
Repair of
imported/Indigenous
Goods***

6.17

- (a) The general provisions of the Policy relating to export of replacement/repair of goods under para 2.37 of Policy would also apply equally to EOU/EHTP/STP/BTP units. Cases not covered by these provisions shall be considered on merits by the Development Commissioner.
- (b) The goods sold in the DTA and not accepted for any reasons may be brought back for repair/replacement, under intimation to the concerned jurisdictional Customs/Excise authorities.
- (c) Goods or parts thereof on being imported/indigenously procured and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged or become defective subsequently may be returned and replacement obtained or destroyed. In the event of replacement, the goods may be brought back from the foreign suppliers or their authorized agents in India or indigenous suppliers. However destruction shall not apply to precious and semi precious and precious metals.

Exit from EOU Scheme 6.18

- (a) With the approval of the Development Commissioner, EOU units may opt out of the scheme. Such exit from the scheme shall be subject to payment of Excise and customs duties and the industrial policy in force at the time of exit.
- (b) If the unit has not achieved the obligations under the scheme, it shall also be liable to penalty at the time of exit.

- (c) In the event of a gem and jewellery unit ceasing its operation, gold and other precious metals, alloys, gem and other materials available for manufacture of jewellery, shall be handed over to an agency nominated by the Ministry of Commerce and Industry (Department of Commerce) at the price to be determined by that agency.
- (d) An EOU/EHTP/STP/BTP unit may also be permitted by the Development Commissioner, to exit from the scheme on payment of duty on capital goods under the prevailing EPCG Scheme as a one time option. This will be subject to fulfillment of the eligibility criteria under that Scheme and standard conditions indicated in Handbook (Vol-I).
- (e) Units proposing to exit from EOU scheme should obtain permission for in principle approval and submit details of imports and exports made to the Central Excise/ Customs Authority. After such verification, the said authority will assess the duty payment and the unit will pay the duty so assessed and obtain 'no dues certificate' from the excise authority. During the period between such payment of customs duty and obtaining the final debonding letter, the unit will not be entitled to claim any exemption for procurement of capital goods or inputs. They can however, claim DEEC/DEPB/DFRC/Duty Drawback.
- (f) In cases where a unit is initially established as DTA unit with machine procured from abroad after payment of applicable import duty or from domestic market after payment of excise duty and the units are subsequently converted to EOU, in such cases removal of such capital goods to DTA after de-bonding would be without payment of duty. Similarly in cases where a DTA unit imported capital goods under the EPCG Scheme as a DTA units and after completely fulfilling the export obligation under the EPCG scheme gets converted into EOU, the unit would not be charged customs duty on CG at the time of removal of such capital goods in DTA.

Conversion

- 6.19
- (a) Existing DTA units, may also apply for conversion into an EOU/EHTP/STP/BTP unit, and Income Tax benefits under Section 10B will be available under the scheme for plant, machinery and equipment already installed.
 - (b) The existing EHTP/STP units may also apply for conversion/merger to EOU unit and vice-versa. In such cases the units will remain in bond and avail the exemptions in duties and taxes as applicable under the relevant scheme.

Monitoring of NFE	6.20	The performance of EOU units shall be monitored by the Units Approval Committee as per the guidelines given in Handbook (Vol-I).
Export through Exhibitions/Export Promotion Tours /Export through showrooms abroad/ Duty Free Shops	6.21	EOU/EHTP/STP/BTP are permitted to : (i) Export goods for holding/participating in exhibitions abroad with the permission of Development Commissioner (ii) Personal carriage of gold/silver/platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles. (iii) Export goods for display/sale in the permitted shops set up abroad. (iv) Display/sell in the permitted shops set up abroad or in the show rooms of their distributors/agents. (v) Set up show rooms/retail outlets at the International Airports.
Personal Carriage of Import /Export Parcels Including Through Foreign bound Passengers	6.22	Import/export through personal carriage of gem and jewellery items may be under-taken as per the procedure prescribed by Customs. The export proceeds shall, however, be realized through normal banking channel. Import/export through personal carriage for units, other than gem and jewellery units, shall be allowed provided the goods are not in commercial quantity.
Export /Import by Post /Courier	6.23	Goods including free samples, may be exported/imported by airfreight or through Foreign Post Office or through courier, subject to the procedure prescribed by Customs.
Administration of EOUs/Power of Development Commissioner	6.24	Details of administration of EOUs and Power of Development Commissioner are given in Handbook (Vol.1).
Revival of Sick units	6.25	Subject to a unit being declared sick by the appropriate authority, proposals for revival of the unit or its take over may be considered by the Board of Approval.
Approval for EHTP/ STP	6.26	In the case of units under EHTP/STP Schemes, necessary approval /permission under relevant paragraphs of this Chapter shall be granted by the officer designated by the Ministry of Communication and Information Technology, Department of Information Technology instead of the Development Commissioner and by the Inter-Ministerial Standing Committee (IMSC) instead of BOA.

Approval of BTP

6.27

Bio-technology Parks (BTP) would be notified by the DGFT on the recommendations of Department of Biotechnology. In the case of units in the BTP, necessary approval/permission under relevant provisions of this chapter will be granted by the designated officer of the Department of Biotechnology.

CHAPTER-7

SPECIAL ECONOMIC ZONES

Note:

Special Economic Zones (SEZ) are growth engines that can boost manufacturing, augment exports and generate employment. The private sector has been actively associated with the development of SEZs. The SEZs require special fiscal and regulatory regime in order to impart a hassle free operational regime encompassing the state of the art infrastructure and support services. The proposed legislation on SEZs to be enacted in the near future would cover the concepts of the developer and co-developer, incorporate the provision of virtual SEZs, have fiscal concessions under the Income Tax and Customs Act, provide for Offshore Banking Units (OBUs) etc. A brief on the facilities available under the SEZ scheme is given as under:

Eligibility

- 7.1
- (a) Special Economic Zone (SEZ) is a specifically delineated duty free enclave and shall be deemed to be foreign territory for the purposes of trade operations and duties and tariffs.
 - (b) Goods and services going into the SEZ area from DTA shall be treated as exports and goods coming from the SEZ area into DTA shall be treated as if these are being imported.
 - (c) SEZ units may be set up for manufacture of goods and rendering of services.

Export and Import of Goods

- 7.2
- (a) SEZ units may export goods and services including agro products, partly processed goods, sub-assemblies and components except prohibited items of exports in ITC (HS). The units may also export by-products, rejects, waste scrap arising out of the production process. Export of Special Chemicals, Organisms, Materials, Equipment and Technologies (SCOMET) shall be subject to fulfillment of the conditions indicated in the ITC (HS) Classification of Export and Import Items.

SEZ units, other than trading/service unit, may also export to Russian Federation in Indian Rupees against repayment of State Credit/Escrow Rupee Account of the buyer, subject to RBI clearance, if any.
 - (b) SEZ unit may import/procure from the DTA without payment of duty all types of goods and services, including capital goods, whether new or second hand, required by it for its activities or in connection therewith, provided they are not prohibited items of imports in the ITC(HS). However, any permission required for import under any other law shall be applicable. Goods shall include raw

material for making capital goods for use within the unit. The units shall also be permitted to import goods required for the approved activity, including capital goods, free of cost or on loan from clients.

- (c) SEZ units may procure goods required by it without payment of duty, from bonded warehouses in the DTA set up under the Policy and/or under Section 65 of the Customs Act and from International Exhibitions held in India.
- (d) SEZ units, may import/procure from DTA, without payment of duty, all types of goods for creating a central facility for use by units in SEZ. The Central facility for software development can also be accessed by units in the DTA for export of software.
- (e) Gem & Jewellery units may also source gold/silver/platinum through the nominated agencies.
- (f) SEZ units may import/procure goods and services from DTA without payment of duty for setting up, operation and maintenance of units in the Zone.

Leasing of Capital Goods

7.3

SEZ unit may, on the basis of a firm contract between the parties, source the capital goods from a domestic/foreign leasing company. In such a case the SEZ unit and the domestic/foreign leasing company shall jointly file the documents to enable import/procurement of the capital goods without payment of duty.

Net Foreign Exchange Earning (NFE)

7.4

SEZ unit shall be a positive Net Foreign exchange Earner. Net Foreign Exchange Earning (NFE) shall be calculated cumulatively for a period of five years from the commencement of production according to the formula given in Appendix - 14-II of the Handbook (Vol-I)

Monitoring of performance

7.5

- (a) The performance of SEZ units shall be monitored by the Unit Approval Committee.
- (b) The performance of SEZ units shall be monitored as per the guidelines given in Appendix 14-II of Handbook (Vol-I).

Legal Undertaking

7.6

The unit shall execute a legal undertaking with the Development Commissioner concerned and in the event of failure to achieve positive foreign exchange earning it shall be liable to penalty in terms of the legal undertaking or under any other law for the time being in force.

Approvals and Applications

7.7

- (a) Applications for setting up a unit in SEZ other than proposals for setting up of unit in the services sector

(except software and IT enabled services, trading or any other service activity as may be delegated by the BOA), shall be approved or rejected by the Units Approval Committee within 15 days as per procedure indicated in Annexure to Appendix 14-II of Handbook (Vol-I). In other cases approval may be granted by the Board of Approval.

- (b) Proposals for setting up units in SEZ requiring Industrial Licence may be granted approval by the Development Commissioner after clearance of the proposal by the SEZ Board of Approval and Department of Industrial Policy and Promotion within 45 days on merits.

***DTA Sales and
Supplies***

7.8

- (a) SEZ unit may sell goods, including by-products, and services in DTA in accordance with the import policy in force, on payment of applicable duty..
- (b) DTA sale by service/trading unit shall be subject to achievement of positive NFE cumulatively. Similarly for units undertaking manufacturing and services/trading activities against a single LOP, DTA sale shall be subject to achievement of NFE cumulatively.
- (c) The following supplies effected in DTA by SEZ units will be counted for the purpose of fulfilment of positive NFE:
- (i) Supplies effected in DTA in terms of Chapter 8 of the Policy.
 - (ii) Supplies made to bonded warehouses set up under the Policy and/or under Section 65 of the Customs Act.
 - (iii) Supplies to other EOU/SEZ/EHTP/STP units provided that such goods are permissible for procurement by units.
 - (iv) Supplies against special entitlement of duty free import of goods.
 - (v) Supplies of goods and services to such organizations which are entitled for duty free import of such items in terms of general exemption notification issued by the Ministry of Finance.
 - (vi) Supply of services (by services units) relating to exports paid for in free foreign exchange or for such services rendered in Indian Rupees which are

otherwise considered as having been paid for in free foreign exchange by RBI.

(vii) Supplies of Information Technology Agreement (ITA-1) items and notified zero duty telecom/electronic items indicated in the Appendix 14-II of Handbook.

***Entitlement for
Supplies from
the DTA***

7.9

Supplies from DTA to SEZ shall be entitled for the following:

(a) DTA supplier shall be entitled for:

(i) Drawback

Or

DEPB in lieu of Drawback

(ii) Discharge of Export performance, if any, on the supplier.

(b) SEZ units shall be entitled for:-

(i) Exemption from Central Sales Tax;

(ii) Exemption from payment of Central Excise Duty on all goods eligible for procurement by the unit.

(iii) Reimbursement of Central Excise Duty, paid on bulk tea procured from the licenced auction centres by the Development Commissioner of concerned zone as long as levy on bulk tea in this regard is in force.

(iv) Reimbursement of Duty paid on fuels or any other goods procured from DTA as per the rate of drawback notified by the Directorate General of Foreign Trade from the date of such notification.

(c) Supplier of precious and semi-precious stones, synthetic stones and processed pearls from Domestic Tariff Area to the units situated in SEZ shall be eligible for grant of Replenishment Licenses at the rates and for the items mentioned in the Handbook (Vol. I).

(d) The entitlements under paragraphs (a) and (b) (ii) above shall be available provided the goods supplied are manufactured in India.

***Export Through
Status Holder***

7.10

SEZ unit may also export goods manufactured/software developed by it through a merchant exporter/status holder recognized under this Policy or any other EOU/SEZ/EHTP/STP unit.

Inter-unit Transfer 7.11

- (a) SEZ units may transfer manufactured goods, including partly processed/semi-finished goods and services from one SEZ unit to another SEZ/EOU/EHTP/STP unit.
- (b) Goods imported/procured by a SEZ unit may be transferred or given on loan to another unit within the same SEZ which shall be duly accounted for, but not counted towards discharge of export performance.
- (c) Capital goods imported/procured may be transferred or given on loan to another SEZ/EOU/EHTP/STP unit with prior permission of the Development Commissioner and Customs authorities concerned.
- (d) Transfer of goods in terms of sub-paras (a) and (b) above within the same SEZ shall not require any permission but the units shall maintain proper accounts of the transaction.

Other Entitlements

Other entitlements of SEZ units are indicated in the Appendix 14-II of the Handbook (Vol-1).

Sub-Contracting 7.12

- (a) SEZ unit, may subcontract a part of their production or production process through units in the DTA or through other SEZ/EOU/EHTP/STP, with the annual permission of Customs authorities. Subcontracting of part of production process may also be permitted abroad with the approval of the Development Commissioner.
- (b) Sub-contracting by SEZ gems and jewellery units through other SEZ units or EOUs or units in DTA shall be subject to following conditions
 - i) Goods, finished or semifinished, including studded jewellery, taken outside the zone for sub-contracting shall be brought back to the unit within 30 days. No cut and polished diamonds, precious and semi-precious stones (except precious and semi precious stone having zero duty) shall be allowed to be taken outside the zone for sub-contracting.
 - ii) Receive plain gold/silver/platinum jewellery from DTA in exchange of equivalent quantity of gold/silver/platinum, as the case may be, contained in the said jewellery.
 - iii) SEZ units shall be eligible for wastage as applicable for sub-contracting and against exchange.
 - iv) The DTA unit undertaking job work or supplying jewellery against exchange of gold/silver/platinum shall not be entitled to export benefits.

- (c) All units, including gem and jewellery, may sub-contract part of the production or production process through other units in the same SEZ without permission of Customs authorities subject to records being maintained by both the supplying and receiving units.
- (d) SEZ units other than gems and jewellery units may be allowed to undertake job-work for export, on behalf of DTA exporter, provided the finished goods are exported directly from SEZ units. For such exports, the DTA units will be entitled for refund of duty paid on the inputs by way of Brand Rate of duty drawback.
- (e) Scrap/waste/remnants generated through job work may either be cleared from the job worker's premises on payment of applicable duty or returned to the unit.
- (f) SEZ units engaged in production/processing of agriculture/horticulture products, may on the basis of annual permission from the Customs authorities take out inputs and equipments to the DTA farm subject to the procedure indicated in Appendix 14-II of the Handbook (Vol-I)

Exit from SEZ Scheme 7.13

- (a) SEZ unit may opt out of the scheme with the approval of the Development Commissioner. Such exit from the scheme shall be subject to payment of applicable Customs and Excise duties on the imported and indigenous capital goods, raw materials etc. and finished goods in stock. In case the unit has not achieved positive NFE, the exit shall be subject to penalty, that may be imposed by the adjudicating authority under Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992.
- (b) SEZ unit may also be permitted by the Development Commissioner, as one time option, to exit from SEZ scheme on payment of duty on capital goods under the prevailing EPCG Scheme, subject to the unit satisfying the eligibility criteria of that Scheme and standard conditions for exit indicated in Appendix 14-II of Handbook (Vol-I).

Export through Exhibitions/Export Promotion Tours/Export through show rooms abroad/Duty Free Shops

7.14

- SEZ, units may :
- (i) Export goods for holding/participating in exhibitions abroad with the permission of Development Commissioner.
 - (ii) Personal carriage of gold/silver/platinum jewellery, precious, semi-precious stones, beads and articles.
 - (iii) Export of jewellery is also permitted for display/sale in the permitted shops set up abroad.

- (iv) Display/sell in the permitted shops set up abroad or in the show rooms of their distributors/agents.
- (v) Set up show rooms/retail outlets at the International Airports.

**Personal Carriage of
Export/Import parcel** 7.15

Import/export through personal carriage of gem and jewellery items may be under-taken as per the procedure prescribed by Customs. Import/export through personal carriage for units, other than gem and jewellery unit, shall be allowed provided the goods are not in commercial quantity

**Export/Import by
post/courier** 7.16

Goods including free samples, may be exported/imported by airfreight or through Foreign Post Office or through courier, subject to the procedure prescribed by Customs.

**Disposal of Rejects/
Scrap/Waste/
Remnants** 7.17

Rejects/scrap/waste/remnants arising out of production process or in connection therewith may be sold in the DTA on payment of applicable duty. No duty shall be payable in case scrap/waste/remnants/rejects are destroyed within the Zone after intimation to the Custom authorities or destroyed outside the SEZ with the permission of Custom authorities. Destruction as stated above shall not apply to gold, silver, platinum, diamond, precious and semi precious stones.

**Replacement/Repair
of Goods** 7.18

- (a) The general provisions of Policy relating to export of replacement/repared goods shall apply equally to SEZ units, save that, cases not covered by these provisions shall be considered on merits by the Development Commissioner.
- (b) The goods sold in the DTA and found to be defective may be brought back for repair/replacement under intimation to Development Commissioner.
- (c) Goods or parts thereof, including gem stones and precious metal components for jewellery making, on being imported/indigenously procured and found defective or otherwise unfit for use or which have been damaged or become defective after import/procurement may be returned and replacement obtained or destroyed. In the event of replacement, the goods may be brought back from the foreign suppliers or their authorised agents in India or the indigenous suppliers. Destruction shall however not apply to gem stones and precious metals.
- (d) Goods may be transferred to DTA/abroad for repair/replacement, testing or calibration, quality testing and R & D purpose under intimation to Customs authorities and subject to maintenance of records.

Management of SEZ	7.19	<p>(a) SEZ will be under the administrative control of the Development Commissioner.</p> <p>(b) All activities of SEZ units within the Zone, unless otherwise specified, including export and re-import of goods shall be through self certification procedure.</p>
Setting up of SEZ in Private/Joint/State Sector	7.20	A SEZ may be set up in the public, private, joint sector or by state Government as per details indicated in Appendix 14-II of the Handbook(Vol-I).
Samples	7.21	<p>SEZ units may, on the basis of records maintained by them, and on prior intimation to Customs authorities:</p> <p>(i) supply or sell samples in the DTA for display/market promotion on payment of applicable duties;</p> <p>(ii) Remove samples without payment of duty, on furnishing a suitable undertaking to Customs authorities for bringing the goods back within a stipulated period;</p> <p>(iii) Export free samples, without any limit, including samples made in wax moulds, silver mould and rubber moulds through all permissible mode of export including through couriers agencies/post.</p>
Sale of Un-utilised Material/Obsolete goods	7.22	<p>(a) In case an SEZ unit is unable, for valid reasons, to utilize the goods, including capital goods and spares, it may dispose them in the DTA in accordance with the import policy in force and on payment of applicable duties or export them.</p> <p>(b) Capital goods and spares that have become obsolete/surplus may either be exported or disposed of in the DTA on payment of applicable duties. The benefit of depreciation, as applicable, will be available in case of disposal in DTA.</p> <p>(c) No duty shall be payable in case capital goods, raw material, consumables, spares, goods manufactured, processed or packaged and scrap/waste/remnants/rejects are destroyed within the Zone after intimation to the Custom authorities or destroyed outside the Zone with the permission of Custom authorities. However destruction shall not apply to precious and semi precious and precious metals</p> <p>(d) SEZ unit may be allowed by Customs authorities concerned to donate imported/indigenously procured computer and computer peripherals without payment of duty, two years after their import/procurement and use by the units, to recognized non-commercial educational</p>

institutions, registered charitable hospitals etc as per the details given in Appendix 14-II in Handbook (Vol-I).

Entitlement for SEZ Developer 7.23

For development, operation and maintenance of infrastructure facilities in SEZs, the developer shall be eligible for the following entitlements.

- (a) Income tax exemption as per 80 IA of the Income Tax Act.
- (b) Import/procure goods without payment of Customs/Excise duty.
- (c) Exemption from Service tax.
- (d) Exemption from CST.

CHAPTER-7A

FREE TRADE & WAREHOUSING ZONES

Objective

- 7A.1 The objective is to create trade-related infrastructure to facilitate the import and export of goods and services with freedom to carry out trade transactions in free currency. The scheme envisages creation of world-class infrastructure for warehousing of various products, state-of-the-art equipment, transportation and handling facilities, commercial office-space, water, power, communications and connectivity, with one-stop clearance of import and export formality, to support the integrated Zones as 'international trading hubs'. These Zones would be established in areas proximate to seaports, airports or dry ports so as to offer easy access by rail and road.

Status

- 7A.2 The Free Trade & Warehousing Zones (FTWZ) shall be a special category of Special Economic Zones with a focus on trading and warehousing.

Establishment of Zone

- 7A.3
- (i) Proposals for setting up of FTWZs may be made by public sector undertakings or public limited companies or by joint ventures in technical collaboration with experienced infrastructure developers. The proposals shall be considered by the Board of Approval in the Department of Commerce. On approval, the developer will be issued a letter of permission for the development, operation and maintenance of such FTWZ.
 - (ii) Foreign Direct Investment would be permitted up to 100% in the development and establishment of the zones and their infrastructural facilities.
 - (iii) The proposal must entail a minimum outlay of Rs.100 crores for the creation and development of the infrastructure facilities, with a minimum built up area of five lakh sq.mts.
 - (iv) The developer shall be permitted to import duty free such building materials and equipment as may be required for the development and infrastructure of the zone. Such equipment and materials as are sourced from the DTA shall be considered as physical exports for the DTA suppliers.
 - (v) Once it has developed the FTWZ, the developer shall also be permitted to sale/lease/rent out warehouses/workshops/ office-space and other facilities in the FTWZ to traders/ exporters.

Maintenance of Zone

- 7A.4 The developer shall itself or through suitable special purpose arrangements, ensure a reliable mechanism for the proper

maintenance of the common facilities and security of the FTWZ.

Functioning

7A.5

- (i) The scheme envisages duty free import of all goods (except prohibited items, arms and ammunitions, hazardous wastes and SCOMET items) for ware housing. As far as bond towards customs duty on import is concerned, the units would be subject to similar provisions as are applicable to units in SEZs.
- (ii) Such goods shall be permitted to be re-sold/re-invoiced or re-exported. Re-export shall be permitted without any restrictions. However export of SCOMET items shall not be permitted. However export of SCOMET items shall not be permitted except with the permission of Inter-Ministerial Committee.
- (iii) These goods shall also be permitted to be sold in the DTA on payment of customs duties as applicable on the date of such sale. Payment of duty will become due only when goods are sold/delivered to DTA and no interest will be charged as in the case of bonded warehouses.
- (iv) Packing or re-packing without processing, and labeling as per customer or marketing requirements could be undertaken within the FTWZ.
- (v) The maximum period that goods shall be permitted to be warehoused within the FTWZ will be two years, after which they shall necessarily have to be re-exported or sold in the DTA. On expiry of the two year period, customs duties as applicable would automatically become due unless the goods are re-exported within such grace period, not exceeding three months, as may be permitted.

Entitlement of units

7A.6

- (i) Income Tax exemption as per 80 IA of the Income Tax Act.
- (ii) Exemption from Service Tax.
- (iii) Free foreign exchange currency transactions would be permitted.
- (iv) Other benefits mutatis mutandi as applicable to units in SEZs.

NFE criteria

7A.7

Units in FTWZs shall be net foreign exchange earners. Net foreign exchange earning shall be calculated cumulatively for ever block of five years from the commencement of warehousing and/or trading operations as per formula applicable for SEZ units.

CHAPTER-8**DEEMED EXPORTS**

- | | | |
|------------------------------------|-----|---|
| <i>Deemed Exports</i> | 8.1 | "Deemed Exports" refers to those transactions in which the goods supplied do not leave the country and the payment for such supplies is received either in Indian rupees or in free foreign exchange. |
| <i>Categories of Supply</i> | 8.2 | <p>The following categories of supply of goods by the main/sub-contractors shall be regarded as "Deemed Exports" under this Policy, provided the goods are manufactured in India:</p> <ul style="list-style-type: none">(a) Supply of goods against Advance Licence/Advance Licence for annual requirement/DFRC under the Duty Exemption /Remission Scheme;(b) Supply of goods to Export Oriented Units (EOUs) or Software Technology Parks (STPs) or Electronic Hardware Technology Parks (EHTPs) or Bio Technology Parks (BTP);(c) Supply of capital goods to holders of licences under the Export Promotion Capital Goods (EPCG) scheme;(d) Supply of goods to projects financed by multilateral or bilateral agencies/funds as notified by the Department of Economic Affairs, Ministry of Finance under International Competitive Bidding in accordance with the procedures of those agencies/funds, where the legal agreements provide for tender evaluation without including the customs duty;(e) Supply of capital goods, including in unassembled/disassembled condition as well as plants, machinery, accessories, tools, dies and such goods which are used for installation purposes till the stage of commercial production and spares to the extent of 10% of the FOR value to fertiliser plants.(f) Supply of goods to any project or purpose in respect of which the Ministry of Finance, by a notification, permits the import of such goods at zero customs duty.(g) Supply of goods to the power projects and refineries not covered in (f) above.(h) Supply of marine freight containers by 100% EOU (Domestic freight containers—manufacturers) provided the |

said containers are exported out of India within 6 months or such further period as permitted by the Customs; and

- (i) Supply to projects funded by UN agencies.
- (j) Supply of goods to nuclear power projects through competitive bidding as opposed to International Competitive Bidding.

The benefits of deemed exports shall be available under paragraph (d), (e), (f) and (g) only if the supply is made under the procedure of International Competitive Bidding (ICB).

Benefits for Deemed Exports 8.3

Deemed exports shall be eligible for any/all of the following benefits in respect of manufacture and supply of goods qualifying as deemed exports subject to the terms and conditions as given in Handbook (Vol.1):-

- (a) Advance Licence for intermediate supply/deemed export/DFRC/DFRC for intermediate supplies.
- (b) Deemed Export Drawback.
- (c) Exemption from terminal excise duty where supplies are made against International Competitive Bidding. In other cases, refund of terminal excise duty will be given.

CHAPTER-9

DEFINITIONS

- 9.1 For the purpose of this Policy, unless the context otherwise requires, the following words and expressions shall have the following meanings attached to them.
- 9.2 “Accessory” or “Attachment” means a part, sub-assembly or assembly that contributes to the efficiency or effectiveness of a piece of equipment without changing its basic functions.
- 9.3 “Act” means the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992).
- 9.4 “Actual User” means an actual user who may be either industrial or non-industrial.
- 9.5 “Actual User (Industrial)” means a person who utilises the imported goods for manufacturing in his own industrial unit or manufacturing for his own use in another unit including a jobbing unit.
- 9.6 “Actual User (Non-Industrial)” means a person who utilises the imported goods for his own use in
- (i) any commercial establishment carrying on any business, trade or profession; or
 - (ii) any laboratory, Scientific or Research and Development (R&D) institution, university or other educational institution or hospital; or
 - (iii) any service industry.
- 9.7 “AEZ” means Agricultural Export Zones notified by DGFT in Appendix 15 of Handbook (Vol . 1).
- 9.8 “ALC” means the Advance Licensing Committee in the Directorate General of Foreign Trade for recommending grant of licences under Duty Exemption Scheme and for recommending Input Output norms and value addition norms to be notified by Director General of Foreign Trade.
- 9.9 “Applicant” means the person on whose behalf the application is made and shall, wherever the context so requires, include the person signing the application.
- 9.10 “BOA” means the Board of Approval as notified by the Department of Commerce.

- 9.11 “BTP” means Biotechnology Park as notified by Director General of Foreign Trade on the recommendation of the Department of Biotechnology.
- 9.12 “Capital Goods” means any plant, machinery, equipment or accessories required for manufacture or production, either directly or indirectly, of goods or for rendering services, including those required for replacement, modernisation, technological upgradation or expansion. Capital goods also include packaging machinery and equipment, refractories for initial lining, refrigeration equipment, power generating sets, machine tools, catalysts for initial charge, equipment and instruments for testing, research and development, quality and pollution control. Capital goods may be for use in manufacturing, mining, agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture and viticulture as well as for use in the services sector.
- 9.13 “Competent Authority” means an authority competent to exercise any power or to discharge any duty or function under the Act or the Rules and Orders made thereunder or under this Policy.
- 9.14 “Component” means one of the parts of a sub-assembly or assembly of which a manufactured product is made up and into which it may be resolved. A component includes an accessory or attachment to the component.
- 9.15 “Consumables” means any item, which participates in or is required for a manufacturing process, but does not necessarily form part of the end-product. Items, which are substantially or totally consumed during a manufacturing process will be deemed to be consumables.
- 9.16 “Consumer Goods” means any consumption goods, which can directly satisfy human needs without further processing and includes consumer durables and accessories thereof.
- 9.17 “Counter Trade” means any arrangement under which exports/ imports from/to India are balanced either by direct imports/ exports from the importing/exporting country or through a third country under a Trade Agreement or otherwise. Exports/ Imports under Counter Trade may be carried out through Escrow Account, Buy Back arrangements, Barter trade or any similar arrangement. The balancing of exports and imports could wholly or partly be in cash, goods and/or services.
- 9.18 “Developer” means a person or body of persons, company.

firm and such other private or government undertaking, who develops, builds, designs, organises, promotes, finances, operates, maintain or manages a part or whole of the infrastructure and other facilities in the Special Economic Zones as approved by the Central Government.

9.19 “Development Commissioner” means the Development Commissioner of the Special Economic Zone.

9.20 “DFRC” means Duty Free Replenishment Certificate.

9.21 “Domestic Tariff Area” means area within India which is outside the Special Economic Zones and EOU/ EHTP/ STP/ BTP.

9.22 “Drawback, “ in relation to any goods manufactured in India and exported, means the rebate of duty chargeable on any imported material or excisable material used in the manufacture of such goods in India. The goods include imported spares, if supplied with capital goods manufactured in India.

9.23 “EHTP “ means Electronic Hardware Technology Park.

9.24 “EOU” means Export Oriented Unit for which an LOP has been issued by the Development Commissioner.

9.25 “Excisable goods” means any goods produced or manufactured in India and subject to a duty of excise under the Central Excise and Salt Act 1944 (1 of 1944).

9.26 “Exporter” means a person who exports or intends to export and holds an Importer-Exporter Code number unless otherwise specifically exempted.

9.27 “Export Obligation” means the obligation to export the product or products covered by the licence or permission in terms of quantity, value or both, as may be prescribed or specified by the licensing or competent authority.

9.28 “Group Company” means two or more enterprises which, directly or indirectly, are in a position to:

- (i) exercise twenty-six per cent. or more of the voting rights in the other enterprise; or
- (ii) appoint more than fifty percent, of the members of the board of directors in the other enterprise; or

For the group companies to claim benefits or have their exports counted for benefits to be claimed by another member of the

- group, the group company should have been in existence atleast 2 years prior to the date of application under any of the export promotion schemes notified in the Policy.
- 9.29 “Handbook (Vol. 1)” means the Handbook of Procedures (Vol.1) and “Handbook (Vol. 2)” means Handbook of Procedures (Vol. 2) published under the provisions of paragraph 2.4 of the Policy.
- 9.30 “Importer” means a person who imports or intends to import and holds an Importer-Exporter Code number unless otherwise specifically exempted.
- 9.31 “Infrastructure facilities” means industrial, commercial and social infrastructure or any other facility for the development of the Special Economic Zone as notified.
- 9.32 “ITC(HS)” means ITC(HS) Classifications of Export and Import Items Book.
- 9.33 “Jobbing” means processing or working upon of raw materials or semi-finished goods supplied to the job worker so as to complete a part of the process resulting in the manufacture or finishing of an article or any operation which is essential for the aforesaid process.
- 9.34 “Licensing Authority” means the authority competent to grant a licence under the Act/Order.
- 9.35 “Licensing Year” means the period beginning on the 1st April of a year and ending on the 31st March of the following year.
- 9.36 “Managed Hotel” means hotels managed by a three star or above hotel/hotel chain under an operating management contract for a duration of atleast three years between the operating hotel/hotel chain and the hotel being managed. The management contract must necessarily cover the entire gamut of operations/management of the managed hotel.
- 9.37 “Manufacture” means to make, produce, fabricate, assemble, process or bring into existence, by hand or by machine, a new product having a distinctive name, character or use and shall include processes such as refrigeration, re-packing, polishing, labelling. Re-conditioning repair, remaking, refurbishing, testing, calibration, re-engineering. Manufacture, for the purpose of this Policy, shall also include agriculture, aquaculture, animal husbandry, floriculture, horticulture, pisciculture, poultry, sericulture, viticulture and mining.

- 9.38 “Manufacturer Exporter” means a person who export goods manufactured by him or intends to export such goods.
- 9.39 “MAI” means Market Access Initiative Scheme notified by the Department of Commerce
- 9.40 “Merchant Exporter” means a person engaged in trading activity and exporting or intending to export goods.
- 9.41 “NFEP” means Net Foreign Exchange Earning as a percentage of exports.
- 9.42 “Notification” means a notification published in the Official Gazette.
- 9.43 “Order” means an Order made by the Central Government under the Act.
- 9.44 “Part” means an element of a sub-assembly or assembly not normally useful by itself and not amenable to further disassembly for maintenance purposes. A part may be a component, spare or an accessory.
- 9.45 “Person” includes an individual, firm, society, company, corporation or any other legal person.
- 9.46 “Policy” means the Foreign Trade Policy 2004-2009 as amended from time to time.
- 9.47 “Prescribed” means prescribed under the Foreign Trade (Development and Regulation) Act, 1992 (No. 22 of 1992) or the Rules or Orders made thereunder or under this Policy.
- 9.48 “Public Notice” means a notice published under the provisions of paragraph 2.4 of the Policy.
- 9.49 “Raw material” means:
- (i) basic materials which are needed for the manufacture of goods, but which are still in a raw, natural, unrefined or unmanufactured state; and
 - (ii) for a manufacturer, any materials or goods which are required for his manufacturing process, whether they have actually been previously manufactured or are processed or are still in a raw or natural state.
- 9.50 “Registration-Cum-Membership Certificate” (RCMC) means the certificate of registration and membership granted by an Export Promotion Council/Commodity Board/ Development

- Authority or other competent authority as prescribed in the Policy or Handbook (Vol. 1).
- 9.51 “Rules” means Rules made by the Central Government under Section 19 of the Act.
- 9.52 “Services” include all the tradable services covered under General Agreement on Trade in Services and earning free foreign exchange.
- 9.53 “Service Provider” means a person providing
- (i) Supply of a ‘service’ from India to any other country;
 - (ii) Supply of a ‘service’ from India to the service consumer of any other country in India; and
 - (iii) Supply of a ‘service’ from India through commercial or physical presence in the territory of any other country.
 - (iv) Supply of a ‘service’ in India relating to exports paid in free foreign exchange or in Indian Rupees which are otherwise considered as having being paid for in free foreign exchange by RBI.
- 9.54 “SEZ” means Special Economic Zone notified by the Ministry of Commerce & Industry, Department of Commerce.
- 9.55 “Ships” mean all types of vessels used for sea borne trade or coastal trade and shall include second hand vessels.
- 9.56 “SION” means Standard Input Output Norms notified by DGFT in the Handbook (Vol. 2), 2002-07/approved by Board of Approval.
- 9.57 “Spares” means a part or a sub-assembly or assembly for substitution, that is ready to replace an identical or similar part or sub-assembly or assembly. Spares include a component or an accessory.
- 9.58 “Specified” means specified by or under the provisions of this Policy.
- 9.59 “Status holder” means an exporter recognized as One to Five Star Export House by DGFT/ Development Commissioner.
- 9.60 “STP” means Software Technology Park
- 9.61 “Supporting Manufacturer” means any person who manufactures any product or part/ accessories/ components of

that product. The name of the supporting manufacturer as well as the exporter must be endorsed on the export document(s).

- 9.62 “Third-party exports” means exports made by an exporter or manufacturer on behalf of another exporter(s). In such cases, export documents such as shipping bills shall indicate the name of both the manufacturing exporter/manufacturer and third party exporter(s). The BRC, GR declaration, export order and the invoice should be in the name of the third party exporter.
- 9.63 “Transaction Value” as defined in the Customs Valuation Rules of the Department of Revenue.
- 9.64 “Unit Approval Committee” means the Committee notified for Special Economic Zones to consider proposals on matters relating to Special Economic Zone unit under its jurisdiction.
- 9.65 “Wild Animal” means any wild animal as defined in Section 2(36) of the Wildlife (Protection) Act, 1972.